संपादकीय

अमृतवर्षा संपादकीय

काली इमरजेंसी और गुजरात व बिहार

12 जून, 1975 को जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्व. जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली चुनाव क्षेत्र से 1971 में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा लड़ा गया चुनाव अवैध तरीके अपनाये जाने के कारण रद्द किया जाता है तो उसी दिन गुजरात से भी यह खबर आई कि राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई है और विपक्षी गठबन्धन लोकतान्त्रिक मोर्चे को बहुमत प्राप्त हुआ है। गुजरात में इस मोर्चे के नेता श्री बाबू भाई पटेल थे। उस समय देश भर में लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल मिलकर इन्दिरा गांधी के शासन के खिलाफ आन्दोलन चला रहे थे, मगर 13 दिन बाद 25 जून को इन्दिरा जी ने पूरे देश पर आन्तरिक इमरजेंसी लगा दी और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। इसी दिन 25 जून को दिल्ली के प्रैस एरिया बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली गुल कर दी गई और रात्रि को घोषणा की गई कि अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई है। उस समय मैं इसी क्षेत्र के सबसे बड़े प्रकाशन संस्थान में काम करता था। अगले दिन सभी प्रमुख अंग्रेजी अखबारों ने अपने सम्पादकीय कालमों को खाली छोड़ा। इससे सन्देश चला गया कि सम्पादक की कलम को बन्दी बना लिया गया है। एक तरफ जहां दिल्ली में यह सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अहमदाबाद में श्री बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में लोकतान्त्रिक मोर्चे की सरकार बन चुकी थी। इमरजेंसी लगने के थोड़े समय बाद ही कांग्रेस ने इस सरकार को भी गिरा दिया। असल में गुजरात वह स्थल था जहां से 1974 के जन आन्दोलन की चिंगारी फूटी थी। सबसे पहले यहां छात्र आन्दोलन नागरिक सुविधाओं को लेकर शुरू हुआ और यह बिहार में फैला मगर बिहार में पहुंच कर यह शोले में तब्दील हो गया। बिहार के आन्दोलन में छात्रों का साथ देने जब समाजवादी नेता श्री जय प्रकाश नारायण आ गये तो राज्य के साहित्यकार भी इसमें कूद गये। प्रख्यात साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणू भी पटना के गांधी मैदान में जेपी आन्दोलन में शामिल हो गये थे। गांधी मैदान में तब बिहार पुलिस ने लाठियों के बल पर आन्दोलनकारियों को दबाना चाहा था। लाठी खाने वालों में श्री रेणू भी थे। जेपी पहले से ही मांग कर रहे थे कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री अब्दुल गफूर को पद से हटाया जाये क्योंकि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और अत्याचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। इस प्रकार आन्दोलन का केन्द्र धीरे-धीरे गुजरात की जगह बिहार होता चला गया। बिहार में लगभग सभी विपक्षी दल जेपी के नेतृत्व के साये में आन्दोलन चला रहे थे। इनमें भारतीय जनसंघ के ठाकुर प्रसाद सिंह से लेकर समाजवादी नेता रामानन्द तिवारी और कपूरी ठाकुर तक शामिल थे। जेपी आन्दोलन से जुड़ने में स्व. ठाकुर प्रसाद सिंह ने बहुत जल्दी दिखाई थी और अपने समाजवादी मित्रों के साथ कदम ताल करने में कोताही नहीं बरती थी। दर असल बिहार में स्व. ठाकुर प्रसाद सिंह की कद-काठी का कोई दूसरा भाजपा नेता आज तक पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने जनसंघ की जड़ें जनता के बीच फैलाई थीं। एक तरफ जब यह आन्दोलन चल रहा था और इसकी धमक राजधानी दिल्ली में भी सुनाई पड़ने लगी थी तो देश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों ने जेपी के नेतृत्व में स्वयं को समाहित किया मगर इस सबके चलते ही 25 जून, 1975 की तारीख आ गई और सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, मगर इसके बाद जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकताओं को भी पकड़झपकड़ कर जेलों में डाला गया। ऐसे समय में देश के वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतन्त्र की अलख जगाने के उद्देश्य से वेष बदल कर काम किया और एक सिख युवक के रूप में वह जगह-जगह छिपते झछिपाते संगठन व राष्ट्र का काम करते रहे। उस समय श्री मोदी की आयु मात्र 25 वर्ष थी। गुजरात के और भी संगठन के कार्यकताओं ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी। 21 महीने बाद जब मार्च 77 में इमरजेंसी हटने की अधिकारिक घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा की गई तो लगभग सभी कार्यकताओं को चंगेजी शासन से निजात मिली। अब इमरजेंसी के बाद चुनाव होने थे। इन्दिरा जी को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी कांग्रेस इन लोकसभा चुनावों में विजयी हो जायेगी, क्योंकि विपक्षी नेताओं के जेल चले जाने के बाद देश के भीतर उनके समर्थन में किसी प्रकार का आन्दोलन आदि नहीं हुआ था, मगर चुनावों की घोषणा होने के कुछ समय बाद देश के दलित कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने सरकार और पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा व हरियाणा के नेता भजनलाल ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे आम जनता में विपक्ष के पक्ष में तूफान जैसा खड़ा हो गया, हालांकि विपक्ष के खेमे में तब स्व. अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चौधरी चरण सिंह व राजनारायण और जार्ज फर्नांडीज जैसे दिग्गज थे और आचार्य कृपलानी जैसे महारथी जेपी के साथ मिल कर इन सभी नेताओं का मार्ग दर्शन कर रहे थे मगर बाबू जगजीवन राम के कांग्रेस छोड़ने की वजह से जमीनी चुनावी हवा पूरी तरह बदल गई और स्वतन्त्र भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार दलितों व मुस्लिमों ने कांग्रेस के स्थान पर विपक्ष को चुनाव में अपना मत दिया। विपक्षी दलों ने 1977 के चुनावों में कांग्रेस को हराने के लिए अपने झ अपने अस्तित्व तक को समाप्त कर डाला और मिल कर जनता पार्टी बनाई।

संस्थापक संपादकः स्व. पारसनाथ तिवारी
स्वत्वाधिकारी एवं प्रकाशक रीता तिवारी,मुद्रक कुंज बिहारी के द्वारा आर डी प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि., प्लॉट नं- सी 16-17 पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना-800013 से मुद्रित व B-14 जगत भवानी अपार्टमेंट, एसपी सिन्हा लेन, बोरिंग कैनाल रोड, पटना-1 से प्रकाशित
संपादक-बन बिहारी
दूरभाष - 9905463571, 8757425017, धनबाद कार्यालयः मास्टर पाड़ा जे.सी. मल्लिक रोड, हीरापुर, धनबाद दूरभाष - 2204991, दिल्ली कार्यालयः बी-49, जैन मंदिर गली, शकरपुर मेन मार्केट, दिल्ली-110092, फोन नं.- 011-22055208, आर.एन.आई नं. 44420/87
ईमेलः amritvarshanews2015@gmail.com

संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते राहुल

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि 'भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा (ब्रोकेन) हुआ था, अब यह लड़ रहा है।' उनका यह कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर ही सवाल उठाता है।

डॉ. आशीष वशिष्ठ

नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव में करारी पराजय के बाद कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने चीखना शुरू कर दिया था- 'ईवीएम में भूत है, जो भाजपा को ही वोट भेजता है। अप्रैल 2025 को विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान बोस्टन में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए, चुनाव पर बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग 'कंप्रोमाइज्ड' है। ताजा संदर्भ राहुल गांधी ने मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से 7 जून को एक लेख लिखा। ये कई अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और भाजपा ने सुनियोजित तरीके से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठया हो या फिर उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया हो। वो आदतन अक्सर ऐसा करते रहते हैं । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करता है जिसे संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा और सभी निर्वाचित निकायों के चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने का दायित्व दिया गया है। यह संस्था न तो कार्यपालिका के अधीन है और न ही किसी राजनीतिक दबाव में काम करती है। भारतीय निर्वाचन आयोग केवल एक प्रशासनिक निकाय नहीं बल्कि विवाद-निराकरण और मतदाता-विश्वास निर्माण की भी जिम्मेदारी निभाता है। आयोग मतदान प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने के लिए कई स्तर पर काम करता है। राहुल गांधी सस्ती लोकप्रियता पाने के कुछ भी बयान देते हैं, पर तर्क और तथ्य की कमी होती है। इससे समाज में भ्रम फैलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। विदेशी धरती पर जाकर वो देश का अपमान, मोदी सरकार की आलोचना और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई अवसर चूकते नहीं हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि 'भारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा (ब्रोकेन) हुआ था, अब यह लड़ रहा है।' उनका यह कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर ही सवाल उठाता है। खासकर तब जब भारत में लगातार चुनाव होते रहे हैं और सरकारें बदलती रहीं हैं। बीते 10-11 वर्षों में देश में कई ऐसी सरकारें बनी हैं, जिसे बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस को मौका मिला है। मतलब, अगर नतीजे राहुल और उनकी पार्टी के लिए अच्छे रहें तो लोकतंत्र ठीक है और नहीं तो वह 'ब्रोकेन हो जाता है। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में 'फुल स्केल एसॉल्ट' हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया। मई 2022 में लंदन में 'आइडियाज फॉर इंडिया' सम्मेलन में राहुल ने कहा कि भारत की संस्थाएं 'परजीवी' बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 'डीप स्टेट' (सीबीआई, ईडी) भारत को चबा रहा है। यहां 'डीप स्टेट' का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। यहां 'डीप स्टेट' का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र से भी कर दी। 2017 में ही अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वह नहीं रहा जहां हर कोई कुछ भी कह सकता है। उन्होंने विदेश की धरती पर भारत में 'फ्री स्पीच' की स्थिति पर संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में सहनशीलता खत्म हो गई है। जबकि, हकीकत ये है कि राहुल गांधी संसद से लेकर बाहर तक जब जो जी में आता है, बयान देते रहे हैं और सरकार को छोड़ दें, शायद ही कोई संवैधानिक संस्था बची हो, जिस पर उन्होंने निशाना न साधा हो। राहुल गांधी यह क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही वे चुनाव संपन्न करवाए हैं, जिनके दम पर वह आज विपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए हैं। उनके परिवार के तीन-तीन सदस्य इन्हीं चुनावी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर संसद में मौजूद हैं। यहीं की संवैधानिक संस्थाओं ने उन्हें इतनी राहत दी हुई है कि नेशनल हेराल्ड केस में गंभीर आरोपों के बावजूद वो और उनका मां सोनिया गांधी को जमानत मिली हुई है। बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक तौर पर भले ही भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का चलन बन गया हो लेकिन भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा केवल देश के भीतर ही नहीं संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों और कई विदेशी सरकारों द्वारा भी की गई है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के 2020 के एक अध्ययन में भारत के चुनाव आयोग को ह्यवन ऑफ दी मोस्ट रोबस्ट इलेक्टोरल इंस्टीटूशन्स ग्लोबलीह्व (विश्व स्तर पर सबसे मजबूत चुनावी संस्थाओं में से एक) कहा गया। यही नहीं, 2014, 2019 और 2024 के आम चुनावों में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि तकनीक, प्रशिक्षण और जनता की भागीदारी के माध्यम से एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संभव है। बीती मई को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने से चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया था। यह बातचीत निर्वाचन आयोग की उस नई पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों को सीधे तौर पर सुनकर चुनावी प्रक्रिया को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाना है। चुनाव आयोग अब तक देशभर में कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में अब तक 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से लिखित में तथ्यों की मांग की और चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया है और अब यह दायित्व बनता है कि आरोप लगाने वाले नेता उन्हें उचित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करें। हालांकि राहुल गांधी के पूर्व रिकार्ड के हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अभिषेक सिंघवी, विवेक तन्खा जैसे बड़े वकीलों और पार्टी के अन्य नेताओं को रखा हुआ है। राहुल गांधी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। अगर एजेंसी आरोपों को जवाब देना चाहती है तो वह सुनना उनका काम नहीं है। कमोबेश ऐसा ही आचरण उनका संसद में भी है। असल में] राहुल गांधी आरोप लगाकर, सामने वाले का पक्ष या जवाब सुनने की बजाय कोई नया आरोप लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। तथ्य और तर्क से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। तथ्य यह भी है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की ओर से इसी तरह के मुद्दे उठाए गए थे। आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी को एक विस्तृत जवाब दिया था, जिसकी प्रति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी इस अध्याय का पटाक्षेप नहीं चाहते हैं। उनकी पार्टी इस मामले को जिंदा रखना चाहती है ताकि आगे के चुनाव नतीजों को सुविधा को हिसाब से संदिग्ध बनाया जा सके। चुनाव आयोग ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह किसी भी राजनीतिक दबाव, मीडिया उन्माद या सार्वजनिक सनसनी से परे केवल संविधान और मतदाता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए आज जरूरत है कि हम आलोचना करें लेकिन तथ्यों पर करें। सवाल उठाएं लेकिन समाधान के साथ और सबसे अहम कि लोकतंत्र की मजबूती, सतत निगरानी और निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनायी गयी संस्थाओं का सम्मान बनाए रखें, ताकि आमजन की लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं के प्रति आदर का भाव बना रहे।

राजनाथ का सिंहनाद

भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर खड़े होकर न केवल चीन और पाकिस्तान को जमकर धोया बल्कि आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने ऐसी हुंकार भरी जिसका संदेश पूरी दुनिया तक गया। राजनाथ सिंह की दहाड़ से चीन और पाकिस्तान तो हक्के-बक्के रह गए। चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के प्रस्तावित संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर ?रक्षामंत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख कितना कड़ा है। एससीओ में भारत और पाकिस्तान 2017 से पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस भी हैं। राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर न करके चीन और पाकिस्तान की चाल को पूरी तरह नाकाम कर दिया। आज हर भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पर गर्व कर रहा है। रक्षामंत्री ने हस्ताक्षर करने से इन्कार इसलिए किया क्योंकि उसमें पहलगाम में हुए हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया था, जबकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का उल्लेख था। भारत चाहता था कि संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद और उससे जुड़ी चिंताओं को स्पष्ट रूप में शामिल किया जाए। इस पर रक्षामंत्री ने कड़ा स्टैंड लिया। पाकिस्तान और चीन मिलकर पहलगाम में हुए नरसंहार को बयान में शामिल करने के खिलाफ थे। राजनाथ सिंह ने बैठक में पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के एडमिरल डोंग जून के सामने बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा, कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने धार्मिक पहचान के आधार पर 26 बेकसूर नागरिकों को गोली मार दी थी। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार आतंकी ढांचे को नेस्तनाबूद कर दिया। सिंह ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। हमने दिखाया कि आतंकवाद के गढ़ अब सुरक्षित नहीं हैं। चीन और पाकिस्तान संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें कठघरे में खड़ा न होना पड़े। अगर भारत इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर देता तो भारत का पक्ष कमजोर हो सकता था लेकिन राजनाथ सिंह ने बहुत ही परिपक्व और कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए सतर्क रुख अपनाया।

बाढजनित हादसों में कब तक होती रहेगी जन-धन की हानि

योगेंद्र योगी

देश में सरकारी मशीनरी की तंद्रा तब भंग होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र जागने के लिए बड़े हादसे की इंतजार में रहता है। पहले हुए हादसों से सबक सीखने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है जिम्मेदारी का अभाव। यदि यह जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसी तरह के हादसे के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हादसा होने की सूरत में उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तभी हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरूआत है। हर साल मानूसन के दौरान देश में बाढ़ जनित हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत होती है। भारी बारिश से देश को अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। जन-धन की इस हानि की किसी जिम्मेदारी तय नहीं है। आखिर कौन हर साल होने वाले ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। हादसा होने के बाद सिर्फ लकीर पीटी जाती है। ऐसे उपाय नहीं किए जाते कि हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या फिर इनकी संख्या में कमी लाई जा सके। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी बाकी है, जो इतिहास में भारत का सबसे गर्म साल रहा है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई हैं, या दोनों ही बातें हो रही हैं। 1970 से 2021 तक का डेटा दिखाता है कि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं, जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़, या सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013-2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार, ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की संख्या ज्यादा है। स्विस रे एक प्रमुख पुनबीर्मा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और अध्ययन प्रकाशित करती है। जून 2023 में, चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ के सभी बंदरगाह, जैसे कांडला और मुंद्रा बंदरगाह, बंद हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। दिसंबर 2023 में, चक्रवात मिकाउंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़े नुकसान हुए। इसके अलावा, जुलाई 2023 में उत्तरी भारत और सिक्किम में आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। स्विस रे के विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत में गर्मी का मॉनसून (जून से सितंबर) और पूर्वोत्तर मॉनसून (अक्टूबर से दिसंबर) भारी बारिश लाते हैं, जिससे गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। कुछ बड़ी घटनाओं में 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू और कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल की बाढ़ शामिल हैं। साल 2023 में उत्तर भारत की बाढ़ ने भी एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है कि नुकसान में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख है। बढ़ते तापमान से चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ी है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ता निर्माण और आबादी आपदा के समय अधिक नुकसान का कारण बनते हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं से सड़कों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। इससे ना केवल आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं बल्कि यह लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। कुदरती आपदाओं के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और फिर से निर्माण में भारी खर्च आता है। प्राकृतिक आपदाओं से भारत के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। तटीय राज्य, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल अक्सर चक्रवात और समुद्री तूफानों का सामना करते हैं।

जातिवाद और तुष्टीकरण की विकृत राजनीति का खतरनाक खेल

समाजवादी अखिलेश यादव द्वारा तथाकथित पीडीए की राजनीति को संबल देने के लिए जो बयानबाजी की जा रही है तथा उनकी पार्टी और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे प्रदेश में शांति भंग होने की आशंका बढ़ रही है।

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनैतिक सरगर्मियां तीव्र हो रही हैं। इन सरगर्मियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के प्रमुख विरोधी दल समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य विरोधी दल भी इन आगामी चुनावों में पहले की ही तरह जातिवाद और तुष्टीकरण को ही अपना प्रमुख हथियार बनाएंगे। सपा नेता अखिलेश यादव ने जिस प्रकार पीडीए के नाम पर हिन्दू समाज को जाति-जाति में विभाजित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने अर्थात वर्ष 2027 में सपा सरकार बनाने की योजना बनाई है वह वास्तव में प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का एक खतरनाक खेल है। विगत दिनों प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस खतरनाक खेल की आहट दे रही हैं। समाजवादी अखिलेश यादव द्वारा तथाकथित पीडीए की राजनीति को संबल देने के लिए जो बयानबाजी की जा रही है तथा उनकी पार्टी और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे प्रदेश में शांति भंग होने की आशंका बढ़ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव इटावा में कथावाचक के साथ घटी घटना पर आक्रामक होकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं वहीं नैमिष में एक अन्य कथावाचक के साथ घटीअप्रिय घटना पर मौन हैं। यह तो अच्छा हुआ कि पुलिस प्रशासन ने इटावा के कथावाचक के साथ मारपीट की घटना से सम्बंधित चार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की निष्पक्ष जांच आरंभ हो गई है। इटावा की घटना को लेकर अनावश्यक रूप से ब्राह्मण समाज के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं वो सामाजिक वैमस्यता बढ़ाने वाली हैं। स्मरणीय है कि सत्ता की भूख में आज पीडीए की बात करने वाले सपा मुखिया की सरकार बनते ही 2012 में सबसे पहले सीतापुर में बड़ी संख्या में दलित समाज के घरों को जला दिया गया था। इटावा की घटना की जांच चल रही है किंतु अखिलेश यादव जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। हिंदू समाज में किसी भी जाति का, कोई भी व्यक्ति जिसे धर्मग्रंथों का ज्ञान है तथा जनमानस को अच्छी बातें बताने की क्षमता रखता है वह कथावाचन कर सकता है। अधिकांश कथा वाचक गैर ब्राह्मण ही हैं। कथावाचक की जाति पर कभी चर्चा नहीं होती। यदि कोई कथावाचक अपनी जाति व धर्म को छुपाकर यह कृत्य करता है तो चिंता की बात है। कोई कथा कहना चाहता है तो उसे अपना सही नाम बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। नाम छुपाने के साथ साथ एक से अधिक आधार कार्ड रखना एक आपराधिक कृत्य है कोई कथावाचक ऐसा क्यों करेगा? इस पूरी घटना में सपा की प्रतिक्रिया से लगता है कि संभव है कि इटावा की घटना सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत करवाई गई हो और एक समय बसपा का नारा रहे तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार को अब सपा ने अपना लिया है। सपा ने पीडीए का दिल जीतने के लिए ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। इस बीच सपा ने राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रास वोटिंग करने वाले तीन विधायकों ऊंचाहार से मनोज कुमार पांडेय, गोसाईगंज से अभय सिंह और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। सपा की ओर से एक्स पर लिख गया कि सांप्रदायिक व पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण तीनों विधायकों को निकाला गया है। वहीं इन विधायकों का कहना है कि भगवान राम और रामचरित मानस के अपमान का विरोध करने के कारण इन सभी को निष्कासित किया गया है। विधायक मनोज पांडेय ने कहा कि मैंने सपा नेताओं द्वारा हिंदू देवी-देवताओं को गाली दिए जाने तथा रामायण की प्रतियां जलाने का विरोध किया था। विधायक मनोज पांडेय अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर आये हैं। सभी विधायकों ने कहा कि सपा में हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समाजवादी पार्टी ने अब लोहिया की विचारधारा को त्याग चुकी है। अखिलेश यादव आजकल कोई भी विषय हो पीडीए को बीच में घसीट लाते हैं। हाल ही में सोने-चांदी के बढ़ रहे दामों पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सोने-चांदी के दाम चरम सीमा पर है जिस कारण गरीब पीडीए समाज की बिटिया की सगाई में सोना कैसे खरीदा जाएगा जबकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि सोने चांदी की कीमतों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है अपितु यह अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होता है। समाजवादी पार्टी मुखिया एक घोषणा यह भी कर रहे है कि जब उनकी सरकार आयेगी तब महापुरुषों की सोने की मूर्तियां लगवाई जाएंगी। अखिलेश यादव ने कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन और बहराइच में महाराज सुहेलदेव राजभर की सोने की मूर्तियां लगवाने की घोषणा की है। सत्यता यह है कि सपा मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास और हिन्दुत्व के समन्वित एजेंडे का उत्तर नहीं खोज पा रहे हैं। बहराइच में योगी जी महाराज सुहेलदेव की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं। मूर्तियों की घोषणा पर सपा मुखिया से यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जब 2012 से 217 तक प्रदेश में उनकी सरकार थी तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही तब उसने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते मुस्लिम आक्रान्ताओं को पराजित करने वाले महाराज सुहेलदेव सहित किसी भी अन्य महापुरुष का सम्मान नहीं किया। इसी प्रकार सपा नेता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में आगरा में भव्य संग्रहालय और लखनऊ गोमती नदी के तट पर सोने के सिंहासन पर बैठी उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सपा मुखिया इतना सोना आखिर लायेंगे कहां से ? नेताओं को वही घोषणाएं करनी चाहिए जिस पर जनमानस विश्वास कर सके, नहीं तो चुनाव परिणाम आने पर फिर वही राग छिड़ेगा कि ईवीएम खराब है बैलट वापस लाओ।

स्थायी सीमांकन जरूरी

भारत और चीनके बीच सम्बन्ध जटिल हैं, जिसमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों मौजूद हैं। १९५० में राजनयिक सम्बन्धोंकी स्थापनाके बादसे दोनों देशोंके बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ा है, लेकिन चीनकी विस्तारवादी नीतिके चलते सीमा विवाद और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों देशोंके बीच तनावकी मुख्य वजह बनी हुई है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेशमें सीमा विवाद दोनों देशोंके लिए प्रमुख चुनौती है। गलवान घाटीमें २०२० में हुई हिंसक झड़पने तनावको और बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों देश सीमापर शान्ति और स्थिरता बनाये रखनेके लिए तंत्र स्थापित करनेपर सहमत हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद और अविश्वासकी लम्बी लकीर कम नहीं हुई। इसीलिए भारतने चीनके साथ सभी विवादोंके स्थायी समाधानकी वकालत की है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहने चीनके रक्षामंत्री एडमिरल डोंग जूनके साथ द्विपक्षीय वार्तामें दो-टूक कहा है कि दोनों देशोंके बीच शान्ति और स्थिरताके लिए भारत-चीनके बीच स्थायी सीमांकन जरूरी है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहका यह कहना उचित और न्यायसंगत है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे दोनों देशोंके बीच तनाव और अविश्वासकी खाईंको पाटा जा सकता है। हालांकि चीनने दोनों देशोंके बीच सम्बन्धोंको बेहतर बनानेके लिए बातचीतपर जोर दिया है, लेकिन उसकी कथनी और करनीमें भारी अन्तर होनेके कारण उसकी बातपर विश्वास बेमानी है। चीनको यदि भारतके साथ बेहतर सम्बन्ध बनाना है तो उसे अपनी विस्तारवादी नीतिको छोड़कर सीमा विवादका स्थायी हल निकालना जरूरी होगा और एक-दूसरेकी सीमाका सम्मान करना होगा, यह दोनों देशोंके हितमें होगा। चीनकी नीति और नीयत ठीक न होना भी दोनों देशोंके सम्बन्धोंको बेहतर बनानेमें बड़ी बाधा है, इसलिए चीनको अपनी नीति और नीयतमें बदलाव लाना होगा और पड़ोसीका धर्म निभाना होगा। आतंकवादपर दोहरा रवैया छोड़ना होगा। चीन एक तरफ तो भारतके साथ बेहतर सम्बन्ध बनानेकी बात करता है, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी देश पाकिस्तानको आर्थिक, सामरिक मदद देकर भारतको अस्थिर करनेका प्रयास करता है। इसपर भारतको गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है। चीन जबतक अपने रवैयेमें परिवर्तन नहीं लाता है और विवादके स्थायी समाधानके लिए कटिबद्ध नहीं होता, तबतक उसकी किसी बातपर विश्वास करना बेमानी है।

लिव-इन रिश्ते अहितकारी

भारतीय समाजका युवा वर्ग आजके दौरमें किस तरह अपनी पारम्परिक सभ्यता और संस्कृतिसे दूर होता जा रहा है इसे लिव-इन-रिलेशनशिपके परिप्रेक्ष्यमें देखनेकी जरूरत है। लिव-इन-रिश्तेकी अवधारणा भारतीय समाजको स्थापित मूल्योंके विरुद्ध है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालयने लिव-इन-रिलेशनशिपको वैधानिक मान्यता प्रदान की है, लेकिन ऐसे मामलोंकी संख्या जिस गतिसे बढ़ रही है, वह गम्भीर चिन्ताका विषय है। यह भारतीय परम्परा और संस्कृतिपर कुठाराघात है और पश्चिमी सभ्यताको बढ़ावा देनेवाला है। ऐसे ही एक मामलेकी सुनवाईके दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालयके न्यायमूर्ति न्यायाधीश सिद्धार्थकी एकल पीठका यह कहना महत्वपूर्ण है कि ऐसे रिश्ते पुरुषोंकी अपेक्षा महिलाओंके लिए ज्यादा अहितकर है। पुरुष ऐसे रिश्ते खत्म होनेके बाद आगे बढ़ सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं लेकिन महिलाओंके लिए ब्रेकअपके बाद जीवनसाथी ढूंढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे रिश्ते स्थायी नहीं होते, क्योंकि इसका उद्देश्य मुख्य रूपसे यौन सम्बन्ध बनाना होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ ही दिनों बाद पति-पत्नीके रूपमें रह रहे दम्पतीके रिश्तोंमें दरार पड़नी शुरू हो जाती है जिसका अन्त ब्रेकअपसे होता है। इसके बाद महिलाके पश्चातापके अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। यह पश्चिमी सभ्यताका दुष्प्रभाव है जिसका खामियाजा महिलाओंको भुगतना पड़ता है। विवाह एक बन्धन है जो दम्पतीको एक साथ रहनेको बाध्य करता है। खासकर हिन्दू विवाह भारतकी सभ्यता संस्कृतिमें एक पवित्र संस्कारके रूपमें स्थापित है। इसमें पति-पत्नी अग्निको साक्षी मानकर सप्तपदीकी परम्पराको पूरा करते हुए एक साथ रहने और जीने-मरनेकी शपथ लेते हैं। हिन्दू धर्मके अनुसार विवाह एक-दो जन्मोंका नही सात जन्मोंका सम्बन्ध है। इसके बावजूद किन्हीं विशेष परिस्थितिमें ब्रेकअपकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अदालतके आदेशसे विवाहिताके भरण-पोषणका मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। लिव-इन-रिलेशनशिपकी अवधारणाने युवा पीढ़ीको काफी आकर्षित किया है लेकिन इसके दुष्परिणामकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। शीर्ष न्यायालयने भले ही इसकी वैधानिकतापर मुहर ल गा दी है लेकिन इसमें कुछ कठोर पाबन्दियोंके साथ संशोधनकी जरूरत है जिससे महिलाओंको शोषणसे बचाया जा सके।

लोक संवाद

विश्व शांतिके अग्रदूत

महोदय,-हे ट्रम्प जी! तुस्सी ग्रेटेस्ट हो जी! तीसरे विश्वयुद्धको लालायित दुनियामें तुम शांतिदूतका साक्षात् अवतार हो। भगवान हर जगह शांति स्थापित करने नहीं आ सकते। इसलिए वह केवल आपको अपना शांतिदूत बनाकर दो लड़नेवालोंके बीच शांति स्थापना करनेको भेज देते हैं। हे ट्रम्प जी! जबसे आप शांतिदूतके नये अवतारमें आए हैं, चारों ओर आपका ही डंका बज रहा है। युद्ध करवानेपर जिसका हक हो शांति करवानेपर भी उसीका हक होता है। आपने भारत और पाकिस्तानके बीच सीजफायर करवाया। आपने इसरायल और ईरानके बीच सीजफायर करवाया। अब मेरे यहां भी सीजफायर करवा दो प्लीज! मेरी बीवी और मुझमें उसी दिनसे वर्चस्वके लिए संघर्ष चल रहा है जबसे हमारी रिंग सेरेमनी हुई है। पूरे चालीस साल हो गये हम दोनोंके बीच भीषण युद्ध चलते हुए। हालांकि बीच-बीचमें हमारे युद्धको खत्म करवानेको मेरे रिश्तेदारोंने कोशिश भी की, परन्तु कोई बात नहीं बनी। वे सीजफायर! सीजफायर! चिल्लाते रहे और हम दोनों एक-दूसरे पर अस्त्र-शस्त्र चलाते रहे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उसे युद्धके लिए उकसाऊं और वह हाथपर हाथ धरे बैठी रहे। जानसे अधिक मर्दानगी तो मुझे भी अपनी भी प्यारी है ट्रम्प साहब! प्यार, मनुहार, इजहार, इकरार सबकुछ तो घरेलू युद्ध की भेंट चढ़ चुका है। हे ट्रम्प जी! हमारे घरमें नौ पहर चौबीस घंटे युद्ध चला रहता है। मुझे चपाती जली मिली तो मैं बीवीके खिलाफ युद्धकी घोषणा कर देता हूं। बीवीको जो बाजारसे मेरे द्वारा लायी फार्म फ्रेश सब्जीमें गलतीसे मरा कीड़ा मिल जाय वह मुझपर सीधा अटैक करती है, बिना किसी पूर्व चेतावनीके। हे ट्रम्प जी! मेरी बीवी तो युद्ध करते-करते अभीतक नहीं थकी। पता नहीं उसे पीछेसे कौन सपोर्ट कर रहा है। मुझे पता है कि उसके रिश्तेदार मुझे सपोर्ट करनेका नाटक करते उसे डटकर असलहा मुहैया करवा रहे हैं। आपकी कसम ट्रम्प जी! अपने घरमें अपनी ही बीवीके खिलाफ मैं धर्म युद्ध लड़ता-लड़ता थक गया हूं। मेरा साहस अब जवाब दे रहा है। अब आप हमारे बीच मध्यस्थता करके अब सौ प्रतिशत गारंटी वाली सीजफायर करवा दीजिए प्लीज। **-अशोक, वाया ईमेल।**

एससीओमें भारतका कड़ा सन्देश

भारतके रक्षामंत्री राजनाथ सिंहने चीनके पोर्टे सिटी किंगदाओमें आयोजित एससीओकी बैठकमें आतंकवादके मुद्देपर पाकिस्तानको बेनकाब करते हुए संयुक्त घोषणापत्रमें हस्ताक्षर करनेसे मना कर नये भारतका कड़ा संदेश दिया साथ ही विश्वको भी जता दिया कि भारत आतंकवादको पोषित करने वाले देशोंके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा।

❐ **ललित गर्ग**

चीनके पोर्टे सिटी किंगदाओमें आयोजित शंघाई सहयोग संघटनन (एससीओ) संयुक्त घोषणापत्रमें बलोचिस्तानकी चर्चा की गयी थी किन्तु पहलगामके क्रूर आतंकवादी हमले जिनमें धर्म पूछकर २६ लोगोंको मारे जानेका कोई विवरण नहीं था। भारतकी आतंकवादको लेकर दोहरे मापदंडके विरुद्ध इस दृढ़ता एवं साहसिकताकी चर्चा विश्वव्यापी हो रही है। भारतने विश्वको आगाह कर दिया है कि अब आतंकवादके मुद्देपर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। राजनाथ सिंहके अडिगता एवं असहमतिके इस कदमसे एससीओके रक्षामंत्रियोंका सम्मेलन बिना संयुक्त वक्तव्य जारी किये ही समाप्त हो गया, जो पाकिस्तान एवं चीनके मुंहपर करारा तमाचा है। ऐसा होना भारतकी ही जीत है और चीन-पाकिस्तानके लिए शर्मसार होनेकी घटना है। विशेषत: इस घटनाक्रमसे चीनकी बदनीयत एक बार फिरसे उजागर हो गयी है। भारत विश्व स्तरपर इस कोशिशमें लगा रहता है कि आतंकवादका दबाव कम हो, दुनिया आतंकमुक्त बने, निर्दोष लोगोंकी क्रूर आतंकी हत्याओंपर विराम लगे, परन्तु दुर्भाग्यसे दुनियामें अनेक देश अपना राजनीतिक नफा-नुकसान देखकर ही इसपर अपना रुख तय करते हैं। वास्तवमें एससीओकी बैठकमें भी यही हुआ है। त्रासद विडंबना है कि एससीओमें शामिल देशोंने भारतमें पड़ोसी देश पाकिस्तानकी आतंक घटनाओंपर विसंगतिपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाया। वास्तवमें यह एक और प्रमाण है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद संबंधी भारतीय शिकायतको गम्भीरतासे नहीं लिया जा रहा है। इस बीच, अमरनाथ यात्रासे ठीक एक सप्ताह पहले गुरुवारको उधमपुर जिलेमें सुरक्षा बलों और आतंकियोंके बीच मुठभेड़ सोचनेपर मजबूर करती है। पाकिस्तानकी आतंकी हरकतें रूक नहीं रही है, अमरनाथ यात्रा पहले ही आतंकियोंके निशानेपर रही है और इस बार भी आतंकियोंके निशानेपर है, विगत तीन दशकसे तनावकी स्थितिमें ही अमरनाथ यात्रा हो रही है। सुरक्षा बल शांतिपूर्ण यात्राके लिए प्रयासरत हैं लेकिन एससीओ जैसे संघटनोंको पाकिस्तानको सख्त हिदायत देते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद रुकना चाहिए। निश्चित ही एससीओ सम्मेलनमें भारतके रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एक निडर एवं साहसिक नेताके रूपमें उभरे। उन्होंने आतंकवादकी जड़ोंपर प्रहार करनेकी भारतकी नयी नीतिकी रूपरेखा सम्मेलनमें रखी। उनका कहना था कि संघटनके सदस्य देशोंको आतंकवाद जैसी सामूहिक सुरक्षासे उत्पन्न चुनौतीके मुकाबलेके लिए एकजुट होना चाहिए। उनका मानना था कि कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद दुनियामें शांति, सुरक्षा और विश्वासको कम कर रहे हैं। यह भी कि आतंकवादपर तार्किक प्रहार किये बिना सदस्य देशोंमें शांति एवं समृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने उन तत्वोंको बेनकाब करनेका प्रयास किया जो आतंकवादको एक हथियारके रूपमें इस्तेमाल करनेके लिए उसे प्रश्रय देते हैं। उनका मानना था कि एससीओ आतंकवादपर दोहरे मापदंड अपनानेके बजाय इसको प्रश्रय देनेवाले देशोंकी आलोचना करे, आतंकवादको समाप्त करनेकी मुहिममें निष्पक्ष बने। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षामंत्री इसपर भी अड़े रहे कि एससीओमें आतंकका समर्थन करनेवाले देशोंकी निन्दा एवं भर्त्सना होनी चाहिए। इसका अर्थ था कि पाकिस्तानको बख्शा न जाय, लेकिन चीनने आशंकाके अनुरूप ढिठाई एवं बदनियत ही दिखायी। चीन लगातार पाकिस्तानके आतंकवादपर सहयोगी दृष्टिकोण अपनाये हुए है। उसे आतंकवादके खिलाफ सख्त होना चाहिए लेकिन वह पहले भी आतंकवादके प्रति नरमी दिखा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमें वह पाकिस्तानके आतंकी सरगनाओंका बचाव कर चुका है। इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उसपर कोई असर नहीं पड़ा। चीन आतंकको लेकर जितना संवेदनशील होना चाहिए, पाकिस्तानके कारण वह उतना नहीं हो पा रहा है। इससे उनकी अन्तरराष्ट्रीय छवि आहत हो रही है, लेकिन वह सुधरनेको तैयार नहीं है। यह स्पष्ट है कि एससीओमें चीन-पाकिस्तानके बीच बढ़ते शरारतभरे तालमेलपर भारतको इस संघटनमें अपनी भूमिकाको लेकर सतर्क एवं सावधान होना होगा। भारतको यह भी देखना होगा कि विस्तार ले रहे इस संघटनमें अपनी महत्ता कैसे स्थापित करे। यह ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पके मनमाने रवैयेके कारण चीन भारतसे संबध सुधारना चाहता है और कुछ मामलोंमें अपना रुख बदलनेके लिए विवश भी हुआ है, परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि वह भारतके हितोंकी अनदेखी करे या फिर अमेरिका एवं पश्चिमके अन्य देशोंकी तरह आतंकवादपर दोहरा रवैया अपनाये और आतंकके समर्थक पाकिस्तानका सहयोग एवं समर्थन जारी रखे। भारतीय नजरियेसे देखें तो अमेरिका और चीन, दोनों ही भारतमें आतंकवादके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। भूलना नहीं चाहिए, पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपतिने पाकिस्तानी सैन्य जनरलका अपने भवनमें भोजके साथ स्वागत किया है। ऐसे घटनाक्रमोंसे भारतके लिए सन्देश साफ है कि वह आंतरिक स्तरपर आतंकियोंके लिए अपने संघर्षको तीखी धार दे। भारतको अपनी आर्थिक एवं सैन्य ताकत बढ़ानी होगी, तभी आतंकवादको कुचला जा सकता है। आतंकवादके खिलाफ उसे अकेलेकी संघर्षरत रहना होगा। दरअसल एससीओ सम्मेलनमें भारत चाहता था कि अंतिम दस्तावेजमें आतंकवादको लेकर भारतीय चिन्ताओंको जगह दी जाय। इसीलिए सम्मेलनमें रक्षामंत्रीने आपरेशन सिन्दूरकी तार्किकताको बताया और पहलगाम आतंकी हमलेका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगामकी घटना दुनियाके सामने स्पष्ट थी और दुनियाके तमाम देशोंने इसकी निन्दा भी की। इसीसे दो देशोंके बीच युद्धकी नौबत आ गयी, एससीओ सम्मेलनमें उस हमलेको तवज्जो न देनेकी रणनीति दरअसल हकीकतके साथ मखौल एवं दौगलापन है। लेकिन सम्मेलनमें रक्षामंत्रीने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जी-७ शिखर सम्मेलनमें कही उन बातोंको ही विस्तार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादका समर्थन करनेवाले देशोंको कभी पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आश्चर्य जताया था कि आतंकके अपराधियों और इसके पीड़ितोंको एक तराजूमें कैसे तोला जा सकता है। यह कड़ा सन्देश प्रधान मंत्रीने अमेरिकाको दिया था। पाकिस्तान और उसके करीबी सहयोगियोंके नापाक इरादोंको दुनियाको बताने तथा भारतकी बात हर देशतक पहुंचानेके लिए भारतने बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल दुनियाभरमें भेजे। लेकिन पाकिस्तानके सदाबहार दोस्त चीनके दबदबेवाले एससीओ सम्मेलनमें पाकिस्तानके आतंकी मनसूबोंको लेकर स्पष्ट नजरिया बनना जरूरी है। एससीओकी घोषणामें यदि यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तानकी गड़बड़ीमें भारत शामिल है तो फिर भारतको ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करनेकी जरूरत है। ऐसे झूठे एवं भ्रामक तथ्योंका प्रतिकार जरूरी है। ऐसे झूठको फैलाकर ही पाकिस्तान दुनियासे सहानुभूमि जुटाता रहा है। इसलिए किसी भी ऐसे विश्वस्तरीय सम्मेलनमें अपनी बात भी पुरजोर ढंगसे तथ्यपरक तरीकेसे रखनी चाहिए। वहां पारित होने वाले प्रस्तावोंके प्रति रक्षामंत्रीकी भांति ज्यादा संवेदनशील एवं सख्त होनेकी जरूरत है। भारत अपनी इसी नीतिको दोहरा कर शत्रु मानसिकता वाले देशोंको सबक दे सकेगा। पाकिस्तानके प्रति भारतकी सख्ती हर मोरचेपर दिखाई दे। भले ही पाकिस्तान हकीकत न देखनेकी गलती दोहराता रहे। अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी उद्देश्योंके लिए आतंकवादको प्रायोजित, पोषित तथा प्रयोग करनेवालोंको इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। ऐसा करते हुए वह कंगाल होनेकी कगारपर पहुंच चुका है, वह लगातार गरीबी और कमजोरीका शिकार हो रहा है। आतंकवादको पोषित करते हुए यह देश अन्य देशोंकी दयापर आश्रित होता जा रहा है। लेकिन भीखमें मिली दया या अनुदानसे कबतक खुदको कायम रख पायेगा।

एससीओकी घोषणामें यदि यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तानकी गड़बड़ीमें भारत शामिल है तो फिर भारतको ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करनेकी जरूरत है। ऐसे झूठे एवं भ्रामक तथ्योंका प्रतिकार जरूरी है। पाकिस्तानके प्रति भारतकी सख्ती हर मोरचेपर दिखाई दे। अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी उद्देश्योंके लिए आतंकवादको पोषित करनेवालोंको इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। ऐसा करते हुए वह कंगाल होनेकी कगारपर पहुंच चुका है, वह लगातार गरीबी और कमजोरीका शिकार हो रहा है। आतंकवादको पोषित करते हुए यह देश अन्य देशोंकी दयापर आश्रित होता जा रहा है।

सांस्कृतिक संवर्द्धन ही सृजनका ध्येय

अस्तित्वकी अभिव्यक्ति है प्रकृति। अस्तित्व है अंतहीन। सृजन प्रकृतिका धर्म है। प्रतिपल नयी कोंपलें, नयी कली, नव पराग, नव मकरंद। सृजनके विधाता देव ब्रह्मा हैं। वे कभी थकते नहीं। अथक सृजन। अकथ विस्तार।

❐ **हृदयनारायण दीक्षित**

अस्तित्वकी अभिव्यक्ति प्रकृति अंतहीन है। कीट-पतिंग भी नवसृजन हैं। नन्हीं गौरैय्याके मुंहमें दाना डालती गौरैय्या माता या अपने बच्चेको पेटमें चिपकाये इस डालसे उस डालपर छलांग लगाती बन्दरिया। बछड़ेको चाट-चूमकर शक्तिशाली गोवंश तैयार करती गोमाता। सृजनके विधाता देव ब्रह्मा हैं। वे कभी थकते नहीं। बार-बार अथक सृजन। अकथ विस्तार। गीत, काव्य, संगीत और समूचा साहित्य प्रकृतिकी सृजन शक्ति ही विस्तार है। प्रकृति रचती-गढ़ती है तो यह कर्म प्रकृति है और मनुष्य रचता है तो संस्कृति। प्रकृतिमें सत् चित् आनन्दकी त्रयी है तो संस्कृतिमें सत्य, शिव और सुन्दरकी त्रय-दिव्यता है। प्रकृतिमें सुन्दरतम् सृजनकी गहन अभीप्सा है। मनुष्य प्रकृतिका भाग है। इसलिए मनुष्य भी सुन्दरतम् सृजनकी कामनासे भरापूरा है। बस चित्त प्रशांत होना चाहिए। आनन्द हमारी सर्वोत्तम अभीप्सा है। हरेक सृजनका लक्ष्य आनन्द है। यह आनन्द स्वयंतक ही सीमित नहीं है। सृजन धर्म स्वयंका अतिक्रमण करता है और लोकआनन्द एवं लोकमंगलका हेतु सेतु बनता है। प्रकृतिके पास असीम अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य है। प्रकृतिका अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य संविधानकी देन नहीं। वह वर्षा रचती है, कभी आंधीके साथ, कभी आंधीके पूर्व और कभी आंधीके बाद भी। वह गहन उमसके बीच भी वर्षा ले आती है। आकाशमें इन्द्रधनुष रचनेके लिए उसे इन्द्र या वरुण देवोंकी अनुमति नहीं चाहिए। मनुष्यको भी अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रता है। इस स्वतन्त्रताका सदुपयोग लोकमंगलके लिए ही होना चाहिए। अन्तस्में सत् चित् आनन्दका गीत है। सत्य, शिव और सुन्दर इसीकी अभिव्यक्ति है। भारतीय परम्परामें सृजनका दिक्सूचक यही केन्द्र है।

शाश्वत तत्वोंको सृजनका विषय बनानेकी भारतीय परम्परा महत्वपूर्ण है। तात्कालिक विकृतियोंको हटाना और शाश्वत मूल्योंकी प्रतिष्ठा जरूरी है। संस्कृतिके सारगर्भसे जुड़नेकी यह बात महत्वपूर्ण है। साहित्यका प्रभाव समाजपर पड़ता है और समाजका साहित्यपर भी। रामकथामें रावणके चरित्र वर्णनका समाजपर गहरा असर पड़ा है, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चोंका नाम रावण नहीं रखता। विभीषण भी नहीं रखता, यद्यपि विभीषणने रामका सहयोग किया था लेकिन देशभक्ति प्रश्नवाचक थी। लोकने अच्छे कार्यके बावजूद उसे 'घरका भेदी' ही कहा। लेखन सृजन निरुद्देश्य नहीं होते। तुलसीदासने अपने सृजनको 'स्वान्त: सुखाय' बताया था। स्वसुखके लिए काम करना उचित भी है। सबके अपने सुख होते हैं। तुलसीका सुख लोकमंगलका विस्तार है। प्रत्यक्ष भूमण्डलके सभी लोगों और लोकोंका मंगल। फिर स्व सुख और स्वान्त: सुखमें अन्तर भी है। स्वान्त:में अन्तस् का अन्तिम छोर है। भारतीय चिन्तनमें स्व अन्तस्का अन्तिम छोर विराटसे जुड़ा हुआ है। तुलसीके राम अखिल लोकदायक विश्रामा हैं, उनकी राम कथा 'सुरसरि सम सबका हित होई' से ध्येयबद्ध है। सृजनका उद्देश्य लोकमंगल ही है। होना भी चाहिए। सृजन आनन्दवर्द्धन होता है। इसका लक्ष्य लोकमंगल है। यह निराशाकी तमस्में आशाका दीप प्रज्वलन है। शाश्वत और चिरन्तनका नूतन आख्यान है। दृश्यमान विभाजित अनेकताके भीतर एकताका दर्शन है और सामूहिक उल्लासका संयोजन भी। भरत मुनिने नाट्यशास्त्रमें सुखान्तपर जोर दिया था। सांस्कृतिक मर्यादाका संवर्द्धन और शीलरसका संवर्द्धन भी साहित्यकारका दायित्व है। कथित प्रगतिशीलतामें नेह-स्नेहके आत्मीय रिश्तोंके प्रति आक्रामकता है। पिता भारतीय परम्परामें देव कहे गये हैं। हम सब माता-पिताका विस्तार हैं। वे न होते तो हम न होते लेकिन नवलेखनमें प्राय: माता-पिताकी वैसी प्रतिष्ठा नहीं है। महाभारतकार भी कवि या साहित्यकार थे। उनके सृजनमें यक्ष प्रश्न हैं। यक्षने पूछा, युधिष्ठिर। धरतीसे भी भारी क्या है और आकाशसे भी ऊंचा क्या। युधिष्ठिरने कहा, माता पृथ्वीसे भारी है और पिता आकाशसे भी ऊंचा। ऐसे लेखनमें माता-पिताकी प्रतिष्ठा है। परिवार प्रीतिकर संस्था है। प्रगतिशीलता उसे तोड़ रही है। परिवारका विकल्प नहीं। परिवारको मजबूत करनेवाला लेखन समयकी आवश्यकता है। ऋग्वेदमें नदियोंको प्रणाम किया गया है। नदियां प्रणामके योग्य हैं भी। वे जलमाताएं हैं। विज्ञान भी नदियोंकी महत्ता स्वीकार कर चुका है। वैदिक साहित्यमें विश्वामित्र और नदीका संवाद अनूठा है। विश्वामित्र जैसे पूर्वजोंने नदियोंसे संवादमें भरतवंशियोंकी तरफसे तमाम आश्वासन दिये थे। वे आश्वासन हमारे साहित्यका हिरण्य कोष हैं। लेकिन हम सबने वे आश्वासन तोड़े हैं। नदी और मनुष्यकी प्रीति शून्य हो चुकी है। नदियोंने कहा था, यह संवाद याद रखना, हमारा ध्यान रखना। तुम पार उतरो, हम वैसे ही नीचे झुक रही हैं जैसे बच्चेको स्तनपान करानेके लिए मां झुकती है। विश्वामित्रने कहा था, हे नदियों, मैं आपकी स्तुति करता रहूंगा। सामन्ती कालमें अनेक चारण राजाओंकी प्रशंसा गाते थे। लेकिन वे स्तोता नहीं थे, उनके गायन स्तुति नहीं थे और न ही स्तोत्र। स्तोता होना बड़ी कठिन साधना है। मन, क्रम, वचन और अन्तस्से उगा सृजन ही किसीको स्तोता बनाता है। विश्वामित्रने नदियोंको आश्वासन दिया था हम भारतके लोग आपके स्तोता रहेंगे, जलमाताओंका पोषण करेंगे, तनसे, मनसे। वैदिक साहित्यमें प्रकृतिके कण-कणके प्रति आत्मीयता है। कथित प्रगतिशील दृष्टिमें प्रकृति उपभोक्ता सामग्री है और भारतीय परम्परामें यही प्रकृति नमस्कारोंके योग्य है। तुलसीदासके सृजनमें भौतिक जगत सीयराममय है और बारम्बार प्रणम्य है-सीयराम मय सब जग जानी करूऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रकृतिके प्रति अंगांगी भावकी सतत् अभिव्यक्ति जरूरी है। भारतीय संविधानमें राज्यके नीति निदेशक तत्व हैं। लेखन, सृजनके भी नीति निदेशक तत्व हैं। भले ही वे संहिताबद्ध नहीं हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है। मां-पिताकी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण तत्व है। कथा, कहानी और काव्यमें इस तत्वको ध्यानमें रखना चाहिए। स्त्री आदरणीया है, मां है, बहन है, पुत्री है, श्रद्धेय है। सम्पूर्णताका भाग है। उसे अलग करके देखना-लिखना अनुचित है। भारतीय काम सेक्स नहीं, सृजन अभिलाषा है। यहां काम भी अध्यात्म है। हम सांस्कृतिक राष्ट्र हैं। करोड़ों भरतवंशी एक जन हैं। इनकी एक एकात्म अनुभूत संस्कृति है। इस संस्कृतिका विकास दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे परिपूर्ण हमारे पूर्वजोंने ही किया था। उन पूर्वजों, अग्रजों, मार्गदर्शकोंके प्रति आदरभावका पुरश्चरण अपरिहार्य है और सांस्कृतिक तत्वोंका भी। लेखनमें हम कल्पनाके पंख लगाकर उड़ते हैं, यथार्थवादी भी हो सकते हैं लेकिन भारतीय शील-मर्यादाके गंधमादन क्षेत्रके मधुरसाका उल्लंघन उचित नहीं। मधुरसा सांस्कृतिक प्रवाहका संवर्द्धन ही सृजनका ध्येय है। विचार अभिव्यक्तिकी बातें ठीक हैं, लेकिन विकार-अभिव्यक्ति की नहीं।

आत्मबोध

प्रभुकी कृपा

❐ **बाबा हरदेव**

ऋषि-मुनियोंने बताया है कि जिस अनुपातसे अहंकार छूटता जाता है। उसी अनुपातसे हम स्वतंत्र होते जाते हं। अब ये हमपर निर्भर करता है कि हम परतंत्रताका बोझ उठाना चाहते हैं या फिर स्वतंत्रताका आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान देने योग्य है कि जब कोई मनुष्य किसी चीजके बारेमें ऊपरसे ज्यादा जानता है तो मनुष्य तो वही रह जाता है, इसका परिचय ज्ञान संग्रह बढ़ता चला जाता है, परन्तु ये खुद वहीं रह जाता है, इसमें रत्तीभर भी फर्क नहीं आता। मानो ऊपर-ऊपरसे जाननेका मतलब ऐसे ही है, जैसे कोई साधारण धनी आदमी अपनी तिजोरीमें तो धन-दौलत बढ़ाता चला जाता है, पहले दस फिर हजार, लाख, लेकिन क्यों इस आदमीकी तिजोरीमें धन बढ़ेगा तो आदमी सही मायनोंमें धनी हो जायगा। अकसर देखनेमें आया है कि ऐसे आदमी जितने ऊपरसे धनी मालूम होते हैं, ये अपने अन्दरसे गरीब हो जाते हैं। मानो ये तो केवल अपनी संग्रहकी हुई दौलतपर ही पहरा देने वाले बन जाते हैं, केवल दौलतके चौकीदार, जबकि यदि कोई व्यक्ति गहराईसे जानता है तो इसके अन्दर एक महाक्रांति घटित होती है। इसकी जीवन जीनेकी शैली बदल जाती है, क्योंकि गहरा जानेके लिए खुद गहरा होना पड़ता है, खुदको खुदको मिटाना अनिवार्य है। प्रभुकी कृपासे भक्त सचाईको अपनाने वाला, निर्मल स्वभाव वाला और बच्चों जैसा अज्ञानी हो जाता है। वही बच्चों जैसी सरलता इसके जीवनमें आ जाती है। बड़ा ही प्यारा सूत्र है- कितना मनुष्य ऊपरसे जानता है, इसके परम ज्ञानका कोई संबंध नहीं है, जबकि कितना मनुष्यके जीवनमें परिवर्तन आया है, कितना ये अध्यात्ममें डूबा है, कितना गहरा गया है, इससे इसके परम ज्ञानका संबंध है। इस सूरतमें इसका अहंकार विलीन हो जाता है। जहां अहंकार विलीन होता है, वहां परम ज्ञानमें डुबकी लग जाती है। मानो अहंकार हमारा तैरना है, ऊपरी जानकारी है और जब अहंकार छूट जाता है, हाथ-पांव मारने बंद हो जाते हैं, फिर तैरना नहीं, तरनेकी पद्धति प्रकट होती है। ये परम ज्ञान आध्यात्मिक शांतिका स्रोत है। क्योंकि सद्गुरु भक्तको परम ज्ञान प्रदान करके इसकी सभी वासनाओं और महत्वाकांक्षाओंको खींचनेकी, इसके प्राणोंकी सारी बिखरी हुई विवेक रूपी किरणोंकी एक लपट बनाने और फिर इस लपटसे प्रभु परमात्माकी यात्रा यानी परम सत्यकी यात्रापर ले जानेकी पूर्ण क्षमता रखता है। अत: पूर्ण सद्गुरुकी कृपा द्वारा ही परिचय ज्ञान और परम ज्ञानकी वास्तविकता जानी जा सकती है और परम ज्ञानके होते ही संसार नामकी कोई चीज नहीं रह जाती, क्योंकि परम ज्ञानका अभाव ही संसार है। मानो अज्ञानसे देखा गया परमात्मा भी संसार है और परम ज्ञानसे देखा गया संसार है, परमात्मा।

लगातार बाजार छोड़ रहे विदेशी संस्थागत निवेशक

❐ **मिथिलेश झा**

इन दिनों सेबी लगातार प्रयास कर रही बाजारको सुधारका। एफएनओ और फ्यूचरको लेकर सेटलमेण्ट दिनको निर्धारित कर रहा है। एनएससीको किस दिन किया जायगा और बीएससीको किस दि। लगता है सेबी बाजारको सुधार कर ही मानेगी। किन्तु शेयर बाजारके संरचनामें हुए परिवर्तनको अभीतक सुधारते हुए नहीं दिखता है। बाजारमें मात्र ट्रेड-टू-ट्रेड, एएसएममें शेयरोंको डालने और निकालनेसे क्या होगा। भारतके शेयर बाजारमें बड़ासे बड़ा एक्सपर्ट भी धोखा खा जाय, क्योंकि यहांपर खुली छूट है। आपको जैसे करनेका मन हो करते जाइये। आपको मतलब है कारपोरेट लाबी की। बहुत-सी कम्पनियां हैं, जो दो-चार रुपयेका होता है, इसमें तरह-तरहका ग्रुपमें डाला जाता रहा है और एक बार जब यह ३०-४० रुपयेका हो जाय तो सारे सट्टेबाजी खत्म हो जाता है। न कोई नियम है, न कोई कानून जब चाहे शेयरको ट्रेड-टू-ट्रेडमें डाला जाता है। कभी बीस प्रतिशतका सर्किट होता है तो सीधे-सीधे पांच प्रतिशतका हो जाता है। ले-देकर सेबी लगातार बाजारमें बाधा पैदा करती है। यह सब छोटे निवेशकोंके बचावके नामपर है। बड़े-बड़े एक्सपर्ट भी भारतीय शेयर बाजारमें धोखा खा जाय। ऐसे समयमें नहीं आयगा यहां क्या होता है। एक कम्पनी है वैरेनियम क्लाऊड। यह कम्पनी बहुत अच्छा कर रही थी। २०२० के बादका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो पता चलेगा यह कम्पनी तेजीसे विकास कर रही थी। २०२० के बाद दो बार बोनस दिया। डिविडेण्ट हर साल दे रही थी। दिसम्बर, २०२३ में जो रिजल्ट आया था उसमें ३९५ करोड़ रुपयेका सेल्स दिखाया गया। इसी समय राइट इश्यू भी लाया गया। यह राइट इश्यू ११८ रुपयेके प्रीमियमपर लाया गया था। यानी १२८ रुपये प्रति शेयरपर दिया गया था। इसी समय फोरेंसिक आडिटकी बात आती है और शेयर गिरना शुरू हो गया। २०२४ में ४०० रुपयेका उच्चतम भाव था। अब गिर रहा है। गिरकर ४.५० पैसा आ गया है। बीचमें कुछ भी पता नहीं चला। कम्पनी काम कर रही है या नहीं। निवेशकोंको कुछ भी पता नहीं है। किसी भी प्रमोटरको इतनी हिम्मत कैसे पड़ती है। निवेशकोंका पैसा डूबे, वह भी रेगुलेटरी संस्थाके कारण। भारतीय राजनीतिमें अभी वह जागरूकता नहीं आयी है जिससे शेयर बाजारके महत्वको समझा जा सके। देशके अन्दर बातें हो रही हैं एक तरफ २०१४ के बादसे विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बाजार छोड़ रहे हैं। २०१३-१४ में विदेशी संस्थागत निवेशकोंका निवेश भारतीय अर्थव्यवस्थामें २२ प्रतिशतका था। २०१४ के बाद यह लगातार घट रहा है। वर्तमानमें यह १६ प्रतिशतके पास आ गया है। विदेशी निवेशक लगातार बाजार छोड़ रहे हैं। यह क्यों हो रहा है इस बातपर सरकारको ध्यान देनेकी जरूरत है। वेरेनियम क्लाऊड इसका उदाहरण है। ऐसी हजारों कम्पनी होंगी, जो अच्छा कर रही हैं किन्तु वह मात्र कागजोंपर अच्छा कर रही हैं या हकीकतमें कुछ हो रहा है। इसकी गारण्टी नहीं है, क्योंकि सरकार भी बताती है कि शेयर बाजार रिस्की है। शेयरमें निवेश जोखिमके अधीन होता है। शेयर बाजारमें निवेश तब जोखिमभरा होता है जब कारपोरेटको खुली छूट दे दी जाय। वह मनमानी तरीकोंसे अपना रिजल्ट दिखाये फण्डका प्रयोग मनमाने तरीकोंसे करे। निवेशकसे पैसा उगाही करे और खर्च मनमानी तरीकेसे करे। कोई पूछनेवाला नहीं है। जब पूछा जाता है तो कम्पनी डूबती है। प्रमोटरको किसी प्रकारकी सजा नहीं मिलती है। डूबता है तो निवेशक है। दूसरी बात है २०१४ के बादसे शेयर बाजारके प्रति लोगोंका रुझान तेजीसे बढ़ा है। जहांपर एक-दो प्रतिशत ही शेयर बाजारसे जुड़े लोगोंकी संख्या होती थी। अब यह बढ़कर २२ करोड़ लोगोंकी संख्या हो गयी है। आशा करता हूं २०२९ तक यह संख्या ३२ करोड़ हो जाय तो देशमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तन देखनेको मिलेगा। अभी हाल यह है कि राजनीतिक पार्टी धर्म-जाति आरक्षणसे ऊपर नहीं देख पा रही है किन्तु यह २२ करोड़ लोग जो शेयर बाजारसे जुड़े हैं, इन्हें अच्दी तरहसे दिखता है कि शेयर बाजारमें क्या हो रहा है। सेबी लगातार यह दिखा रही है कि वह बहुत अच्छा कर रही है। यह सरकारको अंधेरेमें रखे हुए है। इस बाजारके माध्यमसे क्या हो रहा है, जो बाजारमें है उन्हें दिख रहा है। शेयर बाजारके अवधारणाको सेबीने पूरी तरह उलट दिया। अब छोटे लोग नये आईपीओको भरनेके लिए तरसेंगे, क्योंकि अब दो लाख रुपया होगा तभी आप एसएमईमें शेयर खरीद सकते हैं। एनसीएलटीमें पुराने निवेशकोंको डुबाया जा रहा है। हेयरकटमें पैसेकी छूट मिलती है। यह पैसा जनताका ही होता है। फिर नया प्रमोटर पुराने शेयर होल्डरका शेयर भी अपने नाम कर लेता है। एक तरहसे देखा जाय तोनये प्रमोटरको फ्रीमें कम्पनी मिल रही है। शेयर बाजारसे आम आदमीका जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। इस बातको सरकार सीधे-सीधे नकार रही है। २०२० के बाद आये आईपीओको देखें लगता ही नहीं कि प्राइस बैण्ड तय करनेमें कोई नियम-कानून है। कम्पनी लगातार घाटापर घाटा दे रही है और उस कम्पनीकी आईपीओकी कीमत देखकर कोई भी कह सकता है कि शेयर बाजारमें क्या हो रहा है। २०२० के बाद जितने भी आईपीओ आये हैं। ज्यादातर कम्पनियोंकी कीमत आधेसे भी कम रह गया है। बाजारमें तेजी चल रही है, तब यह हाल है यदि पहले जैसा दो-तीन वर्षोंकी मंदी चली तो निवेशकोंका क्या होगा, भगवान ही जाने। आईपीओमें सबसे अच्छा विश्लेषण पेटियमके देशमें है। एक रुपयेका फेसवैल्यू है और इसकी कीमत तय किया गया २१५० रुपया। दसके फेसवैल्यूपर देखा जाय तो यह २१ हजार पांच सौका कीमत था। आईपीओकी लिस्टिंग हुई और कभी २१५० रुपयेका कीमत नहीं आया। गिरते हुए यह ४५० रुपयेतक आ गया था। अब जाकर यह ८००-९०० रुपयेपर घूम रहा है। यह कम्पनी लगातार घाटा दे रही थी फिर इसकी कीमत २१५० रुपये कैसे तय हो गया। एक बात तो तय है कि १९९० के दशकमें बाम्बेमें यह प्रचारित था कि हर तेजीमें नये लोग जुड़ते थे और मंदी आनेपर ९० प्रतिशत लोग बाजार छोड़ जाते थे। यदि बाजारके फण्डामेण्टल विश्लेषण आयें तभी बाजारमें निवेश करना चाहिए। बाजारके बारेमें समझ हो। कम्पनीका फण्डामेण्टल विश्लेषण करना आता हो। विकासके रास्तेको समझना आता हो तो शेयर बाजारमें सबसे आसान पैसा मिलता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

हर खबर पर पैनी नजर
नई सोच एक्सप्रेस
(बिहार और झारखंड से प्रकाशित हिन्दी दैनिक)

युद्ध की भूमिका बना रहे आतंकी

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पांच घाटी जिलों में छापामारी कर तीन सौ राइफलें व अन्य हथियार बरामद किए। इसके साथ ही जबरन वसूली करने वाले प्रतिबंधित संगठनों के पांच उग्रवादियों को भी गिरफ्तार किया। मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना व असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने विस्फोटकों व अन्य युद्ध सामग्री बरामद की। इसमें 151 एसएलआर राइफलें, 65 इंसास राइफलें, 73 अन्य प्रकार की राइफलें, बारह हल्की मशीन गनें, पांच कार्बाइन गन, दो एमपी-5 गन, छह एके सीरीज राइफलें, दो अमोघ राइफल, एक मोर्टार, छह पिस्तौलें, दो फ्लेयर बंदूकें, दस ग्रेनेड, सात डेटोनेटर व एक एआर-15 समेत कुल 328 बंदूकें व राइफलें बरामद कीं। यह खुफिया ऑप्रेशन मणिपुर में समान्य स्थिति बहाल करने, सार्वजनिक व्यवस्था कायम करने, नागरिकों व उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिहाज से किया गया। राज्य की पुलिस ने आम जनता से व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अवैध हथियारों से जुड़ी सूचना तत्काल नजदीकी पुलस स्टेशन या केंद्रीय निरीक्षण केंद्र को राज्य में सामान्य देने की अपील की है। जब्त किया गया जखीरा देख कर कहा जा सकता है कि आतंकी युद्ध की भूमिका बना रहे हैं। उनका असल मकसद कुकी व मैतई विद्रोह के बीच फायदा उठाकर राज्य में अमन-चैन तबाह करना है। राज्य की सार्वजनिक व्यवस्था सुचारू बनाने व सामान्य स्थिति बहाल करने के सरकारी प्रयास जारी हैं। लंबे अरसे से संघर्षरत राज्य में आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित है। बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी राज्यों में पलायन कर चुके हैं। रोजगार व आमदनी के साधन चरमरा चुके हैं। घर, दुकान, प्रतिष्ठानों कों बहुत क्षति पहुंची है। इतनी बड़ी संख्या में हथियारों की बरामदगी आतंकियों/ उपद्रवियों के इरादों की द्योतक है। मगर सवाल यह भी है कि चाक-चौबंद सुरक्षा-व्यवस्था व मुस्तैदी के दरम्यान ये अवैध हथियार कैसे राज्य की सीमा के भीतर पहुंच रहे हैं। सीमाओं पर सख्ती के अतिरिक्त घाटी वाले इलाकों पर सतर्कता जरूरी है। राजनीति से इतर इस संघर्ष को रोकने के तत्काल प्रयास बेहद जरूरी हैं। केंद्र द्वारा की जाने वाली उपेक्षा को लेकर पूर्वोत्तर राज्य हमेशा त्योरियां चढाये रहते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। इन छोटे राज्यों के विकास और स्थानीय युवाओं को राजगार देने जैसी मूल दिक्कतों का निस्तारण करने में लापरवाही हमेशा नकारात्मक नतीजे ही देने वाली साबित होगी।

रक्षामंत्री की चेतावनीः एससीओ मंच से चीन-पाक को साफ संकेत

आरती कुमारी

भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के पोर्टे सिटी किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए संयुक्त घोषणापत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर न केवल पाकिस्तान और चीन को नये भारत का कड़ा संदेश दिया, बल्कि दुनिया को भी जता दिया कि भारत आतंकवाद को पोषित एवं पल्लवित करने वाले देशों के खिलाफ अपनी लड़ाई निरन्तर जारी रखेगा। घोषणापत्र में बलोचिस्तान की चर्चा की गई थी किन्तु पहलगाम के क्रूर आतंकवादी हमले जिनमें धर्म पूछकर 26 लोगों को मारे जाने का कोई विवरण नहीं था। भारत की आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड के विरुद्ध इस दृढ़ता एवं साहसिकता की चर्चा विश्वव्यापी हो रही है। भारत ने विश्व को आगाह कर दिया है कि अब आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। राजनाथ सिंह के अडिगता एवं असहमति के इस कदम से एससीओ के रक्षामंत्रियों का सम्मेलन बिना संयुक्त वक्तव्य जारी किये ही समाप्त हो गया, जो पाकिस्तान एवं चीन के मुंह पर करारा तमाचा है। ऐसा होना भारत की ही जीत है और चीन-पाकिस्तान के लिये शर्मसार होने की घटना है। विशेषतः इस घटनाक्रम से चीन की बदनीयत एक बार फिर से उजागर हो गई है। भारत विश्व स्तर पर इस कोशिश में लगा रहता है कि आतंकवाद का दबाव कम हो, दुनिया आतंकमुक्त बने, निर्दोष लोगों की क्रूर आतंकी हत्याओं पर विराम लगे, पर दुर्भाग्य से दुनिया में अनेक देश अपना राजनीतिक नफा-नुकसान देखकर ही इस पर अपना रुख तय करते हैं। वास्तव में एससीओ की बैठक में भी यही हुआ है। त्रासद विडंबना है कि एससीओ में शामिल देशों ने भारत में पडोसी देश पाक की आतंक घटनाओं पर विसंगतिपूर्ण एवं दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाया। वास्तव में, यह एक और प्रमाण है कि पाक पोषित आतंकवाद संबंधी भारतीय शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इस बीच, अमरनाथ यात्रा से ठीक एक सप्ताह पहले गुरुवार को उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सोचने पर मजबूर करती है। पाक की आतंकी हरकतें रूक नहीं रही है, अमरनाथ यात्रा पहले ही आतंकियों के निशाने पर रही है और इस बार भी आतंकियों के निशाने पर है, विगत तीन दशक से तनाव की स्थिति में ही अमरनाथ यात्रा हो रही है। सुरक्षा बल शांतिपूर्ण यात्रा के लिए प्रयासरत हैं लेकिन एससीओ जैसे संगठनों को पाक को सख्त हिदायत देते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में पाक समर्थित आतंकवाद रूकना चाहिए। निश्चित ही एससीओ सम्मेलन में भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एक निडर एवं साहसिक नेता के रूप में उभरे। उन्होंने आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने की भारत की नई नीति की रूपरेखा सम्मेलन में रखी। उनका कहना था कि संगठन के सदस्य देशों को आतंकवाद जैसी सामूहिक सुरक्षा से उत्पन्न चुनौती के मुकाबले के लिये एकजुट होना चाहिए। उनका मानना था कि कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद दुनिया में शांति, सुरक्षा और विश्वास को कम कर रहे हैं। यह भी कि आतंकवाद पर तार्किक प्रहार किए बिना सदस्य देशों में शांति व समृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने उन तत्वों को बेनकाब करने का प्रयास किया जो आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिये उसे प्रश्रय देते हैं। उनका मानना था कि एससीओ आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने के बजाय इसको प्रश्रय देने वाले देशों की आलोचना करे, आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम में निष्पक्ष बने। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षामंत्री इस पर भी अड़े रहे कि एससीओ में आतंक का समर्थन करने वाले देशों की निंदा एवं भर्त्सना होनी चाहिए। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान को बख्शा न जाए, लेकिन चीन ने आशंका के अनुरूप ढिठाई एवं बदनियत ही दिखाई। चीन लगातार पाक के आतंकवाद पर सहयोगी दृष्टिकोण अपनाये हुए है। उसे आतंकवाद के खिलाफ सख्त होना चाहिए लेकिन वह पहले भी आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह पाक के आतंकी सरगनाओं का बचाव कर चुका है। इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। चीन आतंक को लेकर जितना संवेदनशील होना चाहिए, पाक के कारण वह उतना नहीं हो पा रहा है। इससे उनकी अन्तर्राष्ट्रीय छवि आहत हो रही है, लेकिन वह सुधरने को तैयार नहीं है। यह स्पष्ट है कि एससीओ में चीन-पाक के बीच बढ़ते शरारत भरे तालमेल पर भारत को इस संगठन में अपनी भूमिका को लेकर सतर्क एवं सावधान होना होगा। भारत को यह भी देखना होगा कि विस्तार ले रहे इस संगठन में अपनी महत्ता कैसे स्थापित करे। यह ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने रवैये के कारण चीन भारत से संबध सुधारना चाहता है और कुछ मामलों में अपना रुख बदलने के लिए विवश भी हुआ है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत के हितों की अनदेखी करे या फिर अमेरिका एवं पश्चिम के अन्य देशों की तरह आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाए और आतंक के समर्थक पाक का सहयोग एवं समर्थन जारी रखे। भारतीय नजरिये से देखें, तो अमेरिका और चीन, दोनों ही भारत में आतंकवाद के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। भूलना नहीं चाहिए, पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक सैन्य जनरल का अपने भवन में भोज के साथ स्वागत किया है। ऐसे घटनाक्रमों से भारत के लिए संदेश साफ है कि वह आंतरिक स्तर पर आतंकियों के लिये अपने संघर्ष को तीखी धार दे। भारत को अपनी आर्थिक एवं सैन्य ताकत बढ़ानी होगी, तभी आतंकवाद को कुचला जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ उसे अकेले की संघर्षरत रहना होगा। दरअसल, एससीओ सम्मेलन में भारत चाहता था कि अंतिम दस्तावेज में आतंकवाद को लेकर भारतीय चिंताओं को जगह दी जाए। इसीलिये सम्मेलन में रक्षामंत्री ने ऑपेरशन सिंदूर की तार्किकता को बताया और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना दुनिया के सामने स्पष्ट थी और दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा भी की। इसी से दो देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई, एससीओ सम्मेलन में उस हमले को तवज्जो न देने की रणनीति दरअसल हकीकत के साथ मखौल एवं दौगलापन है। लेकिन सम्मेलन में रक्षामंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जी-7 शिखर सम्मेलन में कही उन बातों को ही विस्तार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को कभी पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आश्चर्य जताया था कि आतंक के अपराधियों और इसके पीड़ितों को एक तराजू में कैसे तोला जा सकता है? यह कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया था।

पाक और उसके करीबी सहयोगियों के नापाक इरादों को दुनिया को बताने तथा भारत की बात हर देश तक पहुंचाने के लिए भारत ने बहु-पक्षीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजे। लेकिन पाक के सदाबहार दोस्त चीन के दबदबे वाले एससीओ सम्मेलन में पाक के आतंकी मनसूंबों को लेकर स्पष्ट नजरिया बनना जरूरी है। एससीओ की घोषणा में अगर यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तान की गड़बड़ी में भारत शामिल है, तो फिर भारत को ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है। ऐसे झूठे एवं भ्रामक तथ्यों का प्रतिकार जरूरी है। ऐसे झूठ को फैलाकर ही पाक दुनिया से सहानुभूमि जुटाता रहा है। इसलिये किसी भी ऐसे विश्व स्तरीय सम्मेलन में अपनी बात भी पुरजोर ढंग से तथ्यपरक तरीके से रखनी चाहिए। वहां पारित होने वाले प्रस्तावों के प्रति रक्षामंत्री की भांति ज्यादा संवेदनशील एवं सख्त होने की जरूरत है। भारत अपनी इसी नीति को दोहरा कर शत्रु मानसिकता वाले देशों को सबक दे सकेगा। पाक के प्रति भारत की सख्ती हर मोर्चे पर दिखाई दे। भले ही पाक हकीकत न देखने की गलती दोहराता रहे। अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित तथा प्रयोग करने वालों को इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। ऐसा करते हुए वह कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है, वह लगातार गरीबी और कमजोरी का शिकार हो रहा है। आतंकवाद को पोषित करते हुए यह देश अन्य देशों की दया पर आश्रित होता जा रहा है। लेकिन भीख में मिली दया या अनुदान से कब तक खुद को कायम रख पायेगा?

संविधान में समाजवाद-धर्मनिरपेक्षता की इंट्री इंदिरा की विरासत या साजिश

संजय सक्सेना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने आरएसएस पर निशाना क्या साधा, भारतीय राजनीति में भूचाल ही आ गया। कांग्रेस ने तुरंत आरोप लगा दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'ये बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है, जो आरएसएस-बीजेपी हमेशा से रचती आई है।' इससे पहले दत्तात्रेय होसबोले ने एक कार्यक्रम में कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था और इन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। होसबाले के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन के धड़े और बीजेपी आमने-सामने आ गई है। कांग्रेस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस बदलाव का बचाव करने के लिए इंदिरा की जगह बाबा साहब के पीछे छिपकर भाजपा और संघ नेताओं के खिलाफ हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच बताकर उस पर हमलावर है। गौरतलब हो, भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। यह न केवल देश के शासन की नींव है, बल्कि समय के साथ समाज की बदलती जरूरतों को भी दर्शाता है। संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का समावेश एक ऐसी राजनीतिक घटना है, जो कथित तौर पर भारतीय लोकतंत्र की प्रगतिशीलता और दूरदर्शिता को रेखांकित करती है। इस हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की इंट्री न तो महात्मा गांधी, न ही बाबा साहब अंबेडकर की देन है, बल्कि इसकी बुनियाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तो यह भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने वाला दस्तावेज था। डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने इसे एक ऐसा ढांचा दिया, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। महात्मा गांधी के विचारों ने भी संविधान की भावना को प्रभावित किया, खासकर सामाजिक न्याय और अहिंसा के क्षेत्र में। हालांकि, प्रारंभिक संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थे। यह अनुपस्थिति न तो किसी कमी को दर्शाती थी, न ही किसी विचारधारा की अनदेखी को। यह उस समय की परिस्थितियों का परिणाम था, जब संविधान को एक व्यापक और लचीला दस्तावेज बनाने की जरूरत थी। 1966 में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं, देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। आजादी के बाद के दशकों में भारत ने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया। गरीबी, असमानता और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे देश के सामने थे। इंदिरा ने इन समस्याओं को देखा और महसूस किया कि भारत को एक ऐसी दिशा की जरूरत है, जो न केवल आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करे, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा दे। इसके साथ ही, भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की आवश्यकता थी, ताकि सभी धर्मों और समुदायों के बीच सामंजस्य बना रहे। इंदिरा गांधी का नेतृत्व साहस और दूरदर्शिता से भरा था। उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए, जो समाजवादी विचारधारा का प्रतीक बन गए। उनका मानना था कि भारत का विकास तभी संभव है, जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन यह केवल नारों तक सीमित नहीं था। इंदिरा ने इसे संवैधानिक स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। 1976 में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में 42वां संशोधन पारित हुआ। यह संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में दो महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसके साथ ही, भारत को अब संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया। समाजवादी शब्द का समावेश इंदिरा गांधी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता था, जिसमें आर्थिक और सामाजिक समानता सर्वोपरि थी। यह समाजवाद मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा से अलग था। यह भारतीय संदर्भ में समाजवाद था, जो लोकतंत्र के साथ सामंजस्य बिठाता था। इसका उद्देश्य था कि संसाधनों का वितरण इस तरह हो कि समाज का हर वर्ग, विशेष रूप से गरीब और वंचित, इसका लाभ उठा सके। इंदिरा के नेतृत्व में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी उन्मूलन और ग्रामीण विकास योजनाएं इस समाजवादी दृष्टिकोण का हिस्सा थीं। संविधान में इस शब्द को जोड़कर उन्होंने इसे एक स्थायी और संवैधानिक आधार दिया। विरोध की जड़ें कई स्तरों पर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाते समय समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में शामिल नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि संविधान तटस्थ रहे। उनके लिए संविधान सामाजिक और आर्थिक बदलाव का उपकरण था, न कि किसी विचारधारा का प्रचारक। आलोचकों का कहना है कि इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को जोड़कर अपनी सरकार की समाजवादी नीतियों को संवैधानिक समर्थन देने की कोशिश की, जो आपातकाल जैसे अलोकतांत्रिक कदमों के साथ विरोधाभासी थी। धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी सवाल उठे। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब 'सर्वधर्म समभाव' रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे पश्चिमी 'सेक्युलरिज्म' से जोड़कर देखते हैं, जो धर्म को सार्वजनिक जीवन से अलग करता है। हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का मानना है कि यह शब्द बहुसंख्यक हिंदू संस्कृति को कमजोर करता है। दूसरी ओर, अल्पसंख्यक समुदाय इसे अपनी सुरक्षा का आधार मानते हैं। इस तरह, धर्मनिरपेक्षता एक ध्रुवीकृत मुद्दा बन गया। समाजवाद पर भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे आर्थिक सुधारों के खिलाफ मानते हैं, जो 1991 में शुरू हुए। वे कहते हैं कि समाजवाद का शब्द अब प्रासंगिक नहीं, क्योंकि भारत ने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया है। दूसरी ओर, समाजवादी विचारकों का कहना है कि यह शब्द संविधान को सामाजिक न्याय का दिशा-निर्देश देता है। आज, जब लोग इन शब्दों का विरोध करते हैं, तो वे इंदिरा गांधी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। क्या यह वास्तव में देशहित में था या सत्ता को मजबूत करने की रणनीति? बाबा साहब का संविधान समावेशी था, लेकिन क्या इन शब्दों ने उसकी मूल भावना को बदला? यह बहस भारत के भविष्य को भी प्रभावित करती है, क्योंकि यह तय करती है कि हमारा संविधान किस विचारधारा को अपनाएगा। धर्मनिरपेक्षता एकता का आधार धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक प्रयास था। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। यह शब्द संविधान में जोड़कर इंदिरा ने यह सुनिश्चित किया कि भारत की एकता और अखंडता को कोई धार्मिक या सांप्रदायिक शक्ति कमजोर न कर सके। यह विशेष रूप से उस समय महत्वपूर्ण था, जब सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव देश के लिए चुनौती बन रहे थे। 42वां संशोधन और इंदिरा गांधी के इस कदम की आलोचना भी हुई। कुछ लोगों का मानना था कि यह संशोधन आपातकाल के दौरान लागू किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था।

मेष राशिः आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, घर में ख़ुशी भरा माहौल रहेगा। आज आपके घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, परिवार में चहल- पहल बनी रहेगी। आज आप जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। छात्र जीवन से संबधित समस्या का समाधान होगा, सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा।

वृष राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आपको सगे-संबधियों से शुभ समाचार मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, बच्चों से स्नेह मिलेगा। व्यापार में धन लाभ होगा, अत्यधिक खर्च से आज आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबधी समस्या दूर होगी, जिससे आज आप अपने काम को दोगनी रफ्तार से करेंगे। देवी लक्ष्मी की कृपा से रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। अविवाहित व्यक्तियों के लिए आज का दिन खास है, आज आपको एक अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिलने की संभावना बन रही है।

मिथुन राशिः आज का दिन आपके लिए उत्तम साबित होगा। आज आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आपके बिगड़े काम बनेंगे। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वालों को आज बढ़िया डील मिलेगी। रिश्तो में चल रही अनबन में सुधार होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, आज उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको इलेक्ट्रोनिक बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, बच्चों से जुडी समस्या का समाधान मिलेगा। अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को आज अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा।

सिंह राशिः आज का दिन आपके लिए मिला – जुला रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टि से आपके लाभ की स्तिथि अच्छी बनी रहेगी। आज आपकी दिनचर्या में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। जमीन – जायदाद से जुड़े किसी मसले का समाधान हो सकता है। सामाजिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत होगी, जिससे राजनीति में आप आगे बढ़ेंगे।

कन्या राशिः आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। नौकरी का इन्तजार का कर रहे व्यक्तियों को आज बढ़िया ऑफर मिल सकता है। आज आपको किसी व्यक्ति से धन की प्राप्ति होगी। सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले लोग आज नये आयाम को स्थापित करेंगे।

तुला राशिः आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा, परिवार में खुशियां बनी रहेगी। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे , दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा। आज आपकी रूचि अध्यात्म में ज्यादा रहेगी, जिससे आज आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आज आप लोग किसी नये काम की शुरुआत कर सकते है। शिक्षकों को अपने सीनियर से मान – सम्मान की प्राप्ति होगी।

वृश्चिक राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज आप अपना ज्यादा समय पढ़ने-लिखने में बिताएंगे। हास्य कलाकारों को आज अपनी कला को निखारने का अच्छा अवसर मिलेगा। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज उनको बढ़िया ऑफर मिलेगा। व्यापार में धन लाभ होगा, पारिवारिक स्तिथि अच्छी रहेगी। महिलाओं के लिए आज का दिन खास होने वाला है, आज आप अपने लिए समय निकालेंगी।

धनु राशिः आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। सोने-चांदी का बिजनेस करने वालों को आज बड़ा धन लाभ होगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा, बच्चों के साथ पिकनिक मनाने कहीं बाहर जा सकते है। विदेश में रह रहे व्यक्तियों को घर आने का मौका मिलेगा। आज आप समय का सदुपयोग करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। शादीशुदा लोगों को आज ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा।

मकर राशिः आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आज आपको अचानक किसी व्यक्ति के माध्यम से बड़ा धन लाभ होगा। जिससे आपकी जिन्दगी बदल जाएगी, आप सोच में पड़ जायेंगे कि ये सब कैसे हो गया। रिश्तों में मधुरता आएगी, बच्चों के प्रति सवेंदनशील रहेंगे। आज आपमें एक अलग ही उर्जा का संचार होगा, रोज की अपेक्षा आज आप बेहतर स्थिति में होंगे। ड

कुम्भ राशिः आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको व्यापार में धन लाभ होगा , भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक स्तिथि में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी , बच्चों के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हए व्यक्तियों को आज पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।

मीन राशिः आज का दिन आपके लिए मिला – जुला रहने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार में लाभ की स्तिथि ठीक रहेगी। रिश्तों में चल रही अनबन में सुधार होगा, घर – परिवार में ख़ुशी बनी रहेगी। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। आज ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे , सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, संतुलित भोजन ग्रहण करें।

जलवायु क्षेत्र में भारत की ग्यारह वर्षों की प्रगति

भूपेंद्र यादव

मानव द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2011-20 के दशक में पृथ्वी का तापमान, पूर्व-औद्योगिक काल (1850-1900) की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। साथ ही, विकसित देश वैश्विक कार्बन बजट में असंगत हिस्सेदारी रखने के बावजूद जलवायु कार्रवाई को गति देने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करने के प्रति इच्छुक नहीं दिखाई देते। इस वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत के 'सर्वे भवन्तु सुखिनः के प्राचीन वैदिक सिद्धांत ने सहस्राब्दियों से मानव सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्व की चुनौती से जूझ रही है, तो जलवायु प्रबंधन के प्रति भारत की कालातीत वैदिक ज्ञान की प्रतिध्वनि विश्व को मार्ग दिखा रही है। एक ओर, वैश्विक समुदाय अक्सर जलवायु परिवर्तन से उपजी तापमान वृद्धि, अनियमित मौसम पैटर्न और आपदाओं में वृद्धि जैसी Óअसुविधाजनक सच्चाइयोंÓ में उलझा हुआ है। दूसरी ओर, भारत ने 'सुविधाजनक कार्रवाईÓ के दर्शन को सामने रखा है। हमारे सभ्यतागत लोकाचार में निहित इस दृष्टिकोण ने पिछले ग्यारह वर्षों में भारत को एक कर्तव्यनिष्ठ वैश्विक जलवायु नागरिक में बदल दिया है।

अथर्ववेद का एक श्लोक है,

यत् किञ्च पृथिव्यां पृथिवीमनुत्तं हितं चेद् तत् तवायतु।

मा नः पृथिव्याः परं हिंसिष्ठाः।

पृथ्वी का जो कुछ भी हम खनन करते हैं, उसे जल्दी से भरने दें, हम पृथ्वी के प्राण-तत्वों पर आघात न करें और न ही उसके हृदय को क्षति पहुंचाएं। यह श्लोक आधुनिक जलवायु विज्ञान से हजारों साल पहले के पुनर्निर्माण पर आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों को दर्शाता है। इस प्राचीन ज्ञान को जलवायु कार्रवाई के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर आधारित समकालीन नीतिगत ढाँचों में पिरोया गया है, जिससे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कार्रवाई का एक अनूठा तालमेल बना है।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, 2014 में पदभार ग्रहण करने के कुछ सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सरल लेकिन दूरगामी प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से अपनी जलवायु प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। पर्यावरण और वन मंत्रालय में 'जलवायु परिवर्तनÓ को जोड़कर, उन्होंने जलवायु कार्रवाई को क्षेत्र-संबंधी चिंता के सीमित दायरे से निकालकर शासन की प्राथमिकता में ला दिया। 2015 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का निर्माण इस प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है, जिसके द्वारा राज्यों को जलवायु संकट से निपटने से संबंधित संसाधन प्रदान किए जाते हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के जलवायु परिवर्तन विभाग स्थापित करके इस कदम का समर्थन किया, जिससे जलवायु कार्रवाई की एक संघीय व्यवस्था तैयार हुई। 2015 में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने वैश्विक जलवायु वार्ता में अग्रणी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री खुद पेरिस गए और पेरिस समझौते को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे धरती के संरक्षण में भारत की उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई। ऐसे देशों के विपरीत, जो जलवायु प्रतिबद्धताओं को बोझ के रूप में देखते हैं, भारत ने इसी वर्ष पेरिस में आयोजित कॉप-21 में अपने पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करके ठोस कार्रवाई का प्रदर्शन किया। यह देश की घरेलू अनिवार्यताओं और अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों द्वारा निर्देशित वैश्विक समुदाय के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रकटीकरण था। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय यानी 2015 में ही एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का गठन हुआ, जो लगातार मजबूत होता गया और आज 120 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। इस गठबंधन ने सौर ऊर्जा संपन्न देशों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधानों पर सहयोग करने हेतु एक मंच तैयार किया है। नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) को दिए गए प्रोत्साहन से, इसकी स्थापित क्षमता 2014 के मात्र 76 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में 220 गीगावाट हो गई है और 2030 तक इसके 500 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है। स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत की बात करने तो हम आरई में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर हैं। एक दशक में यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। सरकार द्वारा अपनी कई योजनाओं के माध्यम से परिवर्तनकारी जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता को गति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016) से लाखों महिलाओं को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मिला, जो दर्शाता है कि जलवायु कार्रवाई का सामाजिक न्याय के साथ तालमेल कैसे बिठाना चाहिए। पीएम-कुसुम योजना (2019) ने किसानों को सौर ऊर्जा समाधानों के जरिये सशक्त बनाया, वहीं रूफटॉप सौर कार्यक्रम से पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी आयी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) की घोषणा की, जिसकी औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त, 2019 को हुई थी। इससे आपदा-रोधी अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने में एक वैश्विक साझेदारी का निर्माण हुआ। स्वीडन के साथ साझेदारी में लीडआईटी (उद्योग में बदलाव के लिए नेतृत्व समूह) बनाया गया, जो जलवायु लक्ष्यों के लिए औद्योगिक बदलाव के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सौर विनिर्माण (2020) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता मजबूत हुई, आयात पर निर्भरता कम हुई और एक मजबूत स्वदेशी सौर इकोसिस्टम का निर्माण हुआ। 2021 में ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 में भारत ने देश के जलवायु परिदृश्य को और मजबूत करते हुए ऐतिहासिक घोषणाएँ कीं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने वक्तव्य में भारत के महत्वाकांक्षी अभियान पंचामृत की घोषणा की गई। पंचामृत यानी पाँच अमृत तत्व, जिसमें जलवायु प्रतिबद्धता को बढ़ाना और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना शामिल है। इसी संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ़ - पर्यावरण के लिए जीवनशैली की शुरुआत की, ताकि वैश्विक स्तर पर नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ़ सामूहिक लड़ाई में शामिल किया जा सके। इस ऐतिहासिक प्रतिबद्धता ने भारत को विकासशील देशों के बीच जलवायु नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। 2 नवंबर, 2021 को ग्लासगो में कॉप 26 के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने आईआरआईएस (सुदृढ़ द्वीप देशों के लिए अवसंरचना) लॉन्च किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका, मॉरीशस और यूके के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम से जलवायु-संवेदनशील देशों के प्रति वैश्विक एकजुटता प्रदर्शित की गई। भारत ने 2022 में अपने एनडीसी को परिवर्तित करते हुए उसमें संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर स्वस्थ और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक गुणात्मक लक्ष्य के रूप में मिशन लाइफ को शामिल किया। इसी क्रम में, नवंबर 2022 में भारत ने अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडी) प्रस्तुत की, जिसमें 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के साथ-साथ सतत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। इसी वर्ष राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ हुआ, जिससे भारत हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा, जो ऊर्जा स्वतंत्रता और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की हमारी दृष्टि के अनुरूप है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

कोई भी डूबता हुआ इन्सान यह नहीं जान सकता कि कौन-सी बूंद उसकी आखिरी सांस साबित होगी। -निकोलस स्पार्क्स

गहरे पानी में डूबने का भय वही महसूस कर सकता है, जिसने इसका सामना किया हो। *द गार्जियन* के स्तंभकार क्रिस ब्रॉटन बेहतरीन तैराक भी हैं। उनका यह लेख उनके डूबने के अनुभव के बारे में है। कुछ ऐसा ही डर जॉर्ज ऑरवेल ने भी महसूस किया था, जिसकी छाया से उनका कालजयी उपन्यास *1984* भी बच नहीं पाया था।

डूबने का डर

क्रिस ब्रॉटन
(स्वतंत्र लेखक, द गार्जियन)

सांस लेने के लिए बेचैन मैं इधर-उधर हाथ-पैर मारता रहा। ठीक उसी समय अगली बड़ी लहर मेरे सिर के ऊपर से गुजरी और मुझे वापस नीचे धकेलने लगी। हर बार जब भी मैं पानी के ऊपर आने की कोशिश करता, लहरें मुझे नीचे की तरफ घसीट रही थीं।

मैं उस सप्ताहांत अटलांटिक में कभी पैर नहीं रखना चाहता था। मैंने उत्तरी कॉर्नवाल तट के पास रिप्टाइड्स के बारे में सुना था, जबकि मैं पूर्वी ससेक्स में अपने घर के पास शांत पानी में तैरने का आदी था। हालांकि, मेरे जीजा एक उत्साही तैराक थे और उन्होंने मुझे मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली सुबह, मुझे एक वेटसूट पहनाया गया और पानी के किनारे ले जाया गया। ज्यादातर पहली बार सर्फ करने वालों की तरह, मैंने जल्द ही तय कर लिया कि मैं स्वाभाविक तैराक हूं, तथा अपने हाथों और घुटनों के बल पर तीन बड़ी लहरों पर सवार हो गया।

पानी की धारा बहुत ज्यादा तेज थी और मुझे अचानक घबराहट होने लगी- शायद मुझे उन्हें चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए था। लेकिन उत्साह ने जीत हासिल की, और जब हम अगले दिन तट से दूर एक छोटी खाड़ी में गए, तो मैं फिर से पानी में उतरने के लिए उत्सुक था। जैसे-जैसे दिन की रोशनी कम होने लगी, मुझे लगा कि घर लौटने से पहले मुझे एक आखिरी बार डुबकी लगानी चाहिए। शाम होने लगी थी तथा लहरें और भी तेज हो गई थीं, लेकिन किनारे से देखने पर वे अब भी हानिरहित लग रही थीं। मैंने छलांग लगाई और आगे बढ़ गया। पहले तो मैं आश्वस्त था, लेकिन जब मैं अपनी गहराई से बाहर निकला, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। समुद्र की लहरें मेरे पैरों को नीचे की तरफ खींच रही थीं, और सतह के नीचे छिपी चट्टानें मेरे घुटनों और कोहनी को छू रही थीं, क्योंकि मैं तट पर वापस जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक बड़ी लहर ने मुझे अपनी ओर खींचा और फिर मुझे समुद्र तल पर उछाल दिया। सांस लेने के लिए बेचैन मैं इधर-उधर हाथ-पैर मारता रहा। फिर धारा ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और मैं ऊपर चला गया। लेकिन ठीक उसी समय अगली बड़ी लहर मेरे सिर के ऊपर से गुजरी और मुझे वापस नीचे धकेलने लगी थी। हर बार जब भी मैं पानी के ऊपर आने की कोशिश करता, लहरें मुझे नीचे की तरफ घसीट लेती थीं। तब तक मैं पूरी तरह से पस्त होकर थक चुका था, लेकिन अब भी मैं गहराई से बाहर नहीं निकल पाया था। इस बीच मैंने काफी पानी निगल लिया था, समुद्र तट पर पार्टी कर रहे लोगों की तरफ मैंने पागलों की तरह हाथ हिलाया। वे बैग पैक कर रहे थे और बातें कर रहे थे, मेरी ओर कम ध्यान दे रहे थे। एक या दो बार, किसी ने वापस हाथ हिलाया। उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि मैं लहरों में गोते लगा रहा हूं; लहरा रहा हूं, लेकिन डूब नहीं रहा हूं।

मुझे लगा कि मैं वास्तव में डूबने वाला था और किसी को पता नहीं था। मुझे अकेलेपन और अलगाव की तीव्र भावना का अनुभव हुआ, क्योंकि एक और लहर ने मुझे नीचे धकेल दिया। मैंने उन सभी मूर्खतापूर्ण जोखिमों के बारे में सोचा, जो मैंने बिना किसी परिणाम पर विचार किए उठाए थे। अपने काम में, मैंने बहुत से लोगों का साक्षात्कार लिया था, जो मौत के करीब की स्थितियों में फंसे थे; कुछ ने डर और घबराहट का उल्लेख किया था, तो कुछ ने हार मानने की भावना का। मैं असहाय महसूस कर रहा था। डर के बजाय, मैंने दुख का अनुभव किया : जो काम आपको पसंद है, उसे करते हुए मरना ठीक है, लेकिन यह मेरे जीवन की सबसे कम आनंददायक तैराकी थी। जैसे-जैसे मैं लहरों से जूझ रहा था, मेरे सीने के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द उठा, जो नीचे और अंदर की तरफ फैल रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे फेफड़े और मेरा दिल काम करना बंद कर रहे हैं। वापस सतह पर आकर मैंने फिर से हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं उठा सका तथा दर्द और असहनीय हो गया। लेकिन मैंने पाया कि मैं सांस लेने में सक्षम हूं, लेकिन इससे दर्द और भी बढ़ गया। हालांकि, अगली लहर ने मुझे कुछ राहत प्रदान की और मुझे किनारे की ओर ले गई। मेरे पैरों को आखिरकार सहारा मिला और मैं आगे की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा, मेरा दाहिना हाथ बगल में लटक रहा था। मेरे जीजा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह मुझे समुद्र तट पर ले जाने के लिए उथले पानी की तरफ दौड़े। उन्होंने कहा, 'तुम्हारा कंधा उखड़ गया है।' मैं तौलिया लपेटे समुद्र तट पर बैठा कांप रहा था। किसी ने मुझे कॉफी लाकर दी, लेकिन मैं ठंड से ज्यादा सदमे से पीड़ित था। मैं समुद्र से बचकर निकल आया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सूखी जमीन पर डूब रहा हूं। मैं एंबुलेंस में किसी तरह गैस और हवा लेने में कामयाब रहा। अस्पताल में एक घबराए हुए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने मेरे कंधे को वापस अपनी जगह पर लाकर दर्द को कुछ हद तक कम कर दिया। महीनों की फिजियोथेरेपी ने क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को तो ठीक कर दिया, लेकिन अब छोटी-छोटी लहरें भी मुझे डर और आशंका से भर देती हैं।

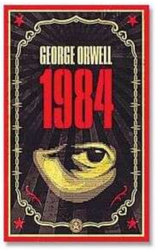

थलासोफोबिया और जॉर्ज ऑरवेल

जॉर्ज ऑरवेल का समुद्र के साथ बहुत दर्दनाक रिश्ता था। अगस्त 1947 में, जब वह उन्नीस सौ चौरासी (प्रकाशन वर्ष 1949) उपन्यास लिख रहे थे, तो वह अपने छोटे बेटे, भतीजे और भतीजी के साथ मछली पकड़ने के लिए स्कॉटिश हेब्रीडीस के जुरा द्वीप पर गए थे। ज्वार-भाटे के आने की सही जानकारी न होने के कारण वापसी के दौरान ऑरवेल ने गलती से नाव को तेज लहरों के बीच डाल दिया। भंवर में फंसकर नाव पलट गई और ऑरवेल एवं उनके परिजन पानी में गिर गए। हालांकि, वे लोग उस दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। इस घटना को ऑरवेल ने उसी शाम अपनी डायरी में बेहद उदासीनता से दर्ज किया। 1984 को आम तौर पर पानी में डूबने के डर से नहीं जोड़ा जाता। फिर भी यह डूबते जहाजों, डूबते लोगों और समुद्र में डूबने के डर से भरा हुआ है।

जब मैं किशोर हुआ, तभी प्रथम विश्वयुद्ध के 'अत्याचार की कहानियों' के बारे में पढ़ा। पूरे युद्ध में किसी भी चीज ने मुझे इतना प्रभावित नहीं किया, जितना कि कुछ साल पहले 1912 में टाइटैनिक के डूबने ने किया।
-ऑरवेल, माई कंट्री राइट ऑर लेफ्ट (1940) में

उपन्यास के नायक, विंस्टन स्मिथ को एक दुःस्वप्न बार-बार दिखता है, जिसमें वह अपनी खोई हुई मां और बहन को डूबते हुए जहाज के सैलून में फंसा हुआ देखता है। उन्हें 'हर मिनट गहरे डूबते हुए' देखना विंस्टन को बचपन के उस पल की याद दिलाता है, जब उसने मां के हाथ से चॉकलेट चुराई थी। ये पानी भरी कब्रें बताती हैं कि विंस्टन अपराधबोध में डूब रहा है।

जल के संदर्भों से भरे इस उपन्यास के अधिकांश चौंकाने वाले प्रसंगों में हताश लोगों के डूबने या डूबते समुद्री जहाजों पर आसन्न मृत्यु का सामना करने की कल्पना की गई है। हालांकि, इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि जॉर्ज ऑरवेल को थलासोफोबिया (गहरे पानी का डर) था, लेकिन उनके लेखन, विशेष रूप से 1984 में पानी से संबंधित कल्पनाओं के प्रति उनका आकर्षण और प्रयोग दिखता है, जो अक्सर एक भयावह और घुटन भरे तरीके से होता है, जिसे गहरे पानी से संबंधित उनकी अपनी चिंताओं की खोज के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

राहु जब चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा, तो वह भगवान शंकर की शरण में पहुंच गया। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर रखकर चंद्रदेव की रक्षा की। इसके बाद भगवान शिव स्वयं 'चंद्रशेखर' कहलाए।

शिव के मस्तक पर कैसे पहुंचा चंद्रमा

देवता और असुर, दोनों ने मिलकर महासागर का मंथन किया था। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन कार्य अत्यंत कठिन था, जिसमें दोनों पक्षों को समान प्रयास करना पड़ा। मंथन से दिव्य वस्तुएं और रत्न समुद्र से प्रकट हुए, जैसे-कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि और अप्सराएं। अंत में लक्ष्मी जी प्रकट हुईं, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनीं।

धूप आने दो

परंतु देवता और असुर, दोनों की दृष्टि एक लक्ष्य पर थी और वह था अमृत, क्योंकि उसे पीने वाला अमर हो जाता। आखिर वह क्षण आ ही गया। समुद्र से एक तेजस्वी, दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान धन्वंतरि थे, जो अपने हाथों में अमृत-कलश लेकर समुद्र में से निकले थे। वे न केवल आयुर्वेद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बल्कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी।

देवता कुछ कर पाते, इससे पहले वृषपर्वा नामक एक दैत्य ने चालाकी से अमृत-कलश छीन लिया और उसे लेकर पाताल लोक की ओर भाग गया। देवता भी पाताल लोक पहुंचे और दैत्यराज बलि से अमृत वापस मांगा। बलि मुस्कराकर बोला, 'हे देवताओ! तुम लोगों को समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, और बहुमूल्य रत्न मिल चुके हैं। असुरों को केवल अमृत चाहिए था।' **निराश देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताया।**

● विष्णु मुस्कराए और बोले, 'घबराओ मत। मैं योगमाया से दैत्यों को मोहित कर अमृत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा।' यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अत्यंत सुंदर, मोहक स्त्री का रूप धारण किया और असुरों के पास पहुंच गए।

उधर, पाताल में असुरों में अमृत बांटने को लेकर परस्पर विवाद छिड़ चुका था। तभी वहां मोहिनी प्रकट हुईं। उनका रूप इतना सुंदर था कि सभी दैत्य उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दैत्यराज बलि ने विनम्रता से कहा, 'हे देवी! हमारे बीच अमृत वितरण का झगड़ा है, कृपया आप इसे उचित रूप से बांट दीजिए।'

मोहिनी मुस्कराईं और बोलीं, 'स्त्रियों पर विश्वास करना मूर्खता है, क्योंकि वे माया, छल और निर्भीकता के लिए विख्यात होती हैं। फिर भी यदि तुम कहते हो, तो मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन यह निर्णय सोच-समझकर लो।' दैत्यों ने मोहिनी पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया। मोहिनी ने सुझाव दिया, 'आज अमृत को सुरक्षित रखो, व्रत रखो और कल सुबह शुद्ध होकर अमृत को ग्रहण करना। सच्ची भक्ति वही है, जिसमें त्याग होता है।' असुरों ने मोहिनी की बात मान ली।

अगले दिन सभी दैत्य स्नान आदि करके तैयार होकर पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी अमृत-कलश लेकर आईं। तभी देवता भी वहां आ पहुंचे। मोहिनी ने मुस्कराकर असुरों से कहा, 'ये लोग तुम्हारे अतिथि हैं। धर्म के अनुसार, *अतिथि देवो भवः*, इसलिए इन्हें भी अमृत का भाग मिलना चाहिए।' दैत्यों ने यह बात भी मान ली।

मोहिनी ने सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। एक-एक कर सब देवताओं ने अमृत का सेवन कर लिया। तभी राहु नाम का एक दैत्य चुपचाप देवताओं की पंक्ति में आ बैठा और अमृत पीने का प्रयास करने लगा। परंतु सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु को संकेत करके बता दिया। विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया।

अमृत की कुछ बूंदें पी लेने से राहु के सिर का भाग अमर हो चुका था। वह उड़कर आकाश में जा पहुंचा। लेकिन उसे सूर्य और चंद्रमा पर क्रोध आ रहा था। इसलिए वह चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा। चंद्रमा भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंच गया। तब शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देकर उसकी रक्षा की। तभी राहु वहां पहुंचा और शिव से बोला, 'हे प्रभु! चंद्रमा मेरा ग्रास है। कृपया मुझे लौटा दें।' शिव मुस्कराए और बोले, 'मैंने चंद्रमा को शरण दी है, इसलिए अब यह मेरे द्वारा रक्षित है।' इस तरह चंद्रमा को शिव के मस्तक पर स्थान मिला और शिव स्वयं 'चंद्रशेखर' कहलाए।

अलब्धमीहेद्धर्मेण
लब्धं यत्नेन पालयेत्।
पालितं वर्धयेन्नीत्या
वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्॥

जो प्राप्त नहीं है, उसे विधिपूर्वक अर्जित करें। जो प्राप्त है, उसकी रक्षा करें। उस रक्षित वस्तु को नैतिक उपायों से बढ़ाएं और योग्य व्यक्तियों को सौंप दें।
-याज्ञवल्क्यस्मृति 1.316

प्रस्तुति : **शास्त्री कोसलेंद्रदास**

ट्रंप, गुस्सा और मनोविज्ञान

जियोफ बीट्टी
मनोवैज्ञानिक

ट्रंप के गुस्से और त्वरित फैसलों के पीछे उनका मनोविज्ञान समझना मुश्किल नहीं है। बात इतनी है कि वह जो पाना चाहते हैं, उसकी राह में कोई बाधा उन्हें बर्दाश्त नहीं।

ईरान-इस्राइल के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने काफी उग्र बयान दिया। असल में, संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्राइल और ईरान, दोनों ने उसका उल्लंघन कर दिया। इसलिए ट्रंप बेहद गुस्से में थे और यह उनकी भाषा से भी जाहिर होता है। 1930 के दशक में मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामक व्यवहार के संबंध में एक परिकल्पना विकसित की थी, जिसके मुताबिक, जब किसी व्यक्ति का लक्ष्य किसी तरह से बाधित होता है, तो यह कुंठा की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आक्रामकता पैदा होती है।

आक्रामकता को कुंठा की इस अप्रिय स्थिति को दूर करने का एक 'स्वाभाविक' तरीका माना जाता था। अगले कुछ दशकों में, इस परिकल्पना को ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने जटिल मानवीय व्यवहार का सरलीकरण माना। इसने हताशा और आक्रामकता के बीच एक सीधा संबंध मान लिया, और अन्य सभी परिस्थितिजन्य और संज्ञानात्मक कारकों को नजरअंदाज कर दिया, जो हस्तक्षेप कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि मनुष्य उससे कहीं ज्यादा जटिल है, जितना कि हम समझते हैं। वह अपनी कुंठाओं से निपटने के दूसरे तरीके खोज लेता है। वह समाधान खोजने के लिए अपनी तर्कसंगत सोच प्रणाली का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब लोग राष्ट्रपति ट्रंप को इस तरह उग्र रूप में देखते हैं, तो उन्हें झटका लगता है। दूर से देखने पर तो यही लगता है कि बहुत जल्दी निर्णय लेना ट्रंप का तरीका है। अपने राष्ट्रपति पद और अपने व्यावसायिक कॅरिअर, दोनों में वह तत्काल कार्रवाई को प्राथमिकता देते दिखे हैं। यही कारण है कि वह अक्सर अपना मन बदल लेते हैं। उनके निर्णय प्रबल भावनाओं से प्रेरित होते हैं। घटनाओं, विरोधियों और मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया अक्सर भावुक और भावनात्मक होती है। इससे निर्णय अनुचित रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ट्रंप की निर्णय लेने की शैली में तत्कालिकता और भावनात्मक दृढ़ विश्वास पर जोर दिया जाता है, जो समर्थकों को एकजुट करने और निर्णायकता की भावना पैदा करने में प्रभावी हो सकता है। हालांकि, यह अप्रत्याशित परिणामों को भी जन्म दे सकता है। कई लोगों का मानना है कि ट्रंप की निर्णय लेने की शैली उच्च व्यावसायिक दबाव की उनकी पृष्ठभूमि को दर्शाती है, जहां ऐसे प्रतिस्पर्धी वातावरण में त्वरित निर्णय और सहज ज्ञान लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन युद्ध की दुनिया में फैसले लेते समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं और यही उनकी शैली है।

द कन्वर्सेशन से

अध्ययन कक्ष

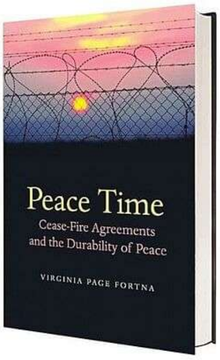

पीस टाइम
सीजफायर एग्रीमेंट एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ पीस
लेखिका : वर्जिनिया पेज फोर्टना
प्रकाशक : प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस
मूल्य : 5,031 रुपये (पेपरबैक)

क्या सीजफायर होते ही उल्लंघन के लिए हैं

युद्धों की आग को शांत कर कामयाब सीजफायर कैसे किए जाएं, यह शीतयुद्ध के बाद का सबसे ज्वलंत और अनसुलझा प्रश्न रहा है। यह क्लासिक बेस्टसेलर किताब जिस को-ऑपरेशन थ्योरी की बात करती है, वह वर्तमान संदर्भों में जटिल होते अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मद्देनजर मजबूत सीजफायर समझौतों का आधार हो सकती है।

कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि युद्धविराम यानी सीजफायर के समझौते कभी-कभी तो सालों तक चल जाते हैं, जबकि कभी-कभी अपनी घोषणा के साथ ही टूटने लगते हैं। ईरान-इस्राइल के हालिया युद्ध के दौरान भी हमने देखा कि अमेरिका द्वारा सीजफायर की घोषणा के बाद भी दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आग बरसाते रहे। युद्ध के बाद शांति कैसे बनाए रखी जाए, यह दरअसल शीतयुद्ध के बाद के युग के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। लेकिन इसके बावजूद यह युद्ध और शांति के अध्ययनों में सबसे कम खोजे गए मुद्दों में से एक है। आखिर क्यों युद्धों से जुड़े इतने महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं की गई?

पेज फोर्टना की यह क्लासिक मानी जाने वाली किताब *पीस टाइम* विभिन्न देशों के बीच सीजफायर के कामयाब या फिर नाकामयाब होने का पहला व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। वह यह तर्क देने के लिए कि इन सीजफायर समझौतों के जरिये युद्ध और शांति के लिए प्रोत्साहनों का असर कम करके, अनिश्चितताओं को कम करके और युद्धकारी दुर्घटनाओं को रोकने या प्रबंधित करने में मदद करके शांति बनाए रखी जा सकती है, सहयोग सिद्धांत (को-ऑपरेशन थ्योरी) विकसित करती है। अपने इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए यह किताब पहले निर्णायक जीत और संघर्ष के अतीत जैसे कठिन कारकों की खोज करती है, जो शांति की बुनियादी संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह किताब इस पर भी विचार करती है कि क्या सबसे मुश्किल या फिर सबसे आसान मामलों में ही मजबूत सीजफायर लागू किए जाने की संभावना होती है। किताब अतीत में हुए सीजफायरों को आधार बनाकर साबित करती है कि ये समझौते मायने रखते हैं। किताब बताती है कि कुछ युद्धों के बाद स्थायी शांति पाना दूसरे युद्धों की तुलना में अधिक मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी स्थितियों वाले देश ही शांति प्रयासों में सबसे अधिक निवेश करते हैं। अमूमन ये प्रयास कारगर साबित होते हैं और युद्ध के जोखिम को काफी कम कर देते हैं। किताब यह भी कहती है कि विसैन्यीकृत क्षेत्र, विवाद समाधान आयोग, शांति स्थापना और बाहरी गारंटी जैसे तंत्र सबसे घातक दुश्मनों के बीच भी शांति बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से भू-राजनीतिक युद्धों की बढ़ती संख्या में शांति के लिए सीजफायर का उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन हम वास्तव में इस बारे में बहुत कम जानते हैं कि युद्ध प्रबंधन की यह रणनीति कितनी प्रभावी है। कुल मिलाकर, यह पुस्तक नीति निर्धारकों, शांति स्थापना में लगे नेतृत्वों और युद्ध एवं शांति जैसे विषयों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विचारोत्तेजक एवं पठनीय कृति है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

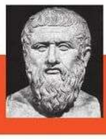

जिस समाज में कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता है, वहां लोगों में सिर्फ अच्छे संस्कार पाए जाते हैं। - प्लेटो, महान दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

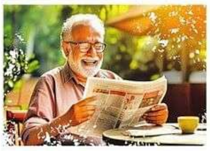

अखबार से दोस्ती रखना,
चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है,
चिढ़ता नहीं है,
सुबह आएगा, पास बिठाना थोड़ी देर,
चाय पीना साथ में...

ऐनक लगा के हेडमास्टर
सूरज देखे सबको ताक के,
डर कर भागा एक छोटा बादल,
आसमान की क्लास से...

331 पारियां और 15 हजार रन

भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने 2007 में आज के ही दिन वन डे इंटरनेशनल मैच में सबसे कम पारी में 15 हजार रन बनाने का कारनामा किया था। मास्टर ब्लास्टर ने 331 पारियों में 18 साल पहले यह कमाल किया था। फ्यूचर कप का यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेलफास्ट में खेला गया था। दुनिया का कोई अन्य बल्लेबाज अभी तक एक दिवसीय मैचों में इस आंकड़े को छू नहीं पाया है।

झरोखा
29 जून

सचिन ने अपने वनडे कॅरिअर में 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाए। साल 2013 में वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो गए। भारत की ओर से विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 15,000 रन बनाने वाले भारत के एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 316 पारियों में हासिल की। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर 352 परियों में 15,000 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर 361 पारियों में, वीरेंद्र सहवाग 363 और दक्षिण अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ 368 पारियां खेलने के बाद इस आंकड़े तक पहुंच पाए हैं।

■ अमरेंद्र पोद्दार, पटना

गर्मी में हम पानी की कमी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन बरसात में प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले इस अनमोल वरदान की कद्र नहीं करते। वर्षा जल के योजनाबद्ध संचयन पर हमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी।

वर्षा जल की उपेक्षा कब तक

बर्बादी नहीं संचयन जरूरी

हमारे देश में प्रतिवर्ष मुख्यतः गर्मी में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, लेकिन बरसात आने पर हम इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरी है कि वर्षा जल को इस तरह स्टोर किया जाए कि इसका उपयोग गर्मियों में किया जा सके।

चिट्ठी 1

दिल्ली को लगभग 100 एमजीडी पानी प्रतिदिन गंगा जल के रूप में उत्तर प्रदेश से आपूर्ति की जाती है, जबकि वर्षा ऋतु में लाखों घन लीटर जल हथिनी बैराज से यमुना में बहाया जाता है, जो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। अगर इस जल को पेयजल के लिए संचित किया जाए तो दिल्ली में इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

वर्षा जल का संरक्षण क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, वर्षा काल, वहां बहने वाली नदियों की क्षमता, जल उपयोग आदि पर निर्भर होना चाहिए। एक समान नियम से प्रदेशों में विरोधभास होता है। पथरीले क्षेत्र में भूमि की ढलान और वर्षा जल की मात्रा के अनुसार बड़े तालाब बनवाए जाएं, और उस पानी का उपयोग जलापूर्ति के लिए किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में चेक डैम का निर्माण किया जाए। क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को नगर पालिका क्षेत्र में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। बोरिंग में छोटे फिल्टर के माध्यम से वर्षा का जल संचित किया जाए। अभावग्रस्त क्षेत्र में घरों के नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स बनाकर पानी का संचयन किया जा सकता है। अपने देश के कई शहरों में आज भी बड़ी झीलें हैं, जिनके पानी का बहुउपयोग होता है। जगह-जगह चेक डैम बनाकर पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाया जा सकता है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं, जब अधिकांश शहर पानी की कमी की समस्या से जूझते नजर आएंगे।

■ लक्ष्मण पुंडीर, श्रीनगर गढ़वाल

अंतरिक्ष कार्यक्रमों में तेजी लानी होगी

भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में दाखिल होकर नया इतिहास रच दिया है। 41 साल बाद यह पहला मौका है, जब नासा के एक्सिओम 4 मिशन का हिस्सा बन वह अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। उनसे पहले 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी।

शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां और आयाम देगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का इस मिशन पर जाना भारतीय वायु सेना के लिए भी गौरव से कम नहीं है। यह बात सही है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अभी बहुत कुछ करना है। आने वाले समय में भारत गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। ऐसे में शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में जाने से इस मिशन को काफी अनुभव और मदद प्राप्त होगी।

चिट्ठी 2

गौर करने वाली बात है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी चुना है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मामले में चीन हमसे काफी आगे निकल चुका है। अंतरिक्ष में उसका अपना केंद्र भी है और वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। भारत को भी अपने प्रयोगों में तेजी लानी चाहिए। अंतरिक्ष की कक्षा में मानव सहित यान भेजने की क्षमता का विकास जल्द से जल्द होना चाहिए।

■ विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

युद्ध एक वैश्विक उन्माद

वैश्विक स्तर पर युद्ध के पीछे का तर्क समीक्षा की विषय-वस्तु है। रूस-यूक्रेन युद्ध दीर्घावधि के चलते अतिप्रासंगिक है। सनद रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव के समय युद्ध विराम करवाने की आत्ममंडित घोषणा कर चुके थे, जबकि युद्ध आज तक जारी है। भारत द्वारा आतंकवाद को मटियामेट करने जैसी संकल्पित सैन्य कार्रवाई में परास्त पाकिस्तान के समर्पण सहित युद्ध विराम के आग्रह को भारत द्वारा स्वीकार किए जाने का श्रेय आत्ममंडित ट्रंप की अनावश्यक अस्वीकृत दखलंदाजी का परिचायक है। ईरान समर्थित आतंकी समूहों को प्रचंड इस्राइली दंड के बाद ईरान पर हमला और फिर ईरान-इस्राइल युद्ध के निहितार्थ में भी अमेरिका की भूमिका संदेशप्रद है।

चिट्ठी 3

यदि संदेश सकारात्मक है तो पाकिस्तान पर प्यार की वजह यक्ष प्रश्न है। अमेरिका के लिए कभी हक, कभी मुशर्रफ तो कभी जिया और अब कट्टर जेहादी जनरल की मेहमाननवाजी में पलक पांवड़े बिछाए ट्रंप को दुनिया ने देखा, जबकि मुनीर तो औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं हैं। अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान की लानत-मलानत करने वाले ट्रंप आज आतंक परस्त पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहे हैं।

विश्व शांति का कथित उद्बोधक अमेरिका लगभग सभी खाड़ी देशों और मध्य पूर्व में सैन्य अड्डे क्यों बनाए है? निश्चित रूप से वर्तमान परिदृश्य में भारत को सभी क्षेत्रों में सशक्त होने के साथ अधिक सचेत होने की परम आवश्यकता है।

■ नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, रायबरेली

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

वाराणसी से जया टंडन, मेरठ से डॉ. नरेंद्र टोंक, लखनऊ से शंभू नाथ 'सार्थक', आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, कुरुक्षेत्र से मुनीष भाटिया, मोहाली से अभिलाषा गुप्ता, फिरोजाबाद से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, नई दिल्ली से नृपेन्द्र, बरेली से दिलीप कुमार गुप्ता, झाबुआ से अरविंद रावल, शाजापुर से मनमोहन राजावत, इंदौर से अमृतलाल मारू 'रवि', सूरत से कांतिलाल मांडोत।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

रेगिस्तान में एक विशाल हाथ

रेगिस्तान के बीच बना यह इन्सानी हाथ का पंजा कोई मृग मरीचिका नहीं, बल्कि सच्चाई है। आखिर रेत के बीच ही क्यों बनाया गया इसे?

जब भी रेगिस्तान की बात आती है तो सिर्फ दूर-दूर तक फैली रेत का अक्स ही मस्तिष्क में उभरता है। उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क गैर-ध्रुवीय रेगिस्तान है, लेकिन बंजर अटाकामा में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले राजमार्गों का नेटवर्क (पैन-अमेरिकन हाईवे) से गुजरने पर एक अलौकिक नजारा दिखाई देता है। रेगिस्तान के बीच में रेत से 36 फीट ऊपर उठा और सीमेंट से बना एक विशाल हाथ पर्यटकों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेता है। यह 'ला मानो डेल डेसिएर्टो' यानी 'रेगिस्तान का हाथ' है। वास्तव में, यह एक आधुनिक मूर्ति कला है।

तकरीबन 25 वर्ष पहले चिली के तांबा खनन उद्योग के केंद्र एंटोफगास्टा शहर की ओर से सैंटियागो के मूर्तिकार मारियो इराराजाबल को अटाकामा रेगिस्तान के खालीपन पर एक स्मारक बनाने के लिए कहा गया था। इस कला-कृति को इराराजाबल ने अपने देश में सैन्य शासन के दौरान अन्याय और यातना के शिकार लोगों के सम्मान में 1992 में बनाया था। यह कला-कृति एनएफएल गोलपोस्ट से भी ऊंची है। मूर्ति का आधार लोहे और सीमेंट से बना है, जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। तब से यह रूट 5 पर यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए दिलचस्प जगह बन गई है, जो पैन-अमेरिकन हाईवे का हिस्सा है।

अटाकामा रेगिस्तान के मध्य में बना यह विशाल हाथ किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष की तरह जमीन से उभरता हुआ दिखाई देता है। दुनियाभर के विभिन्न स्थानों पर इराराजाबल की ऐसी ही कई विशाल हस्त मूर्तियां मौजूद हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के नोट्रे डेम विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र एवं कला का अध्ययन किया था और बाद में पश्चिमी बर्लिन में जर्मन मूर्तिकार ओटो वाल्डेमर के साथ मूर्तिकला का अध्ययन किया।

■ रीना धीमान, शिमला

जिंदगी की पहेली सुलझाते दो सुपर स्टार

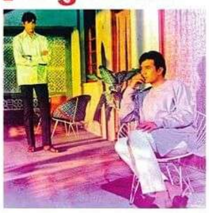

1971 में आई फिल्म 'आनंद' के गाने 'जिंदगी कैसी है पहेली...' की रिकॉर्डिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना।

■ राजन कुमार, पानीपत

छायानट

जब भट्ट और कपूर में ठनी, तब मिला 'बैजू'

बात 50 के दशक की है, जब उस समय की सुपरहिट फिल्म 'बैजू बावरा' का निर्माण हो रहा था। इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर निर्देशक विजय भट्ट और अभिनेता राज कपूर में अहम का टकराव हो गया था। दरअसल, विजय भट्ट 'बैजू बावरा' की स्क्रिप्ट लेकर राज कपूर के पास पहुंचे। कहानी उन्हें पसंद भी आई, लेकिन राज कपूर ने विजय भट्ट को कहानी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए। भट्ट इस बात पर अड़ गए कि कहानी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बाद में स्क्रिप्ट को लेकर दोनों की एक और मुलाकात हुई। राज कपूर ने कहा, "कहानी बदलो", भट्ट ने कहा, "यह नहीं होगा।" हालांकि विजय भट्ट ने राज कपूर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राज कपूर काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। निर्देशक विजय भट्ट ने उन्हें सबक सिखाने के लिए 'बैजू बावरा' में उनकी जगह स्ट्रगलर आर्टिस्ट भारत भूषण को मौका दिया। फिल्म चल निकली और हिट फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई। 'बैजू बावरा' फिल्म पूरे दो साल तक थिएटर में लगी रही थी।

■ मयंक शर्मा, लुधियाना

इंदिरा और मोदी का कार्यकाल

आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनमें इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों सत्तावादी विचारों वाले रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से हम अभी पहले से बेहतर स्थिति में हैं। इसी तरह राजनीतिक विरोध के लिए भी अधिक जगह है।

जून की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने अपने दैनिक पोस्ट में हैशटैग इमरजेंसी@11 का प्रयोग करना शुरू किया और सत्ताधारी लोगों पर गलतियों और अपराधों का आरोप लगाया। यह उस बात के विरोध में था, जिसके बारे में उन्हें मालूम था कि इस महीने के अंत में ऐसा होगा, अर्थात मोदी सरकार द्वारा इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ का आह्वान। इस हैशटैग के माध्यम से रमेश यह सुझाव दे रहे थे कि इंदिरा का आपातकाल तो दो सालों से भी कम समय तक चला था, जबकि मोदी के अधिनायकवादी शासन को तो दस साल से भी अधिक समय हो गया है। इस कॉलम में मैं व्यक्तिगत अनुभव और अकादमिक शोध, दोनों के आधार पर उनकी राजनीतिक विरासत की तुलना करने का प्रयास कर रहा हूं।

इतिहासकार के अनुसार, समय और वैचारिक संबद्धता के आधार पर अलग-अलग दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पांच उल्लेखनीय समानताएं हैं। सबसे पहले मोदी ने इंदिरा की तरह ही अपने राजनीतिक अधिकार का इस्तेमाल एक विशाल व्यक्तिवादी पंथ का निर्माण करने के लिए किया है, जिसमें वे खुद को पार्टी, सरकार और राष्ट्र का एकमात्र अवतार बताते हैं।

दूसरा, इंदिरा की ही तरह मोदी ने भी उन संस्थाओं को कमजोर करने का भरपूर प्रयास किया है, जिनकी स्वतंत्रता लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। यह इंदिरा ही थीं, जिन्होंने पहली बार 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' और 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की बात कही थी। उसी विचार को मोदी ने अपना लिया है। हालांकि इंदिरा के विपरीत मोदी ने औपचारिक आपातकाल की घोषणा तो नहीं की है, फिर भी उन्होंने सांविधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति उसी तरह की उपेक्षा दिखाई है। इंदिरा ने प्रेस को सच दबाने के लिए धमकाया, जबकि मोदी उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नौकरशाही आज 1970 के दशक की तुलना में और भी कम स्वतंत्र है, जांच एजेंसियों का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए और भी अधिक किया जा रहा है।

भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में प्रधानमंत्री को प्रथम माना जाता है। वह उस प्रकार कार्य नहीं कर सकते, जिस प्रकार सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति कर सकते हैं। हालांकि व्यवहार में इंदिरा ने सरकार चलाने के लिए परामर्शी तरीके के बजाय एकतरफा तरीका अपनाया। पूरे शासनकाल में केवल दो लोगों की सलाह को ही उन्होंने गंभीरता से लिया- पहले पीएन हक्सर और फिर संजय गांधी। मोदी के साथ भी ऐसा ही है। वह सिर्फ और सिर्फ अमित शाह पर भरोसा करते हैं। शाह भी अपने बॉस की तरह ही शासन के अपारदर्शी, सत्तावादी तरीकों के समर्थक हैं।

चौथा, इंदिरा की तरह मोदी ने भी भारतीय संघवाद को खत्म करने की कोशिश की है। इंदिरा ने गैर-कांग्रेसी दलों द्वारा चलाए जा रहे राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 को एक हथियार के रूप में उपयोग किया, वहीं मोदी ने राज्यपाल के कार्यालय को हथियार बनाकर उन्हें कमजोर किया है।

पांचवां, इंदिरा की तरह मोदी ने भी अपने शासन को मजबूत करने के लिए उग्र-राष्ट्रवाद को हवा दी है। इंदिरा की तरह उन्होंने भी पार्टी, राज्य और मीडिया का इस्तेमाल

रामचंद्र गुहा
जाने-माने इतिहासकार

कर यह दावा किया है कि केवल वे ही भारत की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस तरह के अंधराष्ट्रवाद को कथित तौर पर विदेशी ताकतों द्वारा भड़काया जाता है। इंदिरा ने तो महान देशभक्त जयप्रकाश नारायण को विदेशी एजेंट तक कह दिया था। अब भाजपा राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस से पैसे लेने का आरोप लगा रही है।

अब मैं उन अंतर के बारे में बात करता हूं, जिनमें से दो खासतौर पर महत्वपूर्ण हैं। पहला, अपने तानाशाही तरीकों के बावजूद इंदिरा ने संविधान में निहित भारत के बहुलवादी विचार को बरकरार रखा। इसके अनुसार नागरिकता को भाषा, धर्म या जातीयता के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू, जो अधिक सिद्धांतवादी और धर्मनिरपेक्ष माने जाते थे, वे कांग्रेस शासित राज्यों में किसी भी मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बना सके, वहीं इंदिरा ने चार मुस्लिमों को मुख्यमंत्री बनाया था। इंदिरा ने अपने सिख अंगरक्षकों को हटाने से भी मना कर दिया था, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी।

दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी एक बहुसंख्यकवादी हैं। वे किसी भी स्वयंसेवक की तरह देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं। भाजपा द्वारा 2014, 2019 और 2024 में लोकसभा में भेजे गए 800 सांसदों में से एक भी मुस्लिम नहीं था।

इंदिरा गांधी का यह मानना कि यह देश जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी, उन्हें बहुसंख्यकवादी मोदी से अलग करता है। आपातकाल के दौरान पहले बेटे संजय गांधी को, फिर 1980 में उनकी मृत्यु के बाद दूसरे बेटे राजीव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर उन्होंने एक खतरनाक राजनीतिक प्रथा की शुरुआत की, जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास और विरासत के विपरीत थी। महात्मा गांधी के बच्चों में से कोई भी स्वतंत्रता के बाद सांसद या मंत्री नहीं बन पाया, हालांकि उनके चारों बच्चे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए थे। इंदिरा ने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को पारिवारिक संस्था बना दिया और इसने दूसरी पार्टी के नेताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवसेना, डीएमके, अकाली और टीएमसी क्षेत्रीय गौरव के लिए उठ खड़े हुए। इसी तरह एसपी और राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी सिद्धांतों की जगह परिवारवाद के सिद्धांत के पक्षधर हैं।

मोदी के माता-पिता राजनीति में नहीं थे और मोदी के भी बच्चे नहीं हैं। चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो यह उनके प्रधानमंत्री पद के संभावित उन प्रतिद्वंद्वियों पर एक बड़ी जीत है, जो इस मुकाम पर केवल इसलिए पहुंचे हैं, क्योंकि वह राजीव और सोनिया गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते हैं। अपने दम पर राजनेता बने मोदी और वंशवादी राहुल के बीच के अंतर ने पिछले तीन आम चुनावों में भाजपा को जीत दिलाने में काफी योगदान किया है और यह अगले चुनाव में भी उनकी मदद कर सकता है। भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर उत्थान उसके प्रमुख विरोधी दलों की वंशवादी राजनीति के कारण संभव हुआ है। यह एक कड़वा सच है, जिसे हिंदू बहुसंख्यकवाद के विरोधी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वंशवादी राजनीति आपातकाल की एक विरासत है, जो वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र पर एक भयावह विरासत का प्रयोग कर रही है।

आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनमें इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों सत्तावादी विचारों वाले रहे हैं। किसका कार्यकाल सबसे खराब रहा? अभिव्यक्ति की आजादी के लिहाज से हम अभी पहले से बेहतर स्थिति में हैं। इसी तरह राजनीतिक विरोध के लिए भी अधिक जगह है। दूसरी तरफ मई 2014 के बाद हमारी सार्वजनिक संस्थाओं को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है। चुनाव आयोग के साथ टैक्स अधिकारी और नियामक एजेंसी पूरी तरह से राजनीतिक आकाओं के प्रति पहले से कहीं अधिक 'प्रतिबद्ध' हैं।

अंततः सबसे चिंता वाली बात यह है कि मोदी के शासनकाल में धार्मिक कट्टरता का जहर अधिक तेजी से फैला है। यह कट्टरता रोजमर्रा की जिंदगी में भी जमीनी सतह पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों और भाजपा के मुख्यमंत्रियों के भाषण तथा आचरण में भी यह कट्टरता तेजी से सामने आ रही है। अधिनायकवाद के साथ बहुसंख्यकवाद का यह मिश्रण नरेंद्र मोदी की शासन शैली का सबसे हानिकारक पहलू है, जिसे उनके पद से हटने के बाद भी पहले जैसा करने में दशकों लग सकते हैं।

कहां गुम हो गईं वो चिट्ठियां

डिजिटल संचार के इस युग में हमारी चिट्ठी-पत्रियां विलुप्त हो गई हैं। लोग अब ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करना पसंद करते हैं, जिससे पारंपरिक पत्रों का उपयोग बहुत कम हो गया है। अब डाकघरों से चिट्ठी-पत्री की जगह कभी-कभी कुछ सरकारी पत्र आते हैं।

आज के इस तकनीकी युग में हर संदेश बस एक क्लिक दूर है, जबकि वे दिन भी थे, जब पत्र लिखना एक कला थी। चिट्ठियां, जो किसी खास व्यक्ति के हाथों तक पहुंचती थीं, उनमें बसी भावनाएं और संवेदनाएं अनमोल होती थीं। किसी प्रियजन की चिट्ठी आते ही मन खुशी से भर जाता था, जैसे किसी ने दिल को हल्के से छू लिया हो। किसी का हाल-चाल जानने के लिए पत्र का इंतजार करना और जवाब मिलने पर उस पत्र को बार-बार पढ़ना, यह एक ऐसा अनुभव था, जिसे आज की पीढ़ी शायद ही समझ पाए। अब कहां गुम हो गई हैं वो चिट्ठियां और उन्हें लाने वाले (पोस्टमैन) डाकिया बाबू। संचार क्रांति के इस युग में अब नहीं आती कहीं से भी अपनों की चिट्ठी-पत्री। बदलते दौर में घर से जाते समय अब कोई नहीं कहता कि पहुंचते ही चिट्ठी लिखना, हाल बताना। अब कहते हैं कि कॉल कर देना।

डॉ. राजेन्द्र सिंह क्वीरा

खुला आकाश

संचार क्रांति के इस युग में अब नहीं आती कहीं से भी अपनों की चिट्ठी-पत्री। बदलते दौर में घर से जाते समय अब कोई नहीं कहता कि पहुंचते ही चिट्ठी लिखना, हाल बताना। अब कहते हैं कि कॉल कर देना। चैटिंग के इस जमाने में हमारी नई पीढ़ी पत्र-लेखन की कला से कोसों दूर हो चुकी है।

दुखद बात यह है कि चैटिंग के इस जमाने में हमारी नई पीढ़ी पत्र-लेखन की कला से कोसों दूर है।

दूसरी बात चिट्ठी-पत्रियों का दौर समाप्त होने के बाद डाकघरों ने भी समय के साथ अपना व्यवसाय बदला है। वहां अब विभिन्न सरकारी योजनाओं में जमा करने वाले खाताधारकों, आधार कार्ड बनाने और अपडेट कराने वालों एवं पार्सल/स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री आदि कराने वालों की भीड़ लगी रहती है। इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर के इस युग में स्कूलों आदि में सिखाई जाने वाली पत्र लेखन की परंपरा भी धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। एक समय वो था, जब अपनों के पास चिट्ठियां भेजी जाती थीं और उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार किया जाता था। घर के आसपास डाकिया बाबू को देखकर मन में उत्सुकता जाग जाती थी कि क्या पता, हमारी भी कोई चिट्ठी आई हो।

एक दौर वो भी था, जब पत्रों की अहमियत होती थी। लोग चिट्ठियों को संभालकर रखते थे। उस समय लोग गर्व से कहते थे- 'ये फलां रिश्तेदार की चिट्ठी है। कैसी सुंदर लिखावट है। ये फलां की चिट्ठी होगी।' आज हमारे पास वैसी कोई भी अनमोल चीज नहीं है, जिसे भविष्य में किसी को दिखाया जा सके।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

उम्मीद

भारत डोगरा

मध्य प्रदेश में गजब हो गया। सीएम के काफिले में शामिल 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। सभी गाड़ियां बंद हो गईं। अफरा-तफरी मचने के बाद नई गाड़ियां मंगाई गईं। जहां से पेट्रोल भरवाया गया, उस पंप को सील कर दिया गया है। अगर सीएम के साथ यह हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा? जिस पेट्रोल-डीजल पर आप उसके दाम के बराबर टैक्स भरते हैं, उसमें आपको पानी मिलाकर बेचा जाता है।

कृष्णकांत, पत्रकार@kkjourno

किसान संकट दूर करने की एक राह

भारत में अधिकतर छोटे किसान हैं, और हमारे विकास कार्यक्रमों की एक बड़ी चुनौती यह है कि छोटे किसानों की आजीविका टिकाऊ तौर पर मजबूत हो। यह केवल हमारे देश का मुद्दा नहीं है, विश्व स्तर पर भी एक बड़ी बहस है कि अनेक धनी देशों में भी छोटे किसानों की आजीविका क्यों संकट में जाती रही है। अमेरिका और यूके में भी किसानों और किसान-परिवारों के कृषि जमीन से हटने के चौंकाने वाले आंकड़े मिलते रहे हैं। दूसरी ओर वहां बड़ी कंपनियों का भूमि पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, और किसानों के कर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हम अपने देश की बात करें तो यहां भी किसानों के कर्ज और संकट का मुद्दा जोर पकड़ता रहा है।

इस स्थिति में यदि इस संकट से बाहर निकलने के कुछ स्पष्ट और रचनात्मक प्रयास नजर आते हैं, तो उनसे भरपूर सीखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रयास सृजन संस्था देश में लगभग 25 वर्षों से कर रही है और इसका असर 5 लाख से अधिक परिवारों तक पंहुचा है। इन प्रयासों की एक विशेषता यह है कि जो छोटे और निर्धन किसान या कमजोर वर्गों के किसान प्रायः उपेक्षित रह जाते हैं, उन पर ही इस कार्यक्रम में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रायः किसानों की चर्चा में महिला किसानों को तो भुला दिया जाता है, जबकि हकीकत देखें तो खेती-किसानी और इससे जुड़े पशुपालन में महिला किसानों का बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान है। पर्वतीय क्षेत्रों में, प्रवासी मजदूरों से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तो यह योगदान और भी बढ़ जाता है। अतः महिला किसानों और उनके योगदान की उपेक्षा किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है। जिस तरह सृजन संस्था के कार्यक्रमों में महिला किसानों को अधिक अवसर प्रदान हुए हैं, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि उनमें कितनी रचनात्मक प्रतिभा है, जो अवसर मिलने पर बहुत सुंदर परिणामों में व्यक्त होती है।

सृजन के कार्यक्रम की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि अपने अनुभवों और प्रयोगों से सीखते हुए यह निरंतर प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ा है-ऐसी कृषि की ओर जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है और गांव के अपने संसाधनों के आधार पर गोबर, गोमूत्र और थोड़े-बहुत अन्य सहज उपलब्ध उत्पादों से गांव में अपनी प्राकृतिक खाद बनाई जाती है या हानिकारक कीड़ों को दूर रखने वाले छिड़काव तैयार किए जाते हैं। अनेक किसानों को प्रेरित किया गया है कि वे अपने यहां प्राकृतिक कृषि केंद्र स्थापित करें जिसमें अतिरिक्त प्राकृतिक खाद और कीड़ों से बचाने के घोल का उत्पादन हो ताकि जो किसान इन्हें स्वयं तैयार नहीं कर सकते, वे

भारत अधिकतर किसान छोटे किसान हैं, और हमारे विकास कार्यक्रमों की बड़ी चुनौती यह है कि छोटे किसानों की आजीविका टिकाऊ तौर पर मजबूत हो। यह केवल हमारे देश का मुद्दा नहीं है, विश्व स्तर पर भी बड़ी बहस है कि अनेक धनी देशों में भी छोटे किसानों की आजीविका क्यों संकट में जाती रही है। अमेरिका और यूके में भी किसानों और किसान-परिवारों के कृषि जमीन से हटने के चौंकाने वाले आंकड़े मिलते रहे हैं। दूसरी ओर वहां बड़ी कंपनियों का भूमि पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, और किसानों के कर्ज भी बढ़ते जा रहे हैं। अपने देश की बात करें तो यहां भी किसानों के कर्ज और संकट का मुद्दा जोर पकड़ता रहा है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भरपूर प्रयास करने होंगे

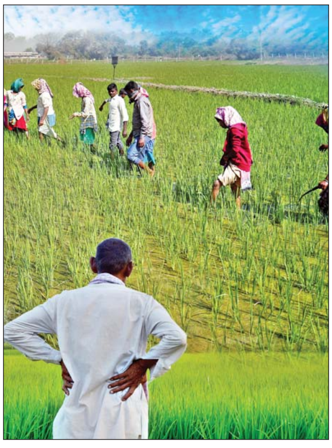

कम कीमत पर उनसे प्राप्त कर सकें। इस तरह की प्राकृतिक खेती में न केवल किसान का खर्च बहुत कम होता है अपितु उसकी मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है, उसकी जल-संरक्षण क्षमता बढ़ती है और सिंचाई के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की जरूरत होती है। इन प्रयासों के अंतर्गत किसानों को प्रेरित किया जाता है कि वे एक छोटे से प्लाट पर सब्जियों का बगीचा इस तरह से लगाएं जिससे कम भूमि पर भरपूर सब्जी का उत्पादन हो सके। इसके लिए बांस, तार, रस्सी और सुरक्षा के उपायों से ऐसा स्थान तैयार किया जाता है जहां पौधे अधिक सुरक्षित रहें और सब्जियों वाली बेल अधिक आसानी से ऊपर चढ़ सके।

इस बगीचे में जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी, बेल, सब्जी के छोटे पौधे और बड़े पौधे इस तरह लगाए जाते हैं कि वे एक दूसरे के विकास में बाधक बने बिना पनप सकें और जिन पौधों को बड़े पौधों की छाया या रक्षा चाहिए वह भी उन्हें मिल सके। इस तरह एक ही बगीचे से वर्ष में 20 या उससे भी अधिक तरह की सब्जियां प्राप्त हो जाती हैं। इससे किसान परिवार के पोषण और स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है और दूसरी ओर उन्हें वर्ष भर सब्जियों की बिक्री से कुछ न कुछ आय प्राप्त होती है। चूंकि इन बगीचों में कई स्तरों पर सब्जी का उत्पादन होता है, अतः इन्हें प्रायः मल्टी लेयर गार्डन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त घर के पास रसोई के अतिरिक्त जल के उपयोग से किचन गार्डन भी लगाए जाते हैं।

इसी तरह खेत के छोटे भाग में फलों के बगीचे भी लगाए जाते हैं। इनमें अमरूद, नींबू, पपीते, आम आदि के पेड़ लगाए जाते हैं, हालांकि अभी अधिक महत्त्व अमरूद को ही दिया गया है। जब तक अमरूद के पेड़ फल देने लायक बड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके साथ-साथ मटर और दलहन जैसी कुछ फसल भी लगा ली जाती है। इन फलों के बगीचों से भी पोषण और आय होने का लाभ मिलता है। फल और सब्जी के बगीचे पूरी तरह प्राकृतिक पद्धति से पनपाए जाते हैं जिससे सब्जी और फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहती है। इस तरह पोषण और स्वास्थ्य का अधिक लाभ मिलता है और अच्छी गुणवत्ता के फल और सब्जी की बिक्री भी फटाफट होती है, अच्छी कीमत भी मिलती है। इन बगीचों में प्रयोगात्मक तौर पर किसान प्राकृतिक खेती की अच्छी उपयोगिता और लाभ भी देखते हैं तो बाद में प्राकृतिक खेती को अपने पूरे खेत में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। कुछ किसान कहते हैं कि वे यह बदलाव धीरे-धीरे करते हैं जबकि कुछ अपेक्षाकृत अधिक तेजी से करते हैं। यह उनके अपने चुनाव और स्थितियां की बात है। यह सब बदलाव लोकतांत्रिक बहस और विमर्श, स्थानीय स्थितियों और खेतों पर हो रहे प्रयोगों के आधार पर होते हैं। सृजन के कार्य-क्षेत्र में अनेक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हैं जो बचत करते हैं और इसका उपयोग विभिन्न सार्थक कार्यों के लिए करते हैं। इस तरह साहूकारों पर निर्भरता दूर होती है और मोटा ब्याज देने से बचाव होता है। अब अधिक रुझान महिला किसान उत्पादक संगठन बनाने की ओर है। इस तरह के गांव स्तर के महिला संगठन अधिक व्यापक संगठनों से जुड़ते हैं जो कृषि, बगीचों और वनों के उत्पादों को एकत्र कर उनकी प्रोसेसिंग के लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। इस कंपनी की शेयर होल्डर महिला किसान ही होती हैं। इस तरह एक ओर उनकी आय बढ़ती है और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के खाद्य मिलते हैं। ऐसे प्रयास अभी आरंभिक स्थिति में ही हैं और उन्हें अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है।

दूसरी ओर इस कार्यक्षेत्र की अनेक महिलाओं ने निर्धारित आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़कर समाज-सुधार के भी महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं और शराब तथा नो को भी कुछ स्थानों पर कम किया है। इन प्रयासों की बड़ी उपलब्धि जल-संरक्षण बढ़ाने के रूप में रही है, जिसके अंतर्गत कम बजट में ही जल-संरक्षण को बढ़ाया गया व इस आधार पर खेती के विकास की बुनियाद मजबूत की गई। तालाबों की सफाई से प्राप्त गाद मिट्टी ने खेतों को प्राकृतिक ढंग से बहुत उपजाऊ बनाया।

बाकी राम जाने

मीडिया

सुधीश पचौरी

विज्ञापन ऐसे ही छल करते हैंः वे ब्रांड की ऐसी विशेषताएं बताते हैं जिनको देख आप उसे खरीद लेते हैं। अगर आपको उनको दोषी कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमने आपको जबर्दस्ती तो कुछ दिया नहीं। आपको चॉयस थी कि आप इसे लेते न लेते...

'लोन' लो 'लोन' लो!
'उधर' लो 'उधर' लो!
ऑफलाइन लो!
ऑनलाइन लो!

मगर 'लोन' लो जरूर। इधर मांगा। उधर मिला। 'लोन' तुरंत मिलेगा। एक विज्ञापन 'लोन' के लिए ललचाता है कि 'लोन' लो तुरंत लो इस नंबर पर संपर्क करो...फिर एक सरकारी बैंक की चेतावनी आती है सावधान रहें...'लोन' की शर्तें पढ़ें, समझें तब फैसला लें। यह पहली बार है कि जनता को चेताया जाने लगा है कि जब ऐसा कुछ करें, शर्तें पहले जान लें। वरना तो वक्त था जब कोई चेताता तक न था! इसी तरह 'मसालों' के विज्ञापन आते हैं। अलग-अलग ब्रांड के मसाले स्वादिष्ट भोजन के लिए ललचाते है। कहते हैं कि दाल-सब्जी में डालो। स्वादिष्ट भोजन खाओ। खाने से गैस हो तो गैस खत्म करने वाला ये पेय लो, वो पेय लो यानी पहले स्वाद के लिए ललचाओ। फिर पेट खराब हो तो कहो कि ये पेय लो। जब खाने वाले का इससे भी काम न चले तो वो क्या करे? अगर आप सोचते हैं कि देश में 'कंज्यूमर अदालतें' हैं, जिनमें अपील की जा सकती है, तो जान लें कि एक हद से आगे वे भी नहीं जा पाते। विज्ञापन वाले के कानूनी 'दांव-पेच' आपको उलझाए रखेंगे।

हमारे विज्ञापन हमें ललचा कर अपना 'उपभोक्ता' तो बना लेते हैं लेकिन इसके बाद हमें 'भाग्य' पर छोड़ देते हैं। अपना 'बाजार' ऐसा 'गैर-जिम्मेदार' बाजार है। वह अपना सामान बेच कर हमें अकेला छोड़ देता है! कुछ विज्ञापन ऐसे भी आते हैं जो पब्लिक को 'म्युचुअल फंड' में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे एक विज्ञापन को नामी क्रिकेट खिलाड़ी करता है। उसकी पत्नी उसके रिटायर होने के बाद नौकरी ढूंढने की बात कहती है तो विज्ञापन एक बैंक के म्युचुअल फंड में निवेश की बात करने लगता है, और यह बात 'सुपर फास्ट' शैली में कही जाती है कि 'म्युचुअल फंड' बाजार के जोखिम के अधीन हैं, इसलिए शर्तों को धयान से पढ़ें...यानी आपका पैस डूब जाए तो आप जानें। हमने तो कहा था कि जोखिम भी है! ऐसे ही एक कार का विज्ञापन आता है। एक युवा, एक युवती अपनी-अपनी कार की विशेषताएं बताते हुए बहस करते रहते हैं। फिर अपनी-अपनी गाड़ी को तेजी से चला कर एक दूसरे को हराना चाहते हैं लेकिन दोनों एक ही समय निर्धारित जगह पहुंच जाते हैं।

ब्रांडेड गाड़ी महंगी है। दस-ग्यारह लाख की तो होगी ही। उसकी पिकअप अच्छी है। डिजिटल है। हाइब्रिड है यानी पेट्रोल के अलावा दूसरी ऊर्जा; जैसे डीजल और बिजली से भी चल सकती है। फिर किसी दिन खबर आती है कि फलां हाईवे पर तेजी से चलती कार 'डिवाइडर' से टकरा गई और कइयों की मौत हो गई। जब हम ऐसी खबर पढ़ते हैं, तब हमें इस तरह की कारों के इन विज्ञापनों की याद नहीं आती जो कार की तेज स्पीड और अन्य गुणों को गाकर बेचते हैं। ऐसी गाड़ियां जब स्पीड के कारण टकरा जाती हैं, और कई लोग मर जाते हैं तो भी या तो हम तेज स्पीड को दोषी मान लेते हैं, या ड्राइवर के नशे को दोषी मानने लगते हैं, लेकिन कार बेचने वाले को हम किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। विज्ञापन ऐसे ही छल करते हैंःवे ब्रांड की ऐसी विशेषताएं बताते हैं जिनको देख आप उसे खरीद लेते हैं।

अगर आपको उनको दोषी कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमने आपको जबर्दस्ती तो कुछ दिया नहीं। आपको चॉयस थी कि आप इसे लेते न लेते...आपने वो महंगी कार उसकी विशेषताओं को जान कर ली। आपको उसकी स्पीड की विशेषता पसंद आई। साथ ही उसकी सीट क्षमता और सामान रखने की जगह पसंद आई। आपको उसकी 'माइलेज क्षमता' पसंद आई, साथ ही उसकी बॉडी की मजबूती भी पसंद आई। कार खरीदते समय आप भी 'पिकअप' और 'स्पीड' की क्षमता को देखते हैं और 'बॉडी' की मजबूती को देखते हैं तो अपने को बचाने की क्षमता के बारे में सोचते हैं। इसलिए हर एक्सीडेंट की खबर कार के मालिक की नजर से दी जाती है। मरने वाले आम आदमी की नजर से नहीं दी जाती! इस तरह कार का हर विज्ञापन समाज को दो भागों में बांटता हैः एक वो जो पैदल है, दूसरा वो जो कार में है, जो कभी पी लेता है, जिसकी कार कभी-कभी 'आउट ऑफ कंट्रोल' हो जाती है और पैदल चपेट में आ जाते हैं। बेचते वक्त विज्ञापन उसकी 'तेज स्पीड' बताता है जब 'स्पीड' किसी की जान ले लेती है तो विज्ञापन नहीं सोचता कि यह 'स्पीड' के कारण भी हुआ हो सकता है। जाहिर है विज्ञापन सिर्फ सेल करना जानते हैं बाकी राम जाने!

हिमाचल में भूस्खलन का खतरा बढ़ा

जलविद्युत परियोजना

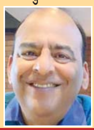

पंकज चतुर्वेदी

हिमाचल सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा प्रकाशित अध्ययन 'लैंडस्लाइड हैजार्ड रिस्क असेसमेंट' ने पाया कि बड़ी संख्या में हाइड्रोपावर स्थल पर धरती खिसकने का खतरा है। लगभग 10 ऐसे मेगा हाइड्रोपावर प्लांट, स्थल मध्यम और उच्च जोखिम वाले भूस्खलन क्षेत्रों में स्थित हैं

सुंदर, शांत, सुरम्य हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौत का सन्नाटा है। राज्य का बड़ा हिस्सा अचानक तेज बरसात और जमीन खिसकने से कब्रिस्तान बना हुआ है तो जहां आपदा आई नहीं वहां के लोग भी आशंका में जी रहे हैं। कई जिलों विशेषकर कुल्लू और धर्मशाला में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और यातायात बाधित हुआ। सेंज घाटी में 2000 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। गंभीरता से देखें तो ये हालात भले ही आपदा से बने हों लेकिन इन आपदाओं को बुलाने में इंसान की भूमिका भी कम नहीं है। जब दुनिया भर के शोध कह रहे थे कि हिमालय पर्वत जैसे युवा पहाड़ पर पानी को रोकने, जलाशय बनाने और सुरंग बनाने के लिए विस्फोटक के इस्तेमाल के अंजाम अच्छे नहीं होंगे तब हिमाचल की जलधाराओं पर छोटे-बड़े बिजली संयंत्र लगा कर उसे विकास का प्रतिमान निरुपित किया जा रहा था। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो द्वारा तैयार देश के भूस्खलन नक्शे में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों को बेहद संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। देश के कुल 147 ऐसे जिलों में संवेदनशीलता की दृष्टि से मंडी को 16वें स्थान पर रखा गया है। यह आंकड़ा और चेतावनी फाइल में सिसकती रही और इस बार मंडी में तबाही का भयावह मंजर सामने आ गया। ठीक यही हाल शिमला का हुआ जिसका स्थान इस सूची में 61वें नम्बर पर दर्ज है।

हिमाचल सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा प्रकाशित अध्ययन 'लैंडस्लाइड हैजार्ड रिस्क असेसमेंट' ने पाया कि बड़ी संख्या में हाइड्रोपावर स्थल पर धरती खिसकने का खतरा है। लगभग 10 ऐसे मेगा हाइड्रोपावर प्लांट, स्थल मध्यम और उच्च जोखिम वाले भूस्खलन क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सर्वेक्षण कर भूस्खलन संभावित 675 स्थल चिन्हित किए हैं। चेतावनी के बाद भी किन्नौर में एक हजार मेगा वॉट की करचम और 300 मेगा वॉट की बासपा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एक बात और समझना होगा कि 'वर्तमान में बारिश का तरीका बदल रहा है और गर्मियों में तापमान सामान्य से कहीं अधिक पर पहुंच रहा है। ऐसे में मेगा जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की राज्य की नीति को एक नाजुक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में लागू किया जा रहा है।

वैसे हिमाचल प्रदेश में पानी से बिजली बनाने का कार्य 120 सालों से हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा दोहन का कार्य इसके पूर्ण राज्य घोषित होने से पहले ही शुरू हो गया था। 1908 में चंबा में 0.10 मेगावॉट क्षमता की एक छोटी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कार्य से शुरू हुई थी। इसके बाद 1912 में औपचारिक रूप से शिमला जिले के चाबा में 1.75 मेगावॉट क्षमता का बिजली संयंत्र शुरू हुआ जिसे ब्रिटिश भारत की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका सफल परिचालन होने पर यहां और बिजली संयंत्र लगाने की संभावनाएं तलाशी जाने लगीं। इसी योजना के तहत मंडी जिले के जोगिन्द्र नगर में 48 मेगावॉट की बड़ी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया जो 1932 में पूरा हुआ। आज हिमाचल में 130 से अधिक छोटी-बड़ी बिजली परियोजनाएं चालू हैं जिनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 10,800 मेगावॉट से अधिक है। सरकार का इरादा 2030 तक राज्य में 1000 से अधिक जलविद्युत परियोजनाएं लगाने का है जो कुल 22,000 मेगावॉट बिजली क्षमता की होगी।

कई शोधपत्र कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध जल विद्युत परियोजनाओं से चार किस्म की दिक्कतें आ रही हैं। पहली, इसका भूवैज्ञानिक प्रभाव है, जिसके तहत भूस्खलन, मिट्टी का ढहना शामिल है। दूसरी दिक्कत जल भूवैज्ञानिक है जिसमें देखा गया कि झीलों और भूजल स्रोतों में जल स्तर कम हो रहा है। तीसरा नुकसान है-बिजली परियोजनाओं में नदियों के किनारों पर खुदाई और बह कर आए मलवे के जमा होने से वनों और चरागाहों में जलभराव बढ़ रहा है, और ऐसी परियोजनाओं का चौथा खतरा है सुरक्षा में कोताही के चलते हादसों की आशंका। इसलिए ऐसी परियोजनाओं से बचा जाना चाहिए जो कुदरत की अनमोल देन कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश को हादसों का प्रदेश बना दें।

सांख्यिकी डिजिटल रूप अधिक पारदर्शी

सांख्यिकी दिवस

सिद्धार्थ जैन

आज 29 जून को प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर देश भर में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है। सांख्यिकी और योजना निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए यह दिन हर वर्ष सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष का आयोजन डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम-'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष' है। यह विषय भारत की आंकड़ा प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की महत्ता को रेखांकित करता है, जिसने दशकों से नीति निर्माण और प्रशासन में सटीक, समयबद्ध और विश्वसनीय आंकड़ों की नींव रखी है। इस अवसर पर जानना जरूरी है कि कैसे बीते एक वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने डिजिटल बदलाव के जरिए भारत की आंकड़ा प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। पिछले वर्ष 29 जून को आरंभ हुए ई-सांख्यिकी पोर्टल के माध्यम से अब तक 13.5 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आम नागरिक, शोधकर्ता, विद्यार्थी और नीति-निर्माता अब एक ही मंच से सरकारी आंकड़ों तक तुरंत पहुंच बना पा रहे हैं। यह पोर्टल न केवल सूचना का स्रोत है, बल्कि डिजिटल लोकतंत्र की मजबूत कड़ी भी बन गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने डाटा इनोवेशन लैब, मेटाडेटा पोर्टल, ऑनलाइन कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की नई वेबसाइटों सहित कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। ये सभी पारदर्शिता बढ़ाने और आंकड़ों को आम जन के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कदम हैं। तकनीकी नवाचार की दिशा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा साइंस जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है। तीन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पूरे किए जा चुके हैं, और कई पायलट प्रोजेक्ट्स पर कार्य जारी है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा विशेषज्ञ समिति (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद) का सक्रिय सदस्य बन चुका है। सांख्यिकी दिवस के मौके पर मंत्रालय द्वारा GoIStats मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जो नागरिकों को मोबाइल पर ही आधिकारिक आंकड़ों तक सीधी पहुंच देगा। इस बदलाव के साथ डेटा सुरक्षा भी एक बड़ी प्राथमिकता रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की है, और एक विशेषज्ञ एजेंसी को आंकड़ों की गोपनीयता और संरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है।

मंत्रालय का यह डिजिटल परिवर्तन रणनीतिक और चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में डेटा संग्रह और प्रसार की व्यवस्था डिजिटल की गई है, जबकि अगले चरण में आंकड़ों की प्रोसेसिंग को तेज और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम होगा। सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी और आम नागरिकों में समझ विकसित हो कि आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं होते-वे निर्णयों की दिशा तय करते हैं, योजनाओं की गुणवत्ता सुधारते हैं। विकसित भारत की आकांक्षा को साकार करने के लिए सटीक, सुरक्षित और समय पर आंकड़ों की भूमिका को अब और भी मजबूती से स्वीकारा जा रहा है।

एमएसपी बढ़ने से रुकेंगे विरोध के स्वर

खेती-किसानी

अमित बैजनाथ गर्ग

हाल ही में मोदी सरकार ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इसी तरह अन्य कई फसल की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि हर फसल के लिए लागत के साथ 50 फीसद को ध्यान में रखा गया है।

वहीं किसानों के लिए ब्याज छूट को बनाए रखने का फैसला भी लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर दो लाख तक का लोन चार फीसद ब्याज पर मिलता रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं। इससे अब छोटे और सीमांत किसानों को बड़ा फायदा हो सकेगा। सरकार का दावा है कि किसानों के हितों के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उसका कहना है कि खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि से उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। खास बात यह है कि अधिकतर फसल की एमएसपी अब लागत के लगभग डेढ़ गुना तक हो चुकी है, जिसकी मांग लगातार हो रही थी। गौरतलब है कि एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते रहे हैं।

अब सवाल यह है कि क्या इस बार एमएसपी बढ़ने से अगली बार आंदोलन नहीं होगा। असल में एमएसपी सरकार द्वारा किसानों से तय दर पर फसल खरीदने की गारंटी है। इसका मकसद किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक निश्चित राशि देना है। एमएसपी की वजह से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ बाजारी मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों से शोषण से बचाया जा सकेगा। वहीं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस-ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का अध्ययन बताता है कि खेती की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने की पक्षपाती सरकारी नीतियों के कारण देश के किसान वर्ष 2000 के बाद से लगातार घाटा उठा रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियों और कृषि कीमतों के कारण किसानों को वर्ष 2022 में 14 लाख करोड़ रुपये और 2000-2017 के दौरान 2017 की कीमतों पर 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके चलते ही किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वहीं सरकार का दावा है कि 2022-23 में किसानों से 60 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक धान और 26 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर करोड़ों रुपये हस्तांतरित किए गए।

असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वे हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसल की एक सूची सरकार को सौंपी थी। एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के कई उपाय हो सकते हैं। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन यानी कि जब फसल की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाए, तो सरकार इसकी भरपाई करे। वहीं किसानों को धान-गेहूं की फसल की बजाय ज्यादा कीमत देने वाली फसल को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को फल, सब्जी, मवेशी और मछली पालन के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आड़ में किसानों को कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस साल की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत न करने एवं उनकी शिकायतों का समाधान न करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। कोर्ट ने केंद्र से एमएसपी के लिए विधिक गारंटी की मांग वाली नई याचिका पर जवाब देते हुए किसानों की मांगों पर विचार करने का आग्रह किया था। असल में एमएसपी तय करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है।

सीएसीपी उत्पादन लागत, बाजार के रुझान और मांग-आपूर्ति के हिसाब से एमएसपी तय करता है। एमएसपी की गणना के लिए सीएसीपी खेती की लागत को तीन हिस्सों में बांटता है। इसमें फसल उत्पादन के लिए किसानों के नकदी खर्च के साथ-साथ पारिवारिक श्रम का भी हिसाब लगाया जाता है। एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। सीएसीपी ने अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट में एमएसपी पर एक कानून बनाने का सुझाव दिया था। उसका कहना था कि सरकार को कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों द्वारा भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सके। ऐसा करने के लिए धान और गेहूं के एमएसपी को फ्रीज कर दिया जाए। इससे किसान सरकारी तंत्र पर निर्भरता से बचेंगे और उनका शोषण रुकेगा।

असल में एमएसपी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। वे हर फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछली बार उन्होंने लगभग सभी फसल की एक सूची सरकार को सौंपी थी। एमएसपी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। हालांकि किसान नेता सरकार के इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार के कई उपाय हो सकते हैं। इसमें एक है मूल्य स्थिरता कोष का गठन यानी कि जब फसल की बाजार कीमत एमएसपी से नीचे चली जाए, तो सरकार इसकी भरपाई करे

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-34, अंक 311

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

विकरे की उपयोगी सैद्धांतिकी-आप पेंटिंग की नीलामी करना चाहते हैं और इच्छुक हैं जानने के कि खरीदार सर्वाधिक कीमत कितनी देना चाहेंगे तो इस नियम का पालन करें। नियम यह कि खरीदारों के प्रस्ताव सीलबंद हों और उन्हें अच्छे से पता हो कि सर्वाधिक बोली लगाने वाले को पेंटिंग मिलेगी लेकिन वह दूसरी सबसे ऊंची कीमत दे रहा होगा। **कौशिक बसु, अर्थशास्री, @kaushikcbasu**

कविता के भूगोल को विस्तार देतीं पार्वती की कविताएं

हिन्दी कविता की युवतम पीढ़ी में पार्वती तिर्की का स्वर अलग से पहचाना जा सकता है। उनकी कविताओं में आदिवासी जीवन-दृष्टि, प्रकृति और सांस्कृतिक स्मृतियों का वह रूप सामने आता है, जो अब तक मुख्यधारा के साहित्य में बहुत कम दिखाई देता रहा है। झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाली कवि पार्वती तिर्की को उनके कविता-संग्रह 'फिर उगना' के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। यह न केवल उनके रचनात्मक योगदान का सम्मान है, बल्कि हिन्दी कविता के निरंतर समृद्ध होते हुए भूगोल और अनुभव संसार के विस्तार की स्वीकृति भी है।

कविताओं के माध्यम संवाद की कोशिश : इस अवसर पर पार्वती तिर्की ने कहा, मैंने कविताओं के माध्यम से संवाद की कोशिश की है। मुझे खुशी है कि इस संवाद का सम्मान हुआ है। संवाद के जरिए विविध जनसंस्कृतियों के मध्य तालमेल और विश्वास का रिश्ता बनता है। इसी संघर्ष के लिए लेखन है, इसका सम्मान हुआ है तो आत्मविश्वास बढ़ा है।

कविता के भीतर एक जीवंत दुनिया : 'फिर उगना' पार्वती तिर्की की पहली काव्य-कृति है, जो वर्ष 2023 में राधाकृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। इस संग्रह की कविताएं सरल, सच्ची और संवेदनशील भाषा में लिखी गई हैं, जो पाठक को सीधे संवाद की तरह महसूस होती हैं। वे जीवन की जटिलताओं को बहुत सहज ढंग से कहने में सक्षम हैं। इन कविताओं में धरती, पेड़, चिड़िया, चांद-सितारे और जंगल सिर्फ प्रतीक नहीं हैं-वे कविता के भीतर एक जीवंत दुनिया की तरह मौजूद हैं। पार्वती तिर्की अपनी कविताओं में बिना किसी कृत्रिम सजावट के आदिवासी जीवन के अनुभवों को कविता का हिस्सा बनाती हैं। वे आधुनिक सभ्यता के दबाव और आदिवासी संस्कृति की जिजीविषा के बीच चल रहे तनाव को भी गहराई से रेखांकित करती हैं। उनका यह संग्रह एक नई भाषा, नई संवेदना और नए दृष्टिकोण की उपस्थिति दर्ज कराता है।

युवा प्रतिभा का सम्मान हमारे लिए गर्व की बात : इस उपलब्धि पर राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने कहा कि पार्वती तिर्की का लेखन साबित करता है कि परंपरा और आधुनिकता एक साथ कविता में जी सकती हैं। उनकी कविताएं बताती हैं कि आज हिन्दी कविता में नया क्या हो रहा है, और कहां से हो रहा है। उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि कविता का भविष्य सिर्फ शहरों या स्थापित नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वहां भी जन्म ले रही है, जहां भाषा, प्रकृति और परंपरा का रिश्ता अब भी जीवित है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसी युवा प्रतिभा की पहली कृति का प्रकाशन हमने किया है। उन्होंने कहा कि पार्वती तिर्की वर्ष 2024 में राजकमल प्रकाशन के सहयात्रा उत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले 'भविष्य के स्वर' विचार-पर्व में वक्ता भी रह चुकी हैं। ऐसे स्वर को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलना सुखद है। इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पर मैं उन्हें राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। हम आशा करते हैं कि यह सम्मान नई पीढ़ी के लेखकों को प्रेरित करेगा और आने वाले समय में उनके जैसे और नए स्वर साहित्य में और अधिक स्थान पाएंगे।

वे पुरुष

वे पुरुष
जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया
पंछियों के प्रति अधिक विनम्र हुए
और धरती की ओर
अधिक झुके हुए दिखे

वे पुरुष
अपनी पीठ पर
बच्चे को बेतराए (1) हुए
और उन्हें खेलाते हुए दिखे

वे पुरुष
जो स्त्रियों के गीतों को
दोहराते हुए सुनाई पड़े

वे पुरुष
जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया
पुरुष होते हुए अधिक स्त्री हुए।

1. बच्चे को अपनी पीठ पर ढोना।

पार्वती तिर्की का परिचय: पार्वती तिर्की का जन्म 16 जनवरी, 1994 को झारखंड के गुमला जिले में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय, गुमला में हुई। इसके बाद उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से हिन्दी साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वहीं के हिन्दी विभाग से 'कुडुख आदिवासी गीत : जीवन राग और जीवन संघर्ष' विषय पर पी-एच.डी. की डिग्री हासिल की। पार्वती की विशेष अभिरुचि कविताओं और लोक गीतों में है। वे कहानियां भी लिखती हैं। उनकी रचनाएं हिन्दी की अनेक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और वेब-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्ष 2024 में वे राजकमल प्रकाशन द्वारा आयोजित 'भविष्य के स्वर' कार्यक्रम की वक्ता रही हैं। उनका पहला कविता-संग्रह 'फिर उगना' वर्ष 2023 में राधाकृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह को हिन्दी कविता के समकालीन परिदृश्य में एक नई और जरूरी आवाज के रूप में देखा गया है। वर्तमान में पार्वती तिर्की, राम लखन सिंह यादव कॉलेज (रांची विश्वविद्यालय), रांची के हिन्दी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।

(जनचौक वेबसाइट से साभार) ■

'फिर उगना' पार्वती तिर्की की पहली काव्य-कृति है, जो वर्ष 2023 में राधाकृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। इस संग्रह की कविताएं सरल, सच्ची और संवेदनशील भाषा में लिखी गई हैं, जो पाठक को सीधे संवाद की तरह महसूस होती हैं। वे जीवन की जटिलताओं को बहुत सहज ढंग से कहने में सक्षम हैं। इन कविताओं में धरती, पेड़, चिड़िया, चांद-सितारे और जंगल सिर्फ प्रतीक नहीं हैं-वे कविता के भीतर एक जीवंत दुनिया की तरह मौजूद हैं। पार्वती तिर्की अपनी कविताओं में बिना किसी कृत्रिम सजावट के आदिवासी जीवन के अनुभवों को कविता का हिस्सा बनाती हैं। वे आधुनिक सभ्यता के दबाव और आदिवासी संस्कृति की जिजीविषा के बीच चल रहे तनाव को भी गहराई से रेखांकित करती हैं

छत्तीसगढ़ी साहित्य के वैश्विक पर्याय

डॉ. सुरेंद्र दुबे : स्मरण शेष

गुदगुदाता हास्य, तीक्ष्ण व्यंग्य, अद्भुत रचनात्मक शैली के धनी अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे सबको रोता, बिलखता और आंसुओं से भीगता छोड़ गए। उनका असामयिक निधन संपूर्ण साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। अपनी स्वयं की मृत्यु पर हास्य पैदा करने वाले और हास्य व्यंग्य में टाइगर अभी जिंदा है, कहने वाले हास्य के शिखर पुरुष व्यंग्य के पुरोधा, छत्तीसगढ़ी भाषा-साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन से साहित्य जगत स्तब्ध है।

डॉक्टर दुबे जितने उच्च कोटि के कवि थे, उतने ही संवेदनशील, सीधे, स्वाभिमानी और गरीब तबकों के बड़े हिमायती भी थे। मुझे उनके साथ 15 से 20 मंचों में काव्य पाठ करने का प्रदेश और देश के विभिन्न स्थानों में सान्निध्य प्राप्त हुआ। मुझसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह व्यवहार किया करते थे। उनकी श्रीमती शशि दुबे मेरे मामा जी की सुपुत्री हैं, और रिश्ते में मेरी बड़ी बहन लगती हैं। इस तरह मेरा दुबे जी से रिश्ता साले-जीजा का बड़ा नाजुक और मजाक का ही हुआ करता था। छत्तीसगढ़ी भाषा के हास्य व्यंग्य के पुरोधा कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ एवं देश के कवि सम्मेलन की आन, बान और शान रहे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों में डॉक्टर दुबे की उपस्थिति अति अनिवार्य होती थी। जब भी कोई कवि मंच में दर्शकों द्वारा नापसंद या खारिज किया जाता था, तब डॉक्टर दुबे ही थे जो मंच और दर्शकों को पूरी तरह संभाल कर गुदगुदा कर हास्य पैदा कर देते थे जिससे कवि सम्मेलन पूरी तरह सफल हो जाया करता था।

व्यक्तिगत तौर पर मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की कविताओं और उनकी मेहनत लगन तथा ईमानदार व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रशंसक और अनुयायी रहा। उनका अचानक स्वर्ग सिधार जाना व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ का हर कवि सम्मेलन उनके बिना अधूरा और अपूर्ण हुआ करता था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया था। निश्चित तौर पर वे इस सम्मान के सच्चे और सही हकदार थे। देश और प्रदेश के हर कवि सम्मेलन में उनकी उपस्थिति कवि सम्मेलन की सफलता की गारंटी और पर्यायवाची थी। बहत्तर वर्षीय हास्य सम्राट कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने 26 जून को शाम 4:00 बजे अपनी अंतिम सांस ली और स्वर्ग में देवताओं को हंसाने के लिए स्वर्ग सिधार गए। 27 जून, 2025 को दोपहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

उनके निधन पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने के लिए शक्ति और संबल की प्रार्थना की। उन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन को साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि डॉक्टर दुबे की जीवंतता, ऊर्जा और साहित्य के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। प्रख्यात कवि डॉ. कुमार विश्वास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ की बौद्धिक साहित्य की सांस्कृतिक धरोहर के स्थापित पर्याय कुशल मंच संचालक एवं शब्दों के हुनर से दर्शकों और श्रोताओं में जान फूंकने के सिद्ध कवि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन से संपूर्ण साहित्य जगत अपूर्व क्षति की मनोदशा में है। कविवर आप सदैव हमारे मुस्कुराहटों में सजीव रहेंगे। अशेष श्रद्धा प्रणाम। पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र दुबे व्यंग्य शैली के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े कवि और लेखक थे। उनका जन्म 8 जनवरी, 1953 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुआ था। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मंच तथा टेलीविजन के भी प्रख्यात कवि थे। उन्होंने चार किताबें भी लिखी हैं। उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया था। कवि सम्मेलन में अक्सर जाते समय कार या ट्रेन में बातों के दौरान सदैव भावुक खोकर मेरा नाम लेकर कहा करते थे यार, इतने छोटे व्यक्ति को इतना सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है, वे अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े कवि होने के बावजूद बहुत सामान्य आदमी समझते यह उनका बड़प्पन ही था और कहते मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे मृत्यु पर्यंत यह सम्मान बना रहे और मेरी कविताएं दर्शकों को, श्रोताओं को गुदगुदाती रहें, हंसाती रहें।

शायद उन्हें भान हो गया था कि वे पृथ्वी लोक में श्रोताओं और दर्शकों को हंसाते हुए देवताओं को भी हंसाने स्वर्ग लोक सिधार जाएंगे। हास्य सम्राट, छत्तीसगढ़ भाषा के अंतरराष्ट्रीय पर्याय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को मेरी व्यक्तिगत एवं छत्तीसगढ़ काव्य संस्थान, उत्तरायण सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थान एवं नव-छत्तीसगढ़ साहित्य संस्कृत संस्थान, रायपुर की तरफ से श्रद्धांजलि, नमन। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक संतप्त मेरी बड़ी बहन आदरणीया शशि दुबे जी को और उनके संपूर्ण परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।

प्रस्तुति : संजीव ठाकुर

जनकवि हूं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं

जनता पूछ रही क्या बतलाऊं,
जनकवि हूं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं।

ये पंक्तियां बाबा नागार्जुन की कविता की हैं। इसमें वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वे जनकवि हैं। स्पष्ट कहेंगे और कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मौजूदा दौर में कितने ऐसे कवि हैं, जिनके ये तेवर हैं, जो सत्ता के सामने खम ठोक कर, खड़े हो जाएं। सरकार की जनविरोधी नीतियों की अपनी कविताओं में खुल कर आलोचना करें जबकि नागार्जुन का सारा काव्य साहित्य सत्ता के विरोध का साहित्य है। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का साहस उनमें था। देश में कोई भी सत्ता रही हो, वह हमेशा सच के साथ रहे। झूठ और सत्ता के दोगलेपन का उन्होंने जमकर विरोध किया।

30 जून, नागार्जुन की जयंती

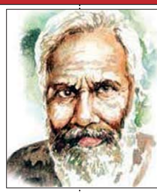

नागार्जुन प्रगतिशील धारा के जनकवि थे। आजादी से पहले उन्होंने किसानों-मजदूरों के आंदोलनों में हिस्सा लिया। अपनी जिंदगी में वे तीन बार जेल गए। सत्ता का विरोध और आंदोलनों में रचनात्मक भूमिका उनकी शख्सियत का हिस्सा रहीं। वे उस दौर के कवि हैं, जब देश राजनीतिक उथल-पुथल और जन आंदोलनों के दौर से गुजर रहा था। हम जब भी बाबा नागार्जुन की तस्वीर देखते हैं, उसमें उनकी देशज छवि नजर आती है। कोई बनावटीपन नहीं था। दोहरा चरित्र जीने में यकीन नहीं करते थे।

बाबा नागार्जुन की पूरी जिंदगी फक्कड़पन और घुमक्कड़ी में बीती। जनता के दुःख-दर्द को आवाज दी। पं. जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, बाल ठाकरे से लेकर मायावती तक को उन्होंने अपनी रचनाओं का मौज़ूअ बनाया। जरूरत पड़ी, तो उनकी मुखालफत भी की। सच कहने से नहीं हिचके। नागार्जुन की रचनाओं में मानवीय पीड़ा, लोक संस्कार, दबे-कुचले लोगों की आवाज और अपने समय की राजनीतिक घटनाओं पर त्वरित टिप्पणियां मिलती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के मार्फ्त तात्कालिक विषयों को उठाया। उनकी कविताओं में व्यंग्य की धार पैनी दिखाई देती है। यही सब बातें नागार्जुन और उनकी कविताओं को जनप्रिय बनाती हैं। नागार्जुन की कविताओं को लिखे हुए एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन आज भी उनकी कविताएं याद की जाती हैं। मुहावरे की तरह दोहराई जाती हैं। गरीबी, भूख, अत्याचार और कुशासन के खिलाफ उन्होंने जम कर लिखा। हक की बात करने से वे जरा भी नहीं हिचकिचाए।

रोजी-रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा
कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा।

स्पष्ट विचार, धारदार टिप्पणी, गरीबों और मजलूमों की आवाज नागार्जुन की कविताओं में प्रमुखता से शामिल रही। हिन्दी कविता में सही मायनों में कबीर के बाद, यदि कोई फक्कड़ और जनकवि कहलाने का उत्तराधिकारी हुआ, तो वो बाबा नागार्जुन थे। आजादी से पहले 1941 के आस-पास जब बिहार में किसान आंदोलित हुए, तो बाबा सब कुछ छोड़कर आंदोलन का हिस्सा बने और जेल भी गए। आजादी के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उनके बगावती तेवर बरकरार रहे। ब्रिटेन की महारानी जब भारत आईं, तो बाबा नागार्जुन ने अपनी कविता में उन्हें संबोधित करते हुए लिखा-

आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी,
यही हुई है राय जवाहरलाल की!

1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। समाजवादी लीडर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक जबर्दस्त आंदोलन हुआ जिसमें देश भर के लोग सत्ता की बर्बरता के खिलाफ लामबंद हुए, इन हालात पर नागार्जुन ने सत्ता के शीर्ष पद पर बैठी नेता को संबोधित करते हुए सीधे-सीधे लिखा-

इन्दु जी, इन्दु जी, क्या हुआ आपको?

बाबा नागार्जुन की कविताओं में जिंदगी के कई रंग और उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अकाल के दिनों में लिखी उनकी कविता में आम आदमी की बदहाल जिंदगी और उसके जीवन का जो संघर्ष दिखाई देता है, ऐसा हिन्दी कविता में विरल है-

कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास।

बाबा नागार्जुन जीवनपर्यंत मसिजीवी रहे। कलम से ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया। जाहिर है कि इसकी वजह से उन्हें गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन उन्होंने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। हाथ नहीं फैलाए। प्रख्यात समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने नागार्जुन की कविता का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, 'जब हिन्दी प्रदेश की श्रमिक जनता एकजुट होकर, नई समाज व्यवस्था के निर्माण की ओर बढ़ेगी, निम्न मध्यम वर्ग और किसानों और मजदूरों में भी जन्म लेने वाले कवि दृढ़ता से अपना संबंध जन आंदोलनों से कायम करेंगे, तब उनके सामने लोकप्रिय साहित्य और कलात्मक सौंदर्य के संतुलन की समस्या फिर दरपेश होगी। साहित्य और राजनीति में उनका सही मार्गदर्शन करने वाले अपनी रचनाओं के प्रत्यक्ष उदाहरण से उन्हें शिक्षित करने वाले, उनके प्रेरक और गुरु होंगे कवि नागार्जुन।'

प्रस्तुति : जाहिद खान

राग रंग | **आलोक पराड़कर**

शततंत्री संतूर की शान में

कई वाद्यों को लेकर आरंभ में हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हिचकिचाहट रही है। संतूर भी उन्हीं में से एक है। कहा गया कि इसके स्वरों में निरंतरता नहीं है, दो स्वरों के बीच अंतराल है, जो हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप, मींड, गमक जैसी जरूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं हैं। सौ तारों वाले इस शततंत्री वाद्य के स्वरों की गूंज को सहेजना और सुर में बनाए रखना भी आसान नहीं माना गया। बताते हैं कि संगीत विद्वान ठाकुर जयदेव सिंह ने संतूर को जब एक बार आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तुत कराने की पेशकश की तो सलाहकारों के विरोध के कारण उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा। लेकिन इस वाद्य को मिले पं. शिवकुमार शर्मा और पं. भजन सोपोरी जैसे विद्वान कलाकारों ने इन तमाम आरोपों का अपने वादन से न सिर्फ माकूल जवाब दिया, बल्कि मिजाज से सूफीयाना कश्मीर के लोकप्रिय वाद्य को नई पहचान भी दिलाई। कलाकारों के परिश्रम, वाद्य में किए गए परिवर्तनों, वादन में प्रयोगों ने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संतूर को न सिर्फ प्रमुखता से स्थान दिलाया है, बल्कि समाज में इसे व्यापक लोकप्रियता भी दिलाई है।

पं. भजन सोपोरी ने संतूर को जो नई दिशा दी उसमें ध्रुपद अंग की खूबियों का समावेश मुख्य रहा। अपने परिवार की संतूर वादन की प्राचीन परंपरा का विस्तार करते हुए सप्तकों के विस्तार, तारों पर दबाव की विशिष्टता जैसे कई नई खूबियों से उन्होंने सोपोरी बाज की शैली प्रचलित करते हुए संगीतप्रेमियों को मुग्ध किया। पं. शिवकुमार शर्मा और पं. भजन सोपोरी जैसे संतूर के दो प्रख्यात कलाकारों का निधन 2022 में कुछ ही समय के अंतराल पर हुआ। पं. भजन सोपोरी के जन्म दिवस को विश्व संतूर दिवस के रूप में मनाने की उनके संतूर वादक पुत्र अभय रुस्तम सोपोरी की परिकल्पना संतूर के सम्मान का ही उद्यम है, जो अब दूसरे वर्ष अधिक व्यापकता पाते हुए भारत के साथ कई और देशों से भी जुड़ गया है। मुख्य समारोह 22 जून को दिल्ली के चिन्मय मिशन सभागार में हुआ तो संतूर वादन के कार्यक्रमों की गूंज लंबे समय तक संगीत प्रेमियों की स्मृति में दर्ज हो गई। समारोह में खुद अभय रुस्तम सोपोरी के अतिरिक्त पं. शिवकुमार शर्मा की शिष्या श्रुति अधिकारी एवं पुत्र निनाद, पं. भजन सोपोरी के शिष्य दिव्यांश श्रीवास्तव के संतूर वादन के कार्यक्रमों के साथ ही समूह संतूर वादन का कार्यक्रम हुआ और विश्व भर में फैले पं. भजन सोपोरी के शिष्य-शिष्याओं ने भी आभासी माध्यम से संतूर वादन प्रस्तुत कर समारोह में शिरकत की।

सामापा (सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स) के तत्वावधान में हुए आयोजन में अभय रुस्तम का संतूर पर बजाया राग-'सोहिनी' कई मायनों में विशिष्ट था। तार सप्तक के चढ़े स्वरों में गाए-बजाए जाने वाली 'सोहनी' को मंद्र सप्तक में बजा कर तथा 'पूरिया' और 'मारवा' से बच कर निकलते हुए अभय रुस्तम ने अपने वादन से यह साबित करने का प्रयास किया कि राग की चिरपरिचित छवि से अलग जाकर भी कई बार उस राग को देखा जा सकता है, और यही हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खूबी भी है। लयकारियों के विभिन्न छंदों में उन्होंने इस राग के कई रूप दिखाए और फिर प्रख्यात गायक पं. कुमार गंधर्व के गाई प्रसिद्ध रचना 'रंग न डारो श्याम जी' का वादन किया एवं 'सोहिनी पंचम' की झलक भी प्रस्तुत की। तबले पर उनका साथ रामकुमार मिश्र ने दिया। खासकर झपताल में उनकी संगत प्रभावपूर्ण बन गई।

श्रुति अधिकारी की अपने पुत्र निनाद के साथ 'मधुकौंस' की प्रस्तुति मधुरता लिए हुए थी। दुर्जय भौमिक ने रूपक, तीनताल और एकताल में सुंदर संगत की। युवा संतूर वादक दिव्यांश ने आषाढ़ माह के अनुकूल राग-'मेघ मल्हार' सुनाया, जिसमें तबले पर आनंद मिश्र और जोड़ी पर चंचल सिंह ने संगत की। समूह वादन में डेनियल आकाश ब्रूनर (जर्मनी), सुमन पात्रा (फिनलैंड), अनुष्का मजूमदार, पौशाली दत्ता, नईरंजना राधिका और धीरज वैष्णव ने राग 'चारुकेशी' की प्रस्तुति की जिसमें जोड़ी पर चंचल सिंह ने साथ दिया। इदो एस्ट्राडा (अर्जेंटीना) ने जेवियर अलर्को गुजमान की तबला संगति में राग 'निर्मल कौंस', मी हुयेन (चीन) ने जुआंग चिंग की तबला संगति और लुईस इदुआरदो वेगा (कोलंबिया) ने आद्रिअना पिनजान की तबला संगति में राग 'यमन' की संक्षिप्त प्रस्तुतियां कीं जिन्हें आभासी माध्यम से देखा गया। बांसुरी वादक पं. चेतन जोशी ने समारोह का उद्घाटन किया। सामापा की अध्यक्ष प्रो. अपर्णा सोपोरी और उपाध्यक्ष संगीत लेखक पं. विजय शंकर मिश्र ने विचार व्यक्त करते हुए पं. भजन सोपोरी के व्यक्तित्व एवं योगदान का स्मरण किया। संचालन साधना श्रीवास्तव ने किया। ■

कैनवस | **जय त्रिपाठी**

शिल्पों की अदृश्य वेदना

नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश काउंसिल की कला दीर्घा में प्रदर्शित कलाकृतियों में समकालीन कलाकार सोनाक्षी चतुर्वेदी की प्रदर्शनी को देखें तो कलाकार की रचनात्मक गहराई स्मृति के साथ सामने आती दिखाई देती है। यदि इस कलाकार द्वारा निर्मित नारीत्व शिल्पों के बहाने सोनाक्षी को स्वीकार करते हुए, हम इस रचनात्मक विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं तो सैद्धांतिक तौर यह उनकी कला द्वारा उठाया गया वह सवाल है जिसमें वह अपने शिल्पों के माध्यम से यह भाव लाने का यत्न करती हैं कि महिलाओं को हम अथवा हमारा समाज कैसे स्मृतिविहीन कर देता है...या ऐसा हो जाता है। आगरा में जन्मी, लंदन में रहकर कलाकर्म में रत सोनाक्षी ने शिल्पों के साथ-साथ एनामेलिंग और जेमोलॉजी में अपनी विशेषज्ञता से रचनात्मक कलाकार के तौर पर 'जात' शीर्षक से अपने कामों को प्रदर्शित किया है।

यह प्रदर्शनी यादों को चिन्हित करती प्रतीत होती उन वस्तुओं की खोज करती है, जो विरासत में मिलती हैं, जिन्हें दशकों से हम साथ लेकर चलते आ रहे हैं। स्त्रियों के अनकहे जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए यदि हम उनके शिल्पों को गौर से देखें एवं महसूस करते हैं तो वे शिल्प भावनाओं की गहराई में जाकर उस ओर ले जाते हैं जहां स्मृतियां दुल्हन, मां और दादी के रूप में निभाए गए रिश्तों के माध्यम से याद आती हैं। स्टडी यूकेः क्रिएटिव कनेक्शन और ब्रिटिश काउंसिल की बेस्ट आफ ब्रिटिश की सांस्कृतिक पहल से आयोजित यह प्रदर्शनी विरासत, धातु और अर्थ की भाषा के माध्यम से मातृवंशीय स्त्री स्मृति को प्रदर्शित करती है।

'द अनार वसे' (अनार फूलदान), 'द प्याज टिफिन', शरीफा जार आदि जैसे ऐसे विषय हैं जिन पर उनके शिल्प केंद्रित हैं जो हमारे घर-परिवार की स्त्रियों का स्मरण कर उनकी याद दिलाते हैं जिन्हें उनके मूर्त गुणों केअनुसार सुध आने पर भूले-बिसरे प्रसारित किया जाता था। अति संवेदनशील कलाकार सोनाक्षी कहती हैं कि कुछ भूली हुईं महिलाएं तो विरासत की रोशनी में चमकती हैं, पर अन्य पुराने बक्सों में बोझ भरी यादों के साथ बंद हो जाती हैं। कलाकार की यह वेदना उनके शिल्पों में छिपी हुई वह खामोशी है जो आज के सभ्य समाज को आईना दिखाती है। इस युवा कलाकार ने 2024 में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट,लंदन से कला की विधिवत शिक्षा ली। अपनी दादी की शादी के सामान से आकर्षित होकर अपने शिल्पों में पारंपरिकता का समावेश करते हुए ब्रोंज, व्हाइट मेटल, एनामेलवेयर (ताम्रचीनी), रेसिन एनामेल और रत्नों के सम्मिश्रण से शिल्पों को उनकी मातृवंशीय स्मृति के बहाने रचा-गढ़ा है। कलाकार के अंतर्मन को दर्शाता शिल्पों में धातुओं का कलात्मक मिश्रण परंपराओं की प्रतिध्वनित करता है।

कहते हैं कि स्त्री सिर्फ एक शब्द नहीं, वह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है, इसी को संदर्भित करती यह युवा कलाकार अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंत करती हैं। वह कहती हैं कि कृतियों की दोहरी सतहें एक सौंदर्य संयोग नही हैं, वे कई महिलाओं के जीवन को दर्शाती हैं। दीर्घा में प्रदर्शित समिश्रित कलाकृतियां समकालीन प्रयोगशाली कलाकार की कलात्मकता एवं मौन प्रतिरोध का वह स्वतंत्र मिश्रण है, जो नई पीढ़ी की दृष्टि को सोच को दर्शाता है। उनकी कला इस बात का को संदर्भित करती है कि आने वाले समय मे नारी को उस रूप में हम याद करें, जिससे 'जात' शब्द पहचान या अस्तित्व की मूल भावना को दर्शाता हो। अपनी दादी की शादी के सामानों से प्रेरणा लेते हुए पीतल, सफेद धातु, ठंडे तामचीनी, राल-आधारित ताम्रचीनी और रत्नों का उपयोग करके गढ़ी गईं मूर्तियों में स्मृति के बहाने जिन शिल्पों को रचा है, वे कलाकार की सुखद यादें हैं।

मार्मिक रूप में अतीत के साथ जुड़ाव की भावना और तत्वों के संयोजन से युवा कलाकार सोनाक्षी चतुर्वेदी अपनी कला में जागरूकता के साथ रचती हैं, वैचारिक दृष्टि से भी आकृतियां में भावों को दर्शाती हैं, जिनमें कलाकृतियों को देखने वाले से बात करने की कोशिश करते शिल्पों में वह अपने मन की बात उन कृतियों में देखती हैं, जो पीढ़ियों, सतहों और मौन के पार चलती हैं। कई प्रश्नों का जवाब चाहती 31 जुलाई तक प्रदर्शित यह प्रदर्शनी, अपनी रचनात्मकता द्वारा समुचित पीढ़ी को समर्पित कर देने का श्रद्धा भाव रखती है। ■

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

NEW LAYOUT-674X576 Pawan New

समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता

भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना है कि ''हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय,विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।'' इसमें तीन शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व अखंडता इमरजेंसी काल के दौरान 1976 में जोड़े गये। यह कार्य तत्कालीन संसद द्वारा 42वां संशोधन करके किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह (महासचिव) श्री दत्तात्रेय होसबोले ने इनमें से दो शब्दों समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता को हटाये जाने की वकालत की है और कहा है कि 26 नवम्बर, 1949 को बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिये गये संविधान में ये शब्द नहीं थे। श्री होसबोले ने अखंडता शब्द पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई है। उनके इस कथन पर देश में राजनैतिक वितंडावाद खड़ा हो गया है जो किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता।

> भारत की हिन्दू संस्कृति स्वयं में ही धर्म या पंथ निरपेक्ष है। हिन्दुओं में सैकड़ों तरीकों की उपासना पद्धितियां हैं। कोई साकार ब्रह्म का उपासक है तो कोई निराकार ब्रह्म का। कोई ईश्वर को सद्‌गुण मानता है तो कोई निर्गुण। हजारों की तादाद में देवी-देवता हैं और कुल देवता हैं। अत: हिन्दू होना ही स्वयं में धर्मनिरपेक्षता की गारंटी होती है। अब सवाल यह है कि हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू राज में क्या अन्तर है? हिन्दू राष्ट्र इसकी संस्कृति का वाहक है जबकि हिन्दू राज प्रशासनिक प्रणाली को संकीर्णता में बांध देता है। इस भेद को समझने की जरूरत है।

कांग्रेस के लोकसभा में विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी ने इसे लेकर आरोप मढ़ दिया है कि भाजपा व संघ के लोग संविधान नहीं चाहते बल्कि वे हिन्दू मनुस्मृति चाहते हैं। संघ का विश्वास निश्चित रूप से हिन्दुत्व में है मगर उसकी राष्ट्रभक्ति पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। अत: श्री राहुल गांधी को भी संघ पर आरोप लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। हमें वह घटना भी याद करनी चाहिए जब 2002 के आसपास केन्द्र की भाजपा नीत वाजपेयी सरकार के संसदीय कार्य मन्त्री स्व. प्रमोद महाजन ने लोकसभा में सदन के सदस्यों के बीच संविधान की हस्तलिखित कापियां बांटी थीं। इसे तब श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने सुन्दर लेख में लिखा था और उस पर भगवान राम के लंका विजय से लौटते हुए चित्रों के साथ अन्य महापुरुषों के चित्र भी थे जिन्हें संविधान की हस्तलिखित कापी को सुन्दर बनाने हेतु नन्द लाल बोस जैसे प्रतिष्ठित चित्रकार ने बनाया था। इसी हस्तलिखित कापी पर उस समय के महान राजनीतिज्ञों के हस्ताक्षर थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। श्री महाजन ने तब संसद में तर्क रखा था कि संविधान की यह प्रति बताती है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द की कोई जरूरत नहीं है और जहां तक भारत के समाजवादी देश होने का सम्बन्ध है तो 1991 से जो आर्थिक उदारीकरण की नीति चल रही है वह बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है अत: इस शब्द की भी कोई जरूरत नहीं है।

देखा जाये तो भारत के समाजवादी नीतियों पर चलने का तब कोई तर्क नहीं था क्योंकि वाजपेयी सरकार घाटे में चलने वाली सरकारी कम्पनियों को पूंजीपतियों को बेच रही थी। इस प्रकार भारत का आर्थिक दर्शन पूंजीवाद से जुड़ गया था परन्तु तत्कालीन विपक्ष ने उन्हें संसद में बुरी तरह आड़े हाथों लिया था और कहा था कि संविधान की मूल प्रति में तो अकबर व टीपू सुल्तान के भी चित्र हैं और पूरा भारतीय संविधान समाजवाद का ऐसा खुला प्रपत्र है जिसमें समाजवादी नीतियों की वकालत की गई है और प्रत्येक नागरिक को बराबर का दर्जा दिया गया है और आर्थिक समानता लाने की बात कही गई है। इसलिए समाजवादी शब्द का प्रस्तावना में जोड़े जाने का उद्‌देश्य पूरी तरह तर्कसंगत व समयोचित है। मगर तब यह बात आगे नहीं खिंची और बहस के दावों व प्रति-दावों में ही सिमट कर रह गई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी इन दोनों शब्दों को जोड़े जाने के पक्ष में निर्णय दे चुका है। इसके साथ यह भी सत्य है कि 42वें संशोधन की विभिन्न उपधाराओं में इमरजेंसी काल के दौरान ही नागरिकों के कर्त्तव्यों को भी जोड़ा गया। इससे पहले केवल नागरिकों के अधिकारों की बात ही संविधान में थी। नागरिकों के मूल अधिकारों की बात संविधान की प्रस्तावना भी करती है। वस्तुत: प्रस्तावना या उद्‌देशियका संविधान का परिचय पत्र है जिसमें लक्ष्यों को अभिवादित किया गया है। मगर श्री होसबोले के कथन के पीछे भारत की जमीनी सच्चाई है।

भारत की हिन्दू संस्कृति स्वयं में ही धर्म या पंथ निरपेक्ष है। हिन्दुओं में सैकड़ों तरीकों की उपासना पद्धितियां हैं। कोई साकार ब्रह्म का उपासक है तो कोई निराकार ब्रह्म का। कोई ईश्वर को सद्‌गुण मानता है तो कोई निर्गुण। हजारों की तादाद में देवी-देवता हैं और कुल देवता हैं। अत: हिन्दू होना ही स्वयं में धर्मनिरपेक्षता की गारंटी होती है। अब सवाल यह है कि हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू राज में क्या अन्तर है? हिन्दू राष्ट्र इसकी संस्कृति का वाहक है जबकि हिन्दू राज प्रशासनिक प्रणाली को संकीर्णता में बांध देता है। इस भेद को समझने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान एक समान अवसर प्रदान करने की वकालत करता है और वह भी उसकी गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए। अत: यह समाजवादी धारा का पोषक है इसलिए प्रस्तावना में समाजवादी शब्द रहना किस लिए जरूरी हो सकता है?आखिरकार हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच-समझ कर ही समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों को नहीं रखा होगा।

जहां तक राष्ट्रीय अखंडता का सवाल है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। संविधान में नागरिकों के कर्त्तव्य निर्दिष्ट किये जाने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। संविधान हर नागरिक के साथ न्याय करने की भी गारंटी देता है। समाजवादी व्यवस्था में इसी की गारंटी तो दी जाती है जो कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में है। संविधान में इन दो शब्दों का महत्व आभूषणीय ज्यादा है। क्योंकि आज भी मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को दो वक्त का मुफ्त भोजन सुलभ करा रही है। यह रास्ता बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के बीच से ही निकला है।

नारी की अस्मिता पर आंच

गीता पाढा

"क्या करें कोई जब बाड़ ही खेत को खाएं,
और कानून का रखवाला ही कानून का मजाक बनाए,,
साक्षारता दर तो प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ती जाए,
पर फिर भी आधी से ज्यादा आबादी
जाहिलों सा आचरण दिखाए,,
जब स्कूल, कालेजों में भी नारी की अस्मिता पर आंच आए,
तो वहां प्रत्येक धर्म, मजहब, ईमाम के रखवाले को
कटघरे में खड़ा करके यह सवाल पूछा जाए,,
क्यों नहीं हम आज भी अपने बेटों को सही परवरिश दे पाएं,
जो नारी केवल उन्हें पैर की जूती और भोग विलास की वस्तु नजर आएं...।।"

भगवान भरोसे चल रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट?

*'शाम के वक्त घर लौटते परिंदों को भी कोई सताता है भला
ये खानाबदोश मंजर भी किसी सूनी आंखों में समाता है भला'*

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे की त्रासदी के जख्म भले ही अभी-अभी उतने ताजा हों, पर लगता है इसके बावजूद भी विमानन मंत्रालय अपने पुराने ढर्रे पर ही चलने को मजबूर है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि आज की तारीख में भी कम से कम डेढ़ दर्जन भारतीय एयरपोर्ट को 'रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर' की कमी खल रही है। उनकी जगह 'टेम्परेरी एयरपोर्ट डायरेक्टर' से ही काम चलाया जा रहा है। कई एयरपोर्ट पर तो सेफ्टी व सिक्योरिटी के दायित्व संभालने वाले अफसरों की कई पोस्ट खाली पड़ी हैं। सनद रहे कि एयरपोर्ट डायरेक्टर का किसी भी एयरपोर्ट के सुचारू व सुरक्षित परिचालन में सबसे अहम रोल होता है, अगर रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर की गैर मौजूदगी की बात हो तो आप मिसाल के तौर पर नार्थ में प्रयागराज, गोरखपुर, सेंट्रल से रायपुर का नाम ले सकते हैं, साउथ में तिरूपति, तूतीकोरन व राजा मुंद्री एयरपोर्ट, नार्थ-ईस्ट में डिब्रूगढ़, सिल्चर, जोरहाट, पश्चिम में गोवा और राजकोट एयरपोर्ट का नाम ले सकते हैं जहां रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर नहीं हैं। आने वाले दिनों में कोलकाता, इंदौर, जम्मू, पुणे, देहरादून के भी रेग्यूलर एयरपोर्ट डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं या उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। सूत्रों की मानें तो उनकी जगह लेने के लिए डायरेक्टर की सलेक्शन प्रक्रिया भी कई महीनों से लंबित पड़ी हुई है। ज्यादातर जगहों पर जहां से एयरपोर्ट डायरेक्टर की विदाई होती है वहां यह जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर वहां के वरिष्ठतम अधिकारी के सुपुर्द कर दी जाती है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह कि वेस्टर्न रीजन के पास कोई रीजनल एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ही नहीं है।

इसी तरह मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में भी कई पोस्ट वर्षों से खाली पड़ी हुई हैं। यहां तक कि रेग्यूलर सेफ्टी ऑफिसर की भी भरपाई अन्य विभागों से लोगों को लाकर की जा रही है, जबकि विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि 'सेफ्टी ऑफिसर की एक खास तरह की ट्रेनिंग होती है, उन्हें ऐसी किसी ट्रेनिंग के बाद ही कोई महती जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।' डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय जो कि एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। उसने अपनी ताजा जांच में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा की बड़ी खामियों को उजागर किया है। अहमदाबाद हादसे के तुरंत बाद से ही डीजीसीए एक के बाद एक कई छोटे-बड़े एयरपोर्ट की जांच में जुटा है, जहां उसे तमाम स्तरों पर खामियां मिल रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि विमानन कंपनियां और हवाई अड्डों पर आपरेटर के तौर पर सेवाएं देने वाली कंपनियां नियमों की भारी अनदेखी कर रही हैं, जो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा बीसीएएस यानी 'ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी' जिसका काम एयरपोर्ट का ऑडिट करना भी है, डीजीसीए के साथ-साथ यहां भी मैनपॉवर की भारी कमी देखी जा सकती है। सो, ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी ही है कि क्या भगवान भरोसे चल रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट?

रनवे पर रबर डिपाजिट भी बन सकता है दुर्घटना का कारण: बारिश के मौसम में रनवे मेंटेनेंस का काम और भी जरूरी व चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि रनवे पर बारिश का पानी ठहरने की वज़ह से फिसलन हो सकती है ऐसे में लैंडिंग या टेकऑफ कर रहे विमानों के पायलट को भी खास सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे मौसम में रनवे मेंटेनेंस का काम सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। आमतौर पर जब विमानों की लैंडिंग होती है तो रनवे पर टायरों के रबर डिपोजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिसका असर रनवे की 'फ्रिक्शन वैल्यू' पर पड़ता है या आसान शब्दों में कहा जाए तो लगातार रबर डिपोजिट की वज़ह से रनवे की चिकनाहट बढ़ जाती है और इससे 'लैंडिंग' या 'टेकऑफ' के दौरान विमान के रनवे पर फिसलने का खतरा बना रहता है। आमतौर पर रनवे की फ्रिक्शन वैल्यू को नियमित तौर पर मापा जाता है, इसका 'विजुअल ऑब्जरवेशन' भी होता है, इसके अलावा भी अगर इस पर कहीं दरार वगैरह दिखती है तो उसकी फौरी मरम्मत भी की जाती है। बाकी रनवे से रबर डिपोजिट को मैनुअली या फिर एक खास मशीन द्वारा साफ किया जाता है चूंकि इस मशीन की लागत बहुत ज्यादा है सो, हर एयरपोर्ट पर उसे रखना संभव नहीं हो पाता। सो, इस मशीन को अलग-अलग जोन में रखा जाता है और खास एयरपोर्ट के डिमांड के हिसाब से उसे वहां भेजा जाता है। कई बार मशीन के वहां पहुंचने में देर हो जाती है तो निर्दिष्ट एयरपोर्ट मैनुअली ही रबर डिपोजिट हटाने का प्रयास करते हैं। अगर 'टच डाउन जोन' (जहां विमान का पहिया रनवे को टच करता है) का फ्रिक्शन वैल्यू तयशुदा सीमा के अंदर हो तो यह वहां विमान उतारने के लिए उपयुक्त है। जिस टच डाउन जोन का फ्रिक्शन वैल्यू तयशुदा सीमा का उल्लंघन कर रहा होता है, एयरपोर्ट ऑथरिटी को उसे नोटिफाई करना पड़ता है। फिर 'नोटस' होकर यह सूचना विमान के पायलट तक पहुंच जाती है, पायलट ऐसे नोटिफाइड एरिया को अपना टच डाउन जोन नहीं बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

दिल्ली में विकास और आईएएस अफसर : दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में भाजपा सरकार सभी विभागों को मजबूती से चलाने और दिल्ली में शानदार काम कराने के लिए देशभर के कोने-कोने से टाप क्लास आईएएस अफसरों को चार्ज दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता की अगुवाई में काम करने वाले ज्यादातर मंत्रियों का प्रशासनिक अनुभव शून्य है। चार आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनकी भूमिका सबसे अहम है। ये सभी पॉलिसी बनाने से लेकर इसे लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जैसे सीएम के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ए. अन्बारासू 96 बैच के आईएएस अफसर हैं जो पुडुचेरी से यहां लाए गए हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ 2006 बैच के यूपी कैडर के आईएएस कौशल राज शर्मा को बनाया गया है। इसी कड़ी में अन्य अफसर भी मोर्चों पर डटे हुए हैं। सो उन्हें सही कामकाज के लिए ये अफसर अलग-अलग विभागों में मोर्चा संभाले हुए हैं। पीडब्ल्यूडी हो या दिल्ली जल बोर्ड ये सभी अफसर फ्री हैंड लेकर काम कर रहे हैं और सबको पता है कि उन्हें ऊपर से मिले आदेशों का पालन करना है। अब सभी विभागों में कामकाज तेजी से हो रहे हैं, यानि दिल्ली तेजी से विकास की सही राह पर है।

बिहार में कांग्रेस राम भरोसे: बिहार कांग्रेस के नए-नवेले अध्यक्ष राजेश राम अपने करीबियों के समक्ष कई-कई दफे इस बात का दावा कर चुके हैं कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपने 85 फीसदी टिकट एससी, एसटी, पिछड़े-अति पिछड़े व मुसलमानों को देगी, यानी कि सवर्ण जातियों को कांग्रेस के कोटे से सिर्फ 15 फीसदी टिकट ही दिया जाएगा। समझा जाता है कि आरजेडी व वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में इस बार कांग्रेस के पास 40 सीटें आ सकती हैं, इसका 15 फीसदी यानी राम साहब की मानें तो अगड़ी जातियों के लिए सिर्फ 6 सीटों की ही गुंजाइश है। कांग्रेस के पास अभी 5 निर्वाचित फॉरवर्ड विधायक हैं, इन सबको फिर से टिकट देना संभवत: हाईकमान की मजबूरी हो सकती है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व अगड़ी भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले अखिलेश सिंह अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, इसकी अनदेखी शायद कांग्रेस शीर्ष के लिए संभव नहीं होगा। चर्चित पत्रकार रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडेय ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात लालू यादव से करवाई थी, ब्रजेश भी कांग्रेस टिकट के एक प्रबल दावेदार हैं। कहते हैं राजेश राम की ताजा मंशाओं को भांपते अगड़ी जातियों का अभी से कांग्रेस से मोह भंग होना शुरू हो गया है। कांग्रेस के कई फॉरवर्ड नेताओं ने तो सदाकत आश्रम का रुख करना ही छोड़ दिया है, वहीं राजद का कांग्रेस पर दबाव है कि वह ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न दें। राजेश राम जो औरंगाबाद की कुटुंबा रिजर्व सीट से मौजूदा विधायक हैं, वे इस बार यहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उन्होंने पार्टी शीर्ष को अभी से ताकीद कर दिया है कि चूंकि उन्हें घूम-घूम कर पूरे बिहार में कांग्रेस के पक्ष में अलख जगाना है तो वे एक सीट से बंध कर नहीं रहना चाहते।

भाजपा व अकाली फिर से करीब आ रहे : लुधियाना उप चुनाव के हालिया नतीजों ने भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को फिर से करीब आने का मौका दिया है। हालांकि अकाली दल काफी पहले से भाजपा के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने में जुटा था। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल ने अपने 'मैन फ्राइडे' कहे जाने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा के मार्फत फिर से भाजपा से पींगें बढ़ानी शुरू कर दी। सिरसा फिलवक्त दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और 2021 में ये व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए शिरोमणि अकाली दल छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में जिस तरह से छोटी-छोटी हार्डलाइनर पार्टियों का अभ्युदय हुआ है, इन पार्टियों ने अकाली दल की सियासी जमीन को और बंजर बनाने का काम किया है। सो, ऐसे में अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के लिए भाजपा एक बड़ी तारणाहार साबित हो सकती है। हालिया लुधियाना उप चुनाव में जहां आप के संजीव अरोड़ा 35179 वोट पाकर विजयी रहे, भाजपा यहां 20323 वोट पाने में कामयाब रही, वहीं शिरोमणि अकाली दल को 8203 वोट मिल गए तो कांग्रेस को 24542 मतों से ही संतोष करना पड़ा। अब अकाली दल-भाजपा को मिला दें तो दोनों के संयुक्त वोट 28526 हो जाते हैं यानी राज्य की दूसरी सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर यह गठबंधन उभर सकता है, भाजपा यह जानती है, सुखबीर के लिए भाजपा को यह बताते रहना उनकी सियासी मजबूरी है।

...और अंत में : जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भाजपा के करीबी रिश्ते रहे हैं। सो, 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों के जिन प्रतिनिधिमंडलों को अलग-अलग देशों में भेजा गया था उसमें से एक अहम दल की रहनुमाई इनको सौंपी गई थी। अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार के न्याय मंत्रालय ने आनन-फानन में संजय झा की दोनों वकील बेटियों यानी अद्या झा व सत्या झा को केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए ग्रुप 'ए' पैनल में शामिल कर लिया है। सनद रहे कि संजय झा की दोनों बेटियां दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से एलएलएम की डिग्री लेकर भारत आई हैं। सत्या जहां स्टेन फोर्ड लॉ कॉलेज से पढ़कर आई हैं तो अद्या ने अपनी कानून की डिग्री हॉवर्ड लॉ स्कूल से हासिल की है। झा साहब के रसूख का जरा आप अंदाजा तो लगाइए कि केंद्र सरकार ने इनकी दोनों बेटियों को एक ही दिन में ग्रुप 'ए' पैनल का काउंसिल बना दिया।

(www.parliamentarian.in)

केरल में नशा रोधी अभियान के लिए स्कूलों में चल रहा है जुंबा नृत्य

कोझिकोड, (पंजाब केसरी): केरल सरकार ने शनिवार को अपने नशा रोधी अभियान के तहत राज्य के विद्यालयों में जुंबा नृत्य शुरू करने के फैसले पर अडिग रहते हुए कहा कि इसका विरोध ''मादक पदार्थ से भी अधिक विषैला है।''

सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इस मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि लोगों का एक वर्ग जानबूझकर इस मामले को मुद्‌दा बना रहा है और ऐसा कुछ भी लागू नहीं किया जा रहा है, जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ''सरकार उन लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार है, जिन्हें इस संबंध में गलतफहमी है। लेकिन, हमने सरकार के मौजूदा रुख से पीछे हटने का कोई फैसला नहीं किया है।'' शिवनकुट्टी ने जुंबा नृत्य पर सरकार का रुख स्पष्ट किया क्योंकि कुछ मुस्लिम समूह इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि यह नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने अपने नशा रोधी अभियान के तहत राज्य भर के विद्यालयों में एक उच्च ऊर्जा वाला फिटनेस कार्यक्रम शुरू किया है।

मंत्री ने कहा कि राज्य के विद्यालयों में जुंबा, एरोबिक्स और योग जैसी गतिविधियों के क्रियान्वयन का कुछ वर्ग विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ये गतिविधियां नशा रोधी जागरूकता के हिस्से के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं।

शिवनकुट्टी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''इस तरह का विरोध समाज में मादक पदार्थों से भी ज्यादा घातक जहर घोल देगा। शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के बजाय, यह सांप्रदायिकता और संप्रदायवाद को बढ़ावा देगा।''

स्कूल की गतिविधियों में केवल हल्के व्यायाम शामिल हैं, जिन्हें बच्चे स्कूल की पोशाक में करते हैं। मंत्री ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) मानदंडों का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित सीखने की प्रक्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, ''इस मामले में माता-पिता के पास कोई विकल्प नहीं है। शिक्षक को आचरण नियमों के अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। किसी ने भी बच्चों को छोटे कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा है।''

सरकार की सक्रियता के कारण शून्य खुराक वाले बच्चों के प्रतिशत में आई कमी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भारत में कुल जनसंख्या में शून्य खुराक वाले बच्चों का प्रतिशत 2023 में 0.11 प्रतिशत से घटकर 2024 में 0.06 प्रतिशत रह गया है, जो देश को बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक उदाहरण के रूप में स्थापित करता है। बाल मृत्यु दर अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह की 2024 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, शून्य खुराक वाले बच्चों को ऐसे बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके माता-पिता की नियमित टीकाकरण सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है या फिर जिन्हें कभी भी टीकाकरण सेवाएं नहीं मिल पाती। इन बच्चों को डीटीपी (डिप्थीरिया-टेटनस-पर्टुसिस) की पहली खुराक तक नहीं मिलती है। मंत्रालय ने ऐसे बच्चों की संख्या में आई गिरावट का श्रेय सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के माध्यम से टीकाकरण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दिया। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में सालाना 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ शिशुओं (0-1 वर्ष) को निशुल्क टीकाकरण सेवाएं दी जाती हैं।

मंत्रालय ने साथ ही जोर देकर कहा कि जिन देशों में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, उनसे भारत की तुलना करते समय, हमारी विशाल आबादी और उच्च टीकाकरण दर को ध्यान में रखना होगा। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि टीकाकरण वर्तमान में सबसे शक्तिशाली और लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों में से एक है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए एक सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। बयान के मुताबिक, "हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मी आशा और एएनएम देशभर में 1.3 करोड़ से अधिक टीकाकरण सत्र आयोजित करते हैं।"

"देशभर में टीकाकरण अभियान के निरंतर प्रयासों और गहन कार्यान्वयन के नतीजतन, कुल जनसंख्या में शून्य खुराक वाले बच्चों का प्रतिशत 2023 में 0.11 फीसदी से घटकर 2024 में 0.06 फीसदी हो गया है।" बयान के मुताबिक, देश में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या को और कम करने के लिए चालू वर्ष में प्रगतिशील और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बयान में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी बाल मृत्यु दर आकलन समूह (यूएन आईजीएमई) की 2024 की रिपोर्ट में दर्शाई गई इन उपलब्धियों ने भारत को बाल स्वास्थ्य के मामले में वैश्विक आदर्श के रूप में स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अतिसार, निमोनिया, मेनिन्जाइटिस और एन्सेफलाइटिस के कारण बच्चों में मृत्यु दर और रोगों की संख्या को कम करने में जीवन रक्षक टीकों की बढ़ी हुई संख्या का असर भी साफ देखा जा सकता है। नवीनतम एसआरएस (2020-22) के अनुसार, भारत में बच्चों को जन्म देते समय महिलाओं का मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 2014-16 में प्रति लाख महिलाओं पर 130 था, जो घटकर 2020-22 में प्रति लाख पर 88 हो गया।

संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर-एजेंसी समूह (यूएन-एमएमईआईजी 2000-2023) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख महिलाओं पर 80 है, जो 1990 के बाद से 48 फीसदी की वैश्विक कमी के मुकाबले 86 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह (यूएनआईजीएमई 2024 रिपोर्ट) के अनुसार, भारत ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78 फीसदी की गिरावट दर्ज की है।

मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनाने के प्रयास जारी: एन. बीरेन सिंह

इंफाल, (पंजाब केसरी): मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में फिलहाल राष्ट्रपति शासन प्रभावी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य मुख्यालय में एक कार्यक्रम से इतर बोलते हुए सिंह ने उम्मीद जताई कि मणिपुर में बहुत जल्द ही नयी सरकार का गठन होगा। उन्होंने कहा, ''हम जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। जमीनी हालात को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि जल्द ही सरकार बनेगी। भाजपा और उसके सहयोगी दल भी एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं। हम लोकप्रिय सरकार की बहाली के लिए काम कर रहे हैं।'' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमने (भाजपा ने) किसी की आलोचना नहीं की है। हम केवल मौजूदा संकट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम राज्य में सौहार्दपूर्ण समाधान और शांति लाने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित व्यक्तियों से संपर्क कर रहे हैं। इस बीच, हम लगातार विधायकों की बैठकों के साथ एक लोकप्रिय सरकार को बहाल करने के लिए भी काम कर रहे हैं।'' सिंह ने कहा कि राज्य में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार रात दिन प्रयास कर रही है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा, ''मैंने पहले भी कहा है कि अवैध आप्रवासियों और मादक पदार्थ के तस्करों ने पूरे पूर्वोत्तर के साथ-साथ पूरे देश को प्रभावित किया है।'' इस बीच, भाजपा की मणिपुर इकाई की अध्यक्ष ए शारदा देवी ने एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा कि अब चुनाव का समय नहीं है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

एक्स से

दशकों तक सब यही मानते थे कि सोवियत संघ और दूसरे तानाशाह हर चीज के बारे में झूठ बोलते हैं। हमें उस दुनिया के आधिकारिक बयानों का इंतजार रहता था, जहां पारदर्शिता, स्वतंत्र मीडिया व जवाबदेही थी। अब? - गैरी कास्पारोव/पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन

वे समस्त कारण यथावत मौजूद हैं, जिन पर जंग छिड़ी थी।... लगभग दो हफ्ते चले इस युद्ध में अमेरिका भी अपनी समूची ताकत के साथ कूदा, पर हासिल क्या हुआ? कहते हैं कि ईरान के पास अभी भी 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है, जिसे कुछ हफ्तों में परमाणु आयुध में तब्दील किया जा सकता है। रही बात खामेनेई की, वह न केवल कायम हैं, बल्कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी तक चुन लिए हैं।

आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

ईरान अब नया अलाव है

शशि शेखर

आजकल

ईरान और इजरायल के बीच खूनी जंग भले ही थम गई हो, लेकिन इसे शांति का आगाज नहीं माना जा सकता। ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि शांति के स्वयंभू मसीहा डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के दिन फरमाया कि अगर ईरान ने यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम जारी रखा, तो अमेरिका बिला शक उस पर दोबारा बम बरसाएगा। इससे एक दिन पहले ईरान के सर्वेसर्वा आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर फिर हमला किया, तो उसे दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को भी जारी रखने पर प्रतिबद्ध है।

मतलब साफ है कि वे समस्त कारण यथावत मौजूद हैं, जिन पर जंग छिड़ी थी।

इजरायल ने हमले से पूर्व दावा किया था कि ईरान बहुत जल्दी परमाणु बम बना लेगा और वह हमारे अस्तित्व के लिए स्थायी खतरा बन जाएगा। दूसरा कारण यह बताया गया था कि हम तेहरान से आयतुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। खामेनेई राज न केवल अलोकप्रिय है, बल्कि औचित्यपूर्ण हुकूमत के नाम पर धार्मिक घृणा से भरे आतंकवादियों का संगठन है। लगभग दो हफ्ते चले इस युद्ध में अमेरिका भी अपनी समूची ताकत के साथ कूदा, पर हासिल क्या हुआ? कहते हैं कि ईरान के पास अभी भी 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है, जिसे कुछ हफ्तों में परमाणु आयुध में तब्दील किया जा सकता है। रही बात खामेनेई की, वह न केवल कायम हैं, बल्कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी तक चुन लिए हैं।

इस जंग में जीत-हार के दावे तो किए गए, परंतु इसकी हकीकत किसी को नहीं मालूम कि किस पक्ष का कितना नुकसान हुआ? इससे आक्रांता इजरायल का मकसद पूरा हुआ या नहीं? जवाबी हमलों से ईरान का प्रतिशोध कितना पूरा हुआ? इस युद्ध में अमेरिका क्यों कूदा? उसके पास तो आक्रमण करने का कोई वाजिब बहाना भी न था।

ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) की शर्तों से बंधा हुआ था। इसे और मजबूत करने के लिए उसकी अमेरिका से वार्ता जारी थी। हमले की तिथि के दो दिन बाद ही बातचीत का अगला दौर प्रस्तावित था। इसके बावजूद इजरायल ने इस दावे के साथ हमला बोल दिया कि उसने पहले से अमेरिका को विश्वास में ले रखा है। क्या यही वजह है कि इस युद्ध को निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया? उसने बी-2 बॉम्बर जैसे विशालकाय विमान और जीबीयू-57 जैसे महाकाय बम का इस्तेमाल किया। क्यों?

दरअसल, इस युद्ध का कोई नैतिक आधार भी नहीं था।

भरोसा न हो, तो इस तथ्य पर नजर डाल देखिए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने बार-बार कहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने का सामर्थ्य अभी तक हासिल नहीं कर सका है। बरसते प्रक्षेपास्त्रों के हत्यारे दिनों में भी उसने इस तथ्य को दोहराया, पर इजरायल और अमेरिका रुके नहीं। मतलब साफ है। ईरान पर हमले के कारण कुछ और हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, गाजा में अंतहीन अनर्थ से दिन-ब-दिन अलोकप्रिय होते बेंजामिन नेतन्याहू को इससे संजीवनी मिलनी थी? इजरायल में अगले साल आम चुनाव हैं और गाजा की हिंसा से उकताए लोगों को भरमाने के लिए अंध-राष्ट्रवाद की नई लहर की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने इस मकसद में फिलहाल सफल होते दिख रहे हैं।

नेतन्याहू मध्य एशिया के सबसे चतुर सियासी खिलाड़ी हैं। वह 1996 से अलापते आए हैं कि ईरान कुछ महीनों में परमाणु बम बना लेगा। सदी बदलने के साथ इसमें सिर्फ एक परिवर्तन हुआ। वह महीनों की जगह हफ्ते गिनाने लगे। आईएईए कहता रह गया कि ऐसा नहीं है, पर जोर से लगातार बोला गया झूठ अक्सर सच को पछाड़ देता है। यह काम तब और आसान हो जाता है, जब जनता इसे सुनना पसंद करती है। क्या इजरायल की जनता बेवकूफ है, जो तमाम नवाचारों की जननी होने के

बावजूद ऐसे झूठ पसंद करती है?

ऐसा नहीं है। कुछ दोष ईरान का भी है। इस्लामिक क्रांति के बाद उसने तेहरान के मुख्य चौराहे पर ऐसी घड़ी स्थापित की थी, जो इजरायल के अंत का समय बताती थी। हर पल वह वक्त कम होता जाता था। इस बेहूदी घृणा को भला कौन पसंद करेगा? यही नहीं, ईरान के हुक्मरां गाहे-बगाहे इजरायल के विनाश की कसम दोहराते रहते थे। पाकिस्तान ने कभी अपने परमाणु बम को 'इस्लामी बम' की उपाधि से नवाजा था। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को यहूदियों का संहारक कहता था। वह घड़ी इस हमले में ध्वस्त हो चुकी है, पर परमाणु कार्यक्रम?

यहां अमेरिका का झूठ और फरेब एक बार फिर बेनकाब होता है। 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच लंबी लड़ाई चली थी। उस समय अमेरिका और उसके पिट्ठू पश्चिमी देश इराक के साथ थे। सद्दाम हुसैन को एक से बढ़कर एक संहारक हथियार दिए जा रहे थे। अगले दशक में उसी इराक का अमेरिका ने क्या हाल बनाया? बगदाद में 'कॉरपोरेट बॉम्बिंग' के लिए झूठा कारण बताया गया था। कहा गया था कि उसके पास खतरनाक रासायनिक हथियार हैं, जो धरती के बाशिंदों के खिलाफ हैं। पूरी तबाही के बाद अंतरराष्ट्रीय निरीक्षकों ने पाया कि न तो इराक के पास ऐसे हथियार थे और न ही वह उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा था।

ईरान के साथ भी यही कुकृत्य दोहराया गया है। आईएईए की घोषणा और बीच बातचीत हमला अमेरिका व इजरायल की अपवित्र जुगलबंदी की एक बार फिर मुनादी करता है।

क्या इससे ईरान इस दिशा में बढ़ते कदम रोक देगा? कतई नहीं। तेहरान अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर है और उसने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की कसम जगजाहिर की है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और इजरायल एक कांटा दूर करने की कोशिश में चारों ओर कांटे बिखेर रहे हैं।

अच्छा हुआ, यह युद्ध रुक गया। यह संघर्ष पांव पसारता, तो भला इसकी क्या गारंटी कि मध्य एशिया के अन्य अरब देश इसकी चपेट में न आ जाते? सोमवार की रात ईरान ने कतर और इराक स्थित अमेरिकी अड्डों पर जो बम बरसाए, वह सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि उन देशों की प्रभुसत्ता पर भी हमला था। कतर ने तो बदला लेने की कसम भी खाई है। जान लें, इस क्षेत्र में अमेरिका के आठ सैन्य अड्डे हैं और ये सभी ईरानी मिसाइलों की जद में आते हैं।

यहां एक बात और गौरतलब है। संसार की दो और बड़ी सामरिक शक्तियां चीन व रूस प्रत्यक्ष तौर पर तो धमकाने की भाषा में विरोध जता रही थीं, पर अंदरखाने संघर्ष-विराम की पटकथा लिखी जा रही थी। ट्रंप ने जिस दिन युद्ध-विराम की घोषणा की, उससे एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को में थे। उन्होंने न केवल अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ लंबी बात की, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। चीन, रूस और अमेरिका मिलकर हालात को यूं ही साधे रहें, तो बेहतर रहेगा, पर खामेनेई व ट्रंप के ताजा वक्तव्य आशंकाओं के नए बीज रोप रहे हैं।

तय है, गाजा और यूक्रेन के बाद अब ईरान को दहशत का नया अलावा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीने की राह

शिल्पी सिंह
समाजसेविका

काश! हर पिता अपनी बेटी की लड़ाई लड़ सकता

जिस समाज में लड़कियों की मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी, उसमें तीन बेटियों के पिता अरुण सिंह ने एक बागी की तरह अपनी सबसे बड़ी बेटी शिल्पी को खुदमुख्तार बनाने का फैसला किया और इसकी शुरुआत कथक डांस एकेडमी में उन्हें दाखिला दिलाने के साथ हुई।

रोशनी की तलाश सबसे ज्यादा किसे होती है? अंधेरे कोनों को। मानव सभ्यता के विकास की समूची कहानी ही अंधकार के विविध रूपों को प्रकाश से पराजित करने की है। इसीलिए दूसरों की जिंदगी रोशन करने वालों को हमारा समाज सिर-माथे पर बिठाता आया है, बाज दफे उसने उनकी पूजा तक की। मगर ऐसे हर परमार्थी की यात्रा आसान नहीं होती। इसलिए बिहार के सबसे पिछड़े इलाके सीमांचल में जन्मी एक बेटी के काम को जब अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड व ब्रिटेन जैसे देशों ने सम्मानित किया, तब हमने उनके योगदान को जाना और सराहा। शिल्पी सिंह के काम की अहमियत किसी और से नहीं, बल्कि उन बच्चियों से पूछिए, जो विवाह के नाम पर बेचे जाने से बच गईं। धूमिल ने कहा है- *लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो, जिसके मुंह में लगाम है!*

आज से करीब 41 साल पहले कटिहार की इमरजेंसी कॉलोनी में जन्मी शिल्पी के दादा वैद्यनाथ सिंह रेलवे के बड़े ठेकेदारों में से एक थे। जाहिर है, परिवार के पास दौलत की कोई कमी न थी, मगर सामंती ठसक को बड़े बेटे की हिमाकतों से काफी ठेस पहुंची। दरअसल, वैद्यनाथ सिंह चाहते थे कि बड़े बेटे अरुण कुमार सिंह (शिल्पी के पिता) इंजीनियर या वकील बनें, मगर अरुण को यह गवारा न था। वह जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के कायल थे। जयप्रकाश आंदोलन ने उन्हें समाज सुधार और राष्ट्र-निर्माण के मार्ग पर उतार दिया था। जाहिर है, परिवार उनकी इन गतिविधियों से खुश नहीं था।

जिस समाज में अरुण जी रहे थे, उसमें लड़कियों और महिलाओं की स्थिति उन्हें विचलित करती थी। उन दिनों दसवीं पास करते ही इमरजेंसी कॉलोनी की ज्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती। कुछ को अगर कॉलेज का मुंह देखना नसीब भी होता, तो उसके पीछे विवाह ही मकसद होता, ताकि माता-पिता को अच्छे रिश्ते तलाशने में सुभीता हो। लड़कियों की मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी। ऐसे में, तीन बेटियों के पिता अरुण सिंह ने एक बागी की तरह अपनी सबसे बड़ी बेटी शिल्पी को खुदमुख्तार बनाने का फैसला किया और इसकी शुरुआत कथक डांस एकेडमी में उन्हें दाखिला दिलाने के साथ हुई।

हंगामा तो मचना ही था। क्योंकि यह सिर्फ रूढ़ियों से बगावत नहीं थी, बल्कि अनगिन दमित आकांक्षाओं को उकसाने वाली कार्रवाई थी। मगर न अरुण घर-समाज के तंज-तानों के आगे झुके, न शिल्पी ने पिता के सपनों से कभी मुंह मोड़ा। ऐसा नहीं कि नन्ही शिल्पी को बुरा नहीं लगता था। लगता था। तब तो और, जब खुद दादा क्रोध में कहते- 'बेटी के बियाह के लिए जब अरुणवा जाएगा, तब लड़का वाला पूछेगा, क्या करते हैं? तो यह कहेगा कि बाप ढोलकिया है, बेटी नचनिया है।'

मगर जब-जब शिल्पी रुआंसी होतीं, पिता यही कहते- 'तुम्हें तो पूरे जमाने से लड़ना है। एक फौजी की तरह खुद को

मजबूत करो।' उस मानसिक प्रशिक्षण का ही नतीजा था कि एक पिछड़े जिले की महज छह साल की शिल्पी को पटना के कालिदास रंगालय में कथक प्रस्तुत करने का मौका मिला। भीड़ के सामने बेखौफ होकर खुद को अभिव्यक्त करने के उस वाकये ने शिल्पी में अदम्य आत्म-विश्वास भरा।

उसके बाद तो पिता ने एक पल के लिए भी बेटी को हीनता-ग्रंथि का शिकार नहीं होने दिया। वह उन्हें साथ लेकर तमाम तरह की गतिविधियों में शरीक होते, ताकि छुटपन से ही शिल्पी सामाजिक विसंगतियों से दो-चार हो जाएं। उनके लिए मानो पिता ही स्कूल-कॉलेज हो गए थे। अकादमिक डिग्री के साथ-साथ पिता द्वारा 1996 में स्थापित गैर-लाभकारी संगठन 'भूमिका विहार' से वह काफी कुछ सीखने लगीं। शिल्पी को किस तरह तराशा गया, इसकी एक बानगी यह है कि कटिहार में उन दिनों जब डेढ़ बजे रात में बिजली आती, तब पिता नींद से जगाकर उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाते थे।

उन्हें शायद यह इलहाम था कि समाज की बेबस बेटियों की एक बड़ी लड़ाई उनकी बेटी लड़ेगी और इसके लिए उसे बहुत कुछ जानना-समझना होगा। किडनी की बीमारी से 2013 में जब पिता ने अचानक दुनिया छोड़ी, तब 29 साल की शिल्पी के कंधों पर कैंसर पीड़ित मां और किशोरवय छोटी बहन के साथ-साथ भूमिका विहार की समूची जिम्मेदारी आ पड़ी। साल 2013 से उन्होंने जिस हौसले से इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाया है, उस पर पूरे बिहार और हिन्दुस्तान को फख्र होगा। संस्था की दुर्गा जत्था और बालिका पंचायत इकाइयों के जरिये उन्होंने अब तक 22,000 से अधिक बच्चियों को विवाह के नाम पर बेचे जाने या बाल विवाह से बचाया है।

यह सब कितना जोखिम भरा है, इसे यह एक घटना बयां कर देगी- जून 2017 में शिल्पी को पता चला कि समेली गांव में एक बालिका की शादी कराई जा रही है। वह जब इसे रोकने पहुंचीं, तो गांव वालों का भारी विरोध झेलना पड़ा। लड़की की मां कुल्हाड़ी लेकर शिल्पी को मारने दौड़ पड़ी, मगर मौके पर मौजूद पुलिस बल की मदद से वह उस बच्ची को बचाकर ले आईं। आज सीमांचल की हजारों लड़कियां भूमिका विहार से जुड़ी हैं। शिल्पी की प्रेरणा से वे सभी स्कूल जाती हैं, सरकारी योजनाओं से वाकिफ हैं और उनके लाभ उठा रही हैं।

इन दिनों शिल्पी 'डिजीप्ले पाठशाला' पहल का नेतृत्व कर रही हैं। इसके तहत मुसहर, पासवान आदि वंचित जातियों के 1,000 से भी अधिक बच्चे और लड़कियां स्टेम लर्निंग, यानी

साल 2013 से उन्होंने जिस हौसले से इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाया है, उस पर पूरे बिहार और हिन्दुस्तान को फख्र होगा। संस्था की दुर्गा जत्था और बालिका पंचायत इकाइयों के जरिये उन्होंने अब तक 22,000 से अधिक बच्चियों को विवाह के नाम पर बेचे जाने या बाल विवाह से बचाया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। शिल्पी को साल 2009 से ही कनाडा, नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों से फेलोशिप और सम्मान मिलते रहे हैं। मगर उनका असली पुरस्कार तो यह है कि जो लोग उनके संघर्ष को लांछित करते रहे, उनका बहिष्कार करते रहे, वे अब इज्जत के साथ न्योता देने आते हैं। सात साल के आद्विक की मां शिल्पी अपनी हर सभा में यह जरूर कहती हैं- अपनी बेटियों के लिए लड़ने वाले हर बाप को मेरा सलाम!

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

प्रशांत चंद्र महालनोबिस
सांख्यिकीविद्

सच्चाई और गणित का दिलचस्प मेल

उन्हें पता चला कि जहाज को आने में कुछ घंटे लग जाएंगे। सवाल खड़ा हो गया कि इंतजार के इन घंटों का क्या किया जाए? दूसरा कोई होता, तो आस-पास सैर करने निकल जाता, पर उन्होंने वह समय पुस्तकालय में लगाने का फैसला किया। पहुंच गए किंग्स कॉलेज के शानदार पुस्तकालय।

ज्ञान में बहुत रस है। आप इसका रसास्वादन करते चले जाते हैं। हो सकता है, आपका मन भर जाए, पर रसों का कभी अंत नहीं होता। इन रसों में भी इतनी विविधता है कि गिनना कठिन है। इंग्लैंड में पढ़ रहे उन बांग्लाभाषी युवक को साहित्य-संगीत में भी इतना रस आता था कि महाकवि टैगोर का भी स्नेह हासिल था। विडंबना देखिए, उन दिनों युवक महोदय इंग्लैंड में विज्ञान पढ़ रहे थे। पूरे मन से वह पढ़ते थे और जिस भी परीक्षा में बैठते थे, कामयाबी कदम चूमने लगती थी।

उनके स्वभाव में था कि एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। घर से हम सिर्फ पढ़ने आए हैं और अगर हम यहां पढ़ने के अलावा कुछ भी करते हैं, तो इसका मतलब है, हम अपने घर से आई गाढ़ी कमाई के साथ अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं।

बहरहाल, उन दिनों कॉलेज में अवकाश था, तो कुछ दिनों के लिए कोलकाता लौटना था। घर जाने के लिए तमाम जरूरी सामान बैग में रखकर इंतजार था, पर उन्हीं दिनों प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, पता चला कि जहाज को आने में कुछ घंटे लग जाएंगे। अब सवाल खड़ा हो गया कि इंतजार के इन घंटों का क्या किया जाए? दूसरा कोई होता, तो कहीं आस-पास सैर करने निकल जाता, पर उन्होंने वह समय पुस्तकालय में लगाने का फैसला किया। पहुंच गए किंग्स कॉलेज के शानदार पुस्तकालय में, तय किया कि कुछ अलग हटकर रस लिया जाए। पुस्तकालय में इधर-उधर कुछ तलाशने के बाद उनकी नजर *बायोमेट्रिका* के नए अंक पर पड़ी। उन्होंने उस अंक के पन्नों को पलटना शुरू किया। प्रकाशित आलेखों में आंकड़ों, टेबल, ग्राफिक्स की गजब बाजीगरी थी। किसी आलेख में शिक्षा संबंधी आंकड़े थे, तो किसी में बदलती चिकित्सा का जायजा लिया गया था। किसी आलेख में जीव-जंतुओं की संख्या का रोचक अध्ययन था। फिर क्या था, वह मोहित हो गए। आंकड़े बहुत काम के होते हैं। आंकड़े अनुमान नहीं लगाते। आंकड़े सिर्फ हकीकत बयान करने की कोशिश करते हैं। संसार की बहुआयामी सच्चाइयों और गणित के सुंदर मेल से सुसज्जित *बायोमेट्रिका* ने कमाल का असर डाला। यह तो सांख्यिकी को समर्पित शानदार शोध अंक है।

उस अंक को पढ़ते हुए दिलो-दिमाग तेज दौड़ने लगा। भौतिकी क्या है? प्रकृति के बुनियादी नियमों और ब्रह्मांड के कार्य के तरीकों को समझने की कोशिश। दूसरी ओर, यह सांख्यिकी है- जिसका पूरा ध्यान आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण, प्रस्तुति पर है। मन से आवाज उठी कि भौतिकी से भी शायद ज्यादा दिलचस्प सांख्यिकी है। सांख्यिकी में विज्ञान भी है और कला भी।

देखते-देखते जहाज का समय हो गया, पर *बायोमेट्रिका* से जी न भरा। चलते-चलते युवक ने *बायोमेट्रिका* का एक पूरा सेट खरीद लिया कि जहाज में बैठे-बैठे दो से चार सप्ताह का समय मिलेगा, रास्ते भर पढ़ते चलेंगे। यही हुआ और लौटती यात्रा में भौतिकी के युवा विद्वान सांख्यिकी पर फिदा हो गए। स्वयं भी कागज-कलम लेकर आंकड़ों के विश्लेषण में जुट गए। भांति-भांति के सांख्यिकी सूत्रों को आजमाने लगे। सफर बहुत आराम से कट गया और कोलकाता आ गया। पुस्तकालय में कुछ समय बिताने के एक फैसले से जिंदगी बदल चुकी थी।

विश्व युद्ध जारी था, तो इंग्लैंड लौटना मुश्किल था, इसलिए वह कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज में भौतिकी पढ़ाने लगे, पर दिल तो सांख्यिकी में बसता था। सांख्यिकीय विश्लेषण का ऐसा जुनून सवार था कि जहां से भी उन्हें कुछ आंकड़े मिलते थे, वह विश्लेषण में जुट जाते थे। वह सदा नए-नए आंकड़ों की तलाश में रहते थे और विद्वानों की दुनिया उन्हें प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से पहचानने लगी थी।

भौतिकी के प्रोफेसर ने साल 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) की स्थापना की और 1933 में पहली भारतीय सांख्यिकी पत्रिका *सांख्य* का भी प्रकाशन शुरू किया। उनके ज्ञान का लोहा खुद अंग्रेज मानते थे। सांख्यिकी की दुनिया में उन्हें एक मौलिक विद्वान के रूप में पहचाना गया। सांख्यिकी ने उन्हें एक मौसम विज्ञानी के रूप में भी स्थापित कर दिया। वह कॉलेज में 30 वर्ष तक भौतिकी पढ़ाते रहे और भारतीय सांख्यिकी संस्थान को भी नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहे। आजाद देश ने भी महालनोबिस को पूरा सम्मान दिया और देश के विकास के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने में वह कभी पीछे नहीं रहे।

29 जून को जन्मे महालनोबिस (1893-1972) भारतीय सांख्यिकी के पितामह हैं। उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वह बता गए कि सांख्यिकी केवल गणित की एक शाखा ही नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय विकास और सामाजिक कल्याण का एक जरूरी औजार है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

कृत्रिम बुद्धि की दगाबाजी पर गुस्सा

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

कामायनी पढ़ रहा था, तभी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से जुड़ी खबर पढ़ी, जो कह रही थी कि कृत्रिम बुद्धि (एआई) काफी आगे है और आज की कृत्रिम बुद्धि दुनिया के किसी भी मनुष्य की बुद्धि से अधिक शक्तिशाली है। जब से कृत्रिम बुद्धि 'ओपन आई' के एग्जीक्यूटिव ऑल्टमैन ने यह बात कही है, तभी से मेरा मन आपके मन की तरह आहत है।

बताइए! मनुष्य ही मनुष्य को हीन बना रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा। कल तक यही पश्चिम मनुष्य को सबसे ऊपर रखता था। दार्शनिक देकार्त ने तो आधुनिक मनुष्य की एक पक्की परिभाषा तक दे दी, जिसे आज तक माना जाता है कि 'मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं', अर्थात् मनुष्य सोचने वाला प्राणी है, बुद्धिवादी है, इसीलिए वह अस्तित्ववान है।

अब वही पश्चिम यह खबर दे रहा है कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है, जबकि अधिकतम बुद्धि चैटजीपीटी या ओपन आई जैसी कृत्रिम बुद्धि के पास ही है। कृत्रिम बुद्धि के इस ज्ञानी द्वारा की जाती ऐसी तारीफ सुन कौन बुद्धिजीवी होगा, जो इसे अपनी तौहीन न समझेगा?

इस कृत्रिम बुद्धि से अधिक हमें तो पश्चिम के ज्ञानियों की इस दगाबाजी पर गुस्सा आता है, जो कल तक हमें समझाते रहे कि मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं, यानी सोचने वाला प्राणी सिर्फ मनुष्य है, उसके पास बुद्धि है, वही तर्क प्रधान है!

देकार्त साहब लगे हाथ यह भी सिखा गए कि आदमी को हर बात पर संदेह करना चाहिए। सवाल पूछने चाहिए, ताकि हम सजग रहें! अब उन्हीं के चेले हमें बता रहे हैं कि दुनिया का कोई आदमी चैटजीपीटी का मुकाबला नहीं कर सकता। वह बुद्धिजीवियों की भी बुद्धिजीवी है!

पश्चिम वाले दगाबाज होते हैं। पहले हमें ज्ञानोदय (एनलाइटनमेंट) दिया, ज्ञानी बनाया और अब उसको उलट रहे हैं, अपनी कृत्रिम बुद्धि को बेच रहे हैं। न ये खुद चैन से रहते हैं, और न हमें रहने देते हैं! वे इसी तरह सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं और एक बार फिर बना रहे हैं। ये कृत्रिम बुद्धिजीवी हमारे जैसे मामूली लोगों को इसी तरह से नीचा दिखाते रहते हैं।

जब से यह सब पढ़ा है, मेरा मूड खराब है और मैं सोच रहा हूं कि कृत्रिम बुद्धि की इस दादागीरी का कुछ तो तोड़ होगा? इसी चक्कर में मुझे अचानक छायावाद के प्रख्यात महाकवि प्रसाद जी के महाकाव्य *कामायनी* की याद आई और लगा कि *कामायनी* की इड़ा भी एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धि ही है।

कामायनी में प्रसाद जी इड़ा के रूप को जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, वह आज की किसी चैटजीपीटी से कम नहीं लगता। लेकिन प्रसाद जी उसे सर्वेसर्वा नहीं बनाते। उसको नियंत्रित रखने के लिए वह श्रद्धा को उसके साथ लगा देते हैं, ताकि वह जैसी मशीनी है, वैसी न रहे और कुछ मानवीय गुणों से युक्त हो जाए!

लेकिन हम ऑल्टमैन साहब को कैसे बताएं कि सर जी! अपने महाकवि प्रसाद जी ने तो 1937 के आसपास ही कृत्रिम बुद्धि के आइडिया को विकसित कर लिया था, जिसका पहला मॉडल वह *कामायनी* में इड़ा के चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस हिसाब से तो कृत्रिम बुद्धि आज से लगभग 88 बरस पहले पैदा हो चुकी है।

इड़ा का पहला परिचय प्रसाद मनु की नजर से इस प्रकार देते हैं- *बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल...* /इड़ा मनु के जरिये एक नई आधुनिक सभ्यता का निर्माण और विकास करती-कराती है, लेकिन वह हृदयहीन भी है। मनु के अहंकार के कारण जब यह आधुनिक सभ्यता ध्वस्त होती है, तो श्रद्धा इड़ा को भी इसके लिए जिम्मेदार मानती है और एक प्रसंग में इड़ा से सीधे कहती है: *सिर चढ़ी रही पाया न हृदय!*

इड़ा के रूप में प्रसाद जी पहली कृत्रिम बुद्धि की कल्पना करते हैं और आलोचना भी पेश करते हैं कि उसके पास तर्कजाल तो है, पर हृदय नहीं है। आज की चैटजीपीटी के लिए भी यही कहा जा सकता है, सिर चढ़ रही, पाया न हृदय!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान है

बेकार की बहस

इसमें हर्ज नहीं कि संविधान पर फिर बहस चल निकली, लेकिन यह ठीक नहीं कि आपातकाल के समय जब लगभग पूरा विपक्ष जेल में था, तब संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने पर घिसी-पिटी बहस ही हो रही है। यह बहस इसलिए हो रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी की ओर से 1975 में आपातकाल थोपे जाने और लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दमनचक्र चलाए जाने के घोर अलोकतांत्रिक फैसले के 50 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर जो कुछ कहा और लिखा गया, वह कांग्रेस को रास नहीं आया। उसने खुले-छिपे शब्दों में यह जताने में संकोच नहीं किया कि उसे इंदिरा गांधी के लोकतंत्र को कलंकित करने वाले फैसले की निंदा-आलोचना पसंद नहीं। देश जानना चाहेगा कि क्यों नहीं पसंद? देश यह भी जानना चाहेगा कि क्या जब संविधान में पंथनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे, तब भारत पंथनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों का वाहक नहीं था। भारत तो यूरोप में सेक्युलर शब्द के प्रचलन में आने के सदियों पहले सर्वपंथ समभाव अर्थात पंथनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का हामी था। यह विचित्र है कि जिसकी जरूरत संविधान निर्माताओं और यहां तक कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नहीं समझी, उसकी इंदिरा गांधी ने क्यों समझी? क्या यह सत्य नहीं कि अपने निर्वाचन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रतिकूल फैसले के चलते प्रधानमंत्री पद का त्याग करने से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपकर संविधान की प्रस्तावना बदली? यह कहना बौद्धिक बेईमानी है कि संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट लिखे जाने से भारत पंथनिरपेक्ष और समाजवादी हो गया। सेक्युलरिज्म का सही पर्यायवाची पंथनिरपेक्षता है, लेकिन प्रचलन में धर्मनिरपेक्षता है। आखिर कोई देश और कम से कम भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्म का अर्थ है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कर्तव्य। क्या भारत को इससे निरपेक्ष हो जाना चाहिए? क्या यह किसी और विशेष रूप से कांग्रेस से यह छिपा है कि समाजवाद ने देश का कैसा बेड़ा गर्क किया है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आज के अनेक कथित समाजवादी नेता कितने पाखंडी और परिवारवादी हैं। आज तो समाजवाद घनघोर जातिवाद का भी पर्याय बन गया है। अच्छा हो कि देश बेकार की और समय जाया करने वाली बहस से बचे और ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श हो, जिससे देश की जनता को कोई दिशा मिले और उसका भला हो। कांग्रेस को यह भी याद रहे तो अच्छा कि वह जिन भीमराव आंबेडकर की हितैषी बन गई है, वे संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। वे तो विभाजनकारी और कश्मीर में अलगाव पैदा करने वाले अनुच्छेद 370 के भी विरोधी थे।

सशक्त पुलिस बल की पहल

पुलिस बल को और मजबूत करने के लिए सरकार ने 20 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है, यह युवाओं को नौकरी का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी एक अच्छी पहल है। शनिवार को 21, 391 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया। रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति से यह आशा की जानी चाहिए कि विधि व्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब अधिकारियों का दायित्व बनता है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए रणनीति बनाते हुए उचित कार्रवाई की जाए, ताकि आम जन में इसका संदेश भी जाए। हाल के दिनों में पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से बार-बार कहा कि अगले महीने ही नियुक्तियां हो जानी चाहिए। इस पर तीव्र गति से कार्य किया जाना चाहिए। सरकार ने विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए मानव बल की स्वीकृति देने के साथ ही समय सीमा में नियुक्ति कार्य संपन्न करने की अपेक्षा भी जताई है। सरकार ने दो वर्ष पहले पुलिस बल में मानव संसाधन 2.29 लाख करने का निर्णय लिया था, जबकि 2005 में यह 51 हजार के लगभग था। गांव-शहरों के विकास और बढ़ती आबादी के साथ पुलिस बल को बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता समय की मांग थी। इस दिशा में जो पहल की गई है, उसे शीघ्रताशीघ्र लागू किए जाने की जरूरत है।

बढ़ती आबादी के साथ पुलिस बल को बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता समय की मांग

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए पंथनिरपेक्ष शब्द की समीक्षा होनी चाहिए?

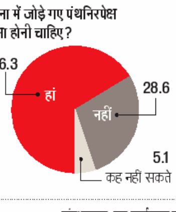

आज का सवाल

क्या चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा का विपक्षी दलों की ओर से विरोध सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

जस्टिस यशवंत वर्मा हाजिर हों!

अरविंद जैन

कूड़े को कालीन तले छिपा कर, न्यायिक संस्थाओं की छवि को कब तक विश्वसनीय रखा जा सकता है?

वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग (1788-1795) की बहस में सांसद और वकील एडमंड बर्क ने कहा था- सत्य, न्याय और इंसाफ के लिए कानून के मार्ग पर जो राष्ट्र चलता है, वही महान है। बेहद गंभीर आरोपों और पर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद ब्रिटिश संसद ने हेस्टिंग्स को बेकसूर माना और कंपनी ने उन्हें 4,000 पौंड सालाना पेंशन भी दी। शायद सत्ता अपने लाडले सपूतों के बचाव में ऐसे ही न्याय के नाटक-नौटंकी करती रही है। 14 मार्च, 2025 को दिल्ली के एक बंगले के स्टोर रूम में आधी रात आग लगने से धुंआ उठने लगा। आग में जलते नोटों के ताप से कांच की बोतलें टूटने और शराब बहने से आग और भड़क उठी। आग में शराब ने घी से भी अधिक खतरनाक काम किया। बंगला दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को आवंटित था। दमकल, पुलिस आई, आग बुझाई, वीडियो बनाई और जले-अधजले या बचे करोड़ों रुपये और शराब की बोतलों को यूं का यूं छोड़ चली गई। कोई पंचनामा (एफआइआर) या बरामदगी नहीं की गई। घटना के समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। अगले दिन आए तो घटनास्थल पर शेष-अशेष कुछ न था। विश्वासपात्र सचिव और अन्य सेवकों ने सब साफ-सफाई कर दी। मीडिया में हफ्ते भर तक कोई खबर नहीं। कैश कांड की जानकारी गोपनीयता और संवेदनशीलता के घूंघट में उच्चाधिकारियों, न्यायाधीशों के बीच घूमती रही। अदालत के गलियारों में धुंआ, धूल और धुंध...खामोशी का षड्यंत्र गहराता रहा, अटकलों का बाजार गर्माता गया। कुछ पत्रकारों ने पर्दा हटाना शुरू किया तो पहले जज साहब को न्यायिक कार्य न करने के निर्देश और फिर इलाहाबाद वापस जाने के आदेश जारी हुए। कैश कांड की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने की सिफारिश करके गेंद संसद के पाले में लुढ़का दी और खुद सेवानिवृत्त हो गए। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अधिकांश दस्तावेज (जांच रिपोर्ट के अलावा) सार्वजनिक करने पड़े। न जाने कैसे जांच रिपोर्ट बाद में लीक हो गई। जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनु शिवरमन शामिल थे।

फिलहाल महाभियोग की पेचीदा प्रक्रिया चलाने या न चलाने के मुद्दे पर वाद-विवाद, सहमति-असहमति की राजनीति के इर्द-गिर्द ही वरिष्ठ वकीलों द्वारा सार्वजनिक रूप से कानूनी तर्क-वितर्क रचे जा रहे हैं। कानून मंत्री सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने में प्रयासरत हैं। एक ओर न्यायपालिका में आमजन की आस्था बचाए रखने के लिए और संसद को इस मामले पर बहस करने, वोट देने और अभियोग सिद्ध करने की दुःसाध्य जटिलता से बचाने के लिए यह सलाह दी जा रही कि जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे दें, ताकि न्यायपालिका और संसद का धर्मसंकट से बचाव हो सके। दूसरी ओर उपलब्ध तथ्यों पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सांसदों में वकील और वकीलों में सांसद के रूप में जाने-पहचाने चेहरे रोज नया रास्ता तलाश-तराश रहे हैं।

कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं, पर यथार्थ यह भी है कि न्याय मंदिरों के विशाल प्रांगण में भी भ्रष्टाचार के विष-वृक्ष अप्रत्याशित रूप से फलते-फूलते रहे हैं। यौन शोषण से लेकर आर्थिक धांधली तक के आरोपों में अकसर लीपापोती होती रही और अधिक हुआ तो न्यायाधीशों से इस्तीफा लेकर बाइज्जत मुक्त कर दिया गया। विचारणीय है कि कूड़े को कालीन तले छिपा कर न्यायिक संस्थाओं की छवि को कब तक विश्वसनीय रखा जा सकता है? इस्तीफा के बारे में सोचते ही न्यायाधीश शामित मुखर्जी सामने आ खड़े होते हैं, जिन पर आपराधिक मामला अभी तक लंबित है। इससे इन्कार नहीं कि शायद कोई न कोई दल जस्टिस वर्मा को भी वैसे ही बचा ले, जैसे कांग्रेस ने वाकआउट करके जस्टिस रामास्वामी को बचाया था। कांग्रेस जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग कर रही है। राजनीति के अपराधीकरण के मौजूदा दौर में अनुमान लगाना मुश्किल है कि अंतिम क्षणों में क्या फैसला लिया या नहीं लिया जाएगा।

अवधेश राजपूत

संदेह और सवालों का घेरा बढ़ रहा है। यदि कथित करोड़ों रुपये वर्मा जी के नहीं थे तो किसके थे? अगर यह उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र है तो ऐसा कौन है, जो रकम और शराब स्टोर रूम में प्लांट कर-करा सकता है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? खुद न्यायाधीश महोदय ने कोई उचित कार्यवाही या शिकायत क्यों नहीं की? बिना किसी विरोध-प्रतिरोध वापस अपने घर (इलाहाबाद) कैसे चले गए? आज तक अग्निकांड में जला-अधजला एक भी नोट बरामद नहीं हुआ। क्या अस्थियां सत्ता के संगम में प्रवाहित कर दी गईं या व्यवस्था के किसी गंदे नाले में? कानून और न्याय व्यवस्था में आस्था बचाए रखने के लिए जांच तो करनी-करानी ही पड़ती है। इसे 'सत्यमेव जयते' कहो या 'यतो धर्मा स्ततो जय'!

जस्टिस वर्मा के विरुद्ध संसद के जुलाई सत्र में महाभियोग आ सकता है, पर इसमें अनेक 'किंतु-परंतु' हैं। महाभियोग के लिए राज्यसभा के 50 या लोकसभा के सौ सांसदों का हस्ताक्षरित प्रस्ताव अनिवार्य है। जजे'ज इंक्वायरी एक्ट, 1968 की धारा-3 के अनुसार संसदीय समिति को स्वतंत्र जांच करनी होगी, तीन न्यायाधीशों की जांच रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में मौजूद सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए। रामास्वामी के महाभियोग के समय उनका बचाव नेता एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (प्रधान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने किया था। न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच वर्चस्व के शीतयुद्ध में विवेकहीन बिखराव घटता-बढ़ता रहता है। देखना है लोकतंत्र के प्रहरी राष्ट्रहित में क्या निर्णय लेते हैं। 'रिमोट कंट्रोल' से संचालित आवारा पूंजी के अभेद्य चक्रव्यूह में अनेक यशवंतों की भूमिका रहती है। यदि वक्त रहते न्याय एवं कानून व्यवस्था की देखभाल नहीं की गई तो स्थितियां बेकाबू और भयावह हो सकती हैं।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं)

response@jagran.com

सिद्धांत वही जो दूसरों के काम आएं

हास्य-व्यंग्य

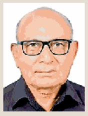

सूर्यकुमार पांडेय

आदमी जीवन में तमाम सिद्धांत बनाता है, लेकिन उन पर तभी तक चल पाता है, जब तक मामला गैरों से जुड़ा हो

उस रोज मंत्री जी के बंगले पर जाना पड़ा। मेरे सगे भाई की नौकरी का प्रसंग था। वह बोला, 'भाई साहब, आप कह देंगे, तो हो सकता है, काम बन जाए!' मैं ठहरा आदर्शवादी। मुझे जीवन भर सोर्स-सिफारिश जैसी चीजों से परहेज रहा। मगर सगे भाई का काम था इसलिए ना करते नहीं बना। मैंने भी सोचा, जिंदगी में कई काम ऐसे भी करने पड़ते हैं, जिनके लिए आत्मा गवारा नहीं करता। आदमी तमाम सिद्धांत बनाता है, उन पर चलने की कोशिशें भी करता है, पर यह तभी तक संभव हो पाता है, जब गैरों का मामला हो। अपने लिए सिद्धांतों से विचलन का चलन पाया जाता है।

मेरे एक मित्र थे। निहायत ईमानदार। सरकारी नौकरी में थे, तब भी ईमानदार बने रहे। उलटे जिसका काम करते, उसी को चाय पिलाते। उन्होंने नौकरी में ऊपर का एक पैसा नहीं लिया। जो कमाया, वेतन से कमाया। तब एक वक्त ऐसा भी आया, जब अपने लड़के की नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत देने में उन्होंने एक मिनट की देरी नहीं की। ईमानदारी की सारी कमाई घूस में परिवर्तित हो गई। सगे खून के आगे सिद्धांतों का खून करने में उन्हें कतई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ था। मैंने पूछा, तो बोले, 'यार, क्या करता? बेटे की नौकरी का सवाल था। बड़ी मुश्किलों से जुगाड़ लगा था। यों भी आजकल नौकरियां कहां मिलती हैं? एक-दो साल और निकल जाते तो बेटा ओवरएज हो जाता।' जब ऐसी ही परिस्थिति मेरे सामने आई तो मैंने अपने उस मित्र का पुण्य-स्मरण किया। बड़ा बल मिला। जब मेरा वह ईमानदार मित्र अपने लड़के की नौकरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की ईमानदारी की कमाई को तिलांजलि दे सकता है, तो क्या मैं अपने सगे भाई के लिए मंत्री जी के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता था? मैंने स्वयं को समझायाः रे मनमूरख, ये सिद्धांत-विद्धांत दूसरों के लिए हुआ करते हैं।

अगर कोई अपने काम के लिए आपके पास आए और आप नहीं करना चाहते हैं, तो उससे कहिए-'भाई, अपना तो उसूल है, जो भी करेंगे, नियमानुसार करेंगे। माफ कीजिएगा, हम दुनिया त्याग सकते हैं, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकते।' फिर वह भी ऊपर से आपको परम आदर्शवादी और भीतर से महा कमीना समझता हुआ कहेगा- 'छोड़िए भी। आपका सिद्धांत आड़े आता है, तो कोई बात नहीं। काम तो किसी और तरीके से भी कराया जा सकता है, लेकिन आप जैसा सिद्धांतवादी आज के जमाने में चिराग लेकर ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेगा।' वह आपके पैर छुएगा और भीतर-ही-भीतर दोबारा आपके दरवाजे का रुख न करने की कसम खाता हुआ विदा लेगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा, जब आपका कोई काम उससे पड़ेगा। आप उससे मिलेंगे तो वह मुस्कुराएगा। आप कहेंगे-'यार, नियम से तो नहीं हो सकता, पर कैसे भी कर-करा दो। करीब के रिश्तेदार का केस न होता तो मैं कहने ही न आता। अपना सिद्धांत जो ठहरा, पर क्या करूं? इतना दबाव है कि दुनियादारी में आना ही पड़ा।' तब वह दुनियादार आदमी आपका काम सबसे पहले करेगा और कहेगा, 'भाई साहब, देखिए, दुनिया ऐसे ही चलती है।'

तो मैंने भी अपने दिल को मजबूत किया और मंत्री जी के बंगले पर पहुंच गया। मंत्री जी ने मुझे पहचान लिया, पर जब मैंने आने का प्रयोजन बताया तो गंभीर हो गए। बोले, 'मैं जानता हूं, आप सिद्धांतवादी हैं। कभी किसी की सिफारिश लेकर नहीं आए। आज एक काम लेकर आए हैं, तो करना भी चाहता हूं। मगर अपना भी एक सिद्धांत है। मैं अपने सगे-संबंधियों के अलावा किसी का काम नहीं करता।' मुझे तत्काल बुरा लगा, लेकिन बाद में यह सोचकर अच्छा भी लगा कि वस्तुतः इस दुनिया में सबको अपने-अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए।

response@jagran.com

ऊर्जा

अपराध बोध

अपराध बोध एक संवेदनात्मक मनोभाव है, जो अपराधी के मन में ग्लानि रूप में उत्पन्न होकर अपराध को रोकने का काम करता है। इसीलिए अपराध के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। अपराध बोध का उत्कृष्टतम रूप वह है, जो अपराध से पहले ही मन में उत्पन्न होकर अपराध भाव को समाप्त कर देता है। संवेदना से भी इसका गहरा संबंध है। संवेदनशील व्यक्तियों में अपराध बोध की मात्रा अधिक होती है। अतः उनमें अपराध की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। अपराध की सर्वाधिक प्रवृत्ति संवेदनशून्य लोगों में होती है, क्योंकि उन्हें अपराध की पीड़ा का अहसास ही नहीं होता। आज अपराधों में हो रही बढ़ोतरी संवेदनहीनता और अपराध बोध में कमी का परिणाम है, जो गहरी चिंता का विषय है।

अपराध बोध एक स्वस्थ मानवीय गुण है, जो आत्म सुधार की प्रक्रिया को बढ़ाकर आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाता है। अतः सभी में इसका होना आवश्यक है। किंतु यही सामान्य से अधिक होने पर विकार भी बन जाता है। फिर अवसाद को जन्म देकर आत्महत्या जैसे घृणित अपराध का कारण बनता है। क्रोध अपराध बोध में बड़ा बाधक है, जो कई बार संवेदनशील व्यक्ति से भी न चाहते हुए अपराध करा देता है। क्रोध शांत होने पर बढ़े हुए अपराध बोध से वही व्यक्ति स्वयं का अनिष्ट कर लेता है। यह अपराध बोध का घृणित रूप है, जो नहीं होना चाहिए। अतः क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है।

अपराध बोध वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है, जो मानव को महान बनाती है। इससे समाज को अपराध मुक्त किया जा सकता है। धर्म में निष्ठा एवं अधर्म का भय अपराध बोध जागृत करने में सहायक हैं। बुद्ध, महावीर, गांधी आदि महापुरुषों ने सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, ममता आदि जिन मानवता के पोषक तत्वों की धर्म के रूप में प्रतिष्ठापना की है, उनके आने से अपराध बोध स्वयं ही जागृत होता है।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

तथ्य-कथ्य

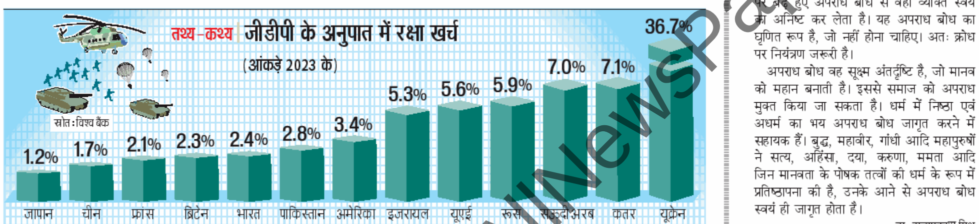

राजरंग

एक संकेत यह भी

कुछ राज्यों में भाजपा ने संगठन चुनाव की फिर से शुरुआत की है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो गई है कि शायद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत दूर नहीं है। हालांकि कुछ बड़े राज्यों में इस संबंध में घोषणा नहीं होने से उनमें थोड़ा असमंजस भी था, लेकिन इसी बीच फिर से उनका उत्साह बढ़ा है। और इसका कारण यह है कि हाल में भाजपा में लगातार सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने वाले जेपी नड्डा ने मुख्यालय के कुछ कर्मचारियों से मुलाकात की। इसे परिवर्तन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी के अध्यक्ष के कार्यालय को सुचारु रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों का आभार जताया। वैसे पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। चर्चा है कि भाजपा संसद के मानसून सत्र शुरू के पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर सकती है।

शाह की प्रशंसा से बढ़ी रेटिंग

कर्नाटक के दावनगिरी से कांग्रेस की सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन की रेटिंग आजकल प्रदेश के किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसके कारण हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बताया जाता है कि हाल ही में अपने कर्नाटक दौरे के वक्त जहां उन्होंने पार्टी नेताओं में एकता की कमी पर नाराजगी जताई, वहीं प्रभा मल्लिकार्जुन की प्रशंसा कर दी। यह खबर तेजी से फैली और कई स्थानीय अखबारों में प्रसारित हो गई। अमित शाह की प्रशंसा से जहां खुद प्रभा मल्लिकार्जुन गदगद नजर आ रही हैं और अमित शाह को धन्यवाद बोलते हुए यह सफाई दे रही हैं कि वह कांग्रेस में ही रहने वाली हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर नेताओं में यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रभा मल्लिकार्जुन की प्रगति को रोकना अब संभव नहीं होगा। हालांकि उनके पति पहले से ही सिद्दरमैया की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन महिला चेहरे के रूप में प्रभा मल्लिकार्जुन की दमक बढ़ने वाली है।

आयोग का दांव

एक कहावत है कि सौ सुनार की, एक लुहार की। चुनाव आयोग पर इन दिनों यह पूरी तरह फिट बैठ रही है। खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेरने के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए थे, उससे निपटने के लिए आयोग ने भी फैसला लिया है कि वह मतदाता सूची में एक भी गड़बड़ी को नहीं छोड़ेगा। इसके लिए वह मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन कराएगा। चुनाव आयोग ने बिहार से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। साथ ही संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, वहां भी मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस जैसे दल दोहरे ईपिक एवं मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को सड़क से संसद तक घेरने में जुटे थे, उनकी आयोग के इस फैसले के बाद नींद उड़ी हुई है। वे आयोग के इस फैसले का विरोध करते दिख रहे हैं।

बंगाल का असमंजस

पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं ने तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ गिरा दिया है, लेकिन इसका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा इसे लेकर विश्लेषकों में भी असमंजस है और वहां के मुख्य विपक्षी दल भाजपा में भी। दरअसल देश में अब यह अकेला राज्य है, जहां चुनाव में हिंसा होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर ही निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, लेकिन नेताओं का मानना है कि राष्ट्रपति शासन का उल्टा असर भी हो सकता है। लोगों में जिस ममता सरकार के खिलाफ अभी गुस्सा है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वह कहीं सहानुभूति में न बदल जाए।

X पोस्ट

दत्तात्रेय होसबाले ने जो कहा, वह गलत नहीं है, लेकिन सामने बिहार का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस और राजद को मौका मिल गया। उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया, वरना राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, इनको शायद पता ही नहीं होगा कि संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने पर खूब बहस हुई थी।

रजत शर्मा@RajatSharmaLive

भारत सेक्युलर था, सेक्युलर है और हमेशा सेक्युलर रहेगा।

मि. डेमोक्रेटिक@Mrdemocratic_

पंथनिरपेक्षता और समाजवाद खूबसूरत विचार हैं। जोड़ते हैं, ताकत देते हैं, बराबरी देते हैं।

विक्रांत यादव@ReporterVikrant

हम ऐसे लोग हैं, जो दूसरे देश में दो लोगों को लंच करते देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। किसी दूर देश में कोई छोटा-मोटा भी चुनाव जीतता है तो हम चिंतित हो अपनी नींद खराब कर लेते हैं, जबकि अपने देश में खराब सड़कें, बेरोजगारी और महंगाई देखकर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि 'सब ठीक है।'

हर्ष गोयनका@hvgoenka

जनपथ

हिंदी जोड़े देश को जुड़ें खेत-खलिहान,
इस भाषा के जोड़ से जुड़ता है इंसान।
जुड़ता है इंसान जोड़ना जिन्हें न भाए,
बस हिंदी का ज्ञान उन्हीं को रास न आए।
भाषा पर भी लोग सियासत करते गंदी,
कर लो कुछ भी आप न रुकने वाली हिंदी।

– ओमप्रकाश तिवारी

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 78

****

वित्त मंत्रालय: अनदेखा न करें

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

वित्त मंत्रालय ने 19 जून, 2025 को अपनी सलाहकार समिति की एक दुर्लभ बैठक आयोजित की। मेरे विचार से जून, 2024 में अठारहवीं लोकसभा के गठन के बाद यह पहली बैठक थी। इस समिति में दोनों सदनों के सभी दलों के मनोनीत सांसद सदस्य हैं। यदि सरकार इस समिति का उपयोग करना चाहे तो यह एक बेहतर तंत्र है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री करती हैं।

19 जून की बैठक औपचारिक थी। दरअसल, जरूरत से ज्यादा औपचारिक और नीरस। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने 19 स्लाइड की पावर प्वाइंट प्रस्तुति (पीपीटी) दी, सदस्यों ने अपनी टिप्पणियां और विचार रखे, वित्त सचिव ने उनका सारांश पेश किया- वस्तुतः संक्षेप में- लेकिन टिप्पणियों पर कोई उत्तर या स्पष्टीकरण नहीं दिया और वित्तमंत्री ने अपना समापन वक्तव्य दिया। किसी भी मुद्दे पर कोई परामर्श नहीं हुआ।

संयोग से, अपनी पावर प्वाइंट प्रस्तुति के 19वें स्लाइड में मुख्य आर्थिक सलाहकार ने समिति के सदस्यों से चार मुद्दों पर सुझाव मांगे :

1. कृषि उत्पादकता में और सुधार;
2. उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए नियमन-मुक्त एजंडा;
3. कौशल विकास कार्यक्रमों को कृत्रिम मेधा और तकनीकी बदलावों के अनुकूल बनाना;
4. अर्थव्यवस्था में औपचारिक तौर पर कैसे तेजी लाई जाए।

मैंने बैठक में बिना सोचे-समझे कोई सुझाव देना उचित नहीं समझा। तबसे मैंने चार मुद्दों पर विचार किया है और ये मेरे सुझाव हैं:

कृषि उत्पादकता में और सुधार लाना

मुख्य आर्थिक सलाहकार की ओर से दी गई प्रस्तुति की एक कड़ी में एमएसपी, पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा, केसीसी, ई-नाम और फूड पार्क्स का उल्लेख था: ये सभी योजनाएं कार्यकुशलता को बढ़ाने और इसके फलस्वरूप उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हैं। 'किसानों को सशक्त बनाना' विषय पर एक अन्य कड़ी की प्रस्तुति में प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि का आंकड़ा दिया गया था। प्रत्येक प्रमुख फसल में वर्ष 2013-14 और 2023-24 के बीच प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि दोहरे अंकों में रही है। वास्तव में, हम 1965 में शुरू हुई हरित क्रांति के दिनों से ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, न कि केवल 2013-14 के बाद से। हालांकि, उत्पादकता को विश्व मानकों के आधार पर मापा जाना चाहिए। *(देखें तालिका)*

उत्पादकता का एक अन्य मापदंड है: उत्पादकता प्रति किसान/कृषि श्रमिक। भारत की 58 फीसद आबादी (चीन में 22 फीसद की तुलना में) कृषि या कृषि-संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। इस कारण भारत में प्रति किसान उत्पादकता बहुत कम है और औसत किसान न केवल गरीब है, बल्कि कर्ज में डूबा हुआ है।

> वर्ष 2014-15 के बाद, मौजूदा सरकार ने और ज्यादा नियंत्रण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है। आरबीआइ, सेबी, कंपनी मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, आयकर विभाग, यूजीसी और दूसरे सभी मंत्रालयों व सरकार की हर अन्य इकाई ने सैकड़ों पृष्ठों के नियम व विनियम बनाए हैं। पुराना नियंत्रण तंत्र अब 'विनियमन' के रूप में वापस आ गया है।

प्रति किसान उत्पादकता बढ़ाने का उपाय है गैर-कृषि नौकरियों का सृजन और लाखों लोगों को कृषि से हटाकर गैर-कृषि क्षेत्रों में लगाना। लेकिन, शहरों में ज्यादा बेरोजगारी और विनिर्माण क्षेत्र की दयनीय स्थिति के कारण यह प्रक्रिया ठहराव और रुकावट की स्थिति में है; आंकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षों में श्रमिक फिर से कृषि क्षेत्र में लौट आए हैं।

फसल	भारत औसत/सर्वश्रेष्ठ	वैश्विक औसत	विश्व में सर्वश्रेष्ठ	
	(किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)			
गेहूं	3,559/5,045	3,548	ईयू/मिस्र	6,500/7,700
धान	2,882/4,516	4,700	चीन	6,500
मक्का	3,351/6,239	5,824	अमेरिका	10,532
गन्ना	84,906/105,000	75,000	ब्राजील	75,000
कपास	443/602	1,040	चीन	2,252

सुझाव : विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर और विस्तार को तेज किया जाए।

उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए नियमन-मुक्त एजंडा

वर्ष 2014-15 के बाद, मौजूदा सरकार ने और ज्यादा नियंत्रण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है। आरबीआइ, सेबी, कंपनी मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, आयकर विभाग, यूजीसी और सभी मंत्रालयों व सरकार की हर अन्य इकाई ने सैकड़ों पृष्ठों के नियम व विनियम बनाए हैं। पुराना नियंत्रण तंत्र अब 'विनियमन' के रूप में वापस आ गया है। सरकारी प्राधिकरण विवाद और मुकदमेबाजी के जरिए शक्ति और नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। भारत में व्यापार करना यानी नियमों और आदेशों को चुनौती देना तथा निवारण के लिए न्यायालयों व न्यायाधिकरण का रुख करना है।

जीएसटी कानून ने कारोबार पर बोझ बढ़ा दिया है। जीएसटी की उच्च और अनेक दरें अपने आप में खराब हैं। जीएसटी कानून के तहत नियम, विनियमन, अधिसूचनाएं, फार्म व अनुपालन और भी बदतर हैं।

आयकर, सीमा शुल्क, डीजीएफटी और जीएसटी विभागों द्वारा कानूनों की व्याख्या और इन्हें लागू करने का तरीका मिलकर किसी भी व्यवसाय के लिए एक दुस्वप्न बन गया है।

सीबीआइ, ईडी, डीआरआइ, जीएसटी प्रवर्तन और एसएफआइओ हर व्यापारी को संदिग्ध तथा सीए और वकील को सहयोगी मानते हैं। यदि व्यापार और उद्योग को अर्थव्यवस्था का प्रमुख संचालक बनना है, तो जिस घुटन भरे माहौल में वे खुद को पाते हैं, उसे खत्म करना होगा।

सुझाव : हर तिमाही में एक अलाव जलाएं, जलाने के लिए पर्याप्त कचरा है।

कौशल विकास कार्यक्रमों को कृत्रिम मेधा और तकनीकी बदलावों के अनुकूल बनाना

वार्षिक शिक्षा स्थिति रपट (एएसईआर) पढ़ें। स्कूली बच्चों के पढ़ने-लिखने और अंकगणितीय कौशल का खराब स्तर तकनीकी रूप से सशक्त समाज की संभावना को लगभग समाप्त कर देता है। यूजीसी, एनटीए और एनएएसी की तिकड़ी ने विश्वविद्यालयों के आवश्यक चरित्र- स्वायत्तता, जांच और उत्कृष्टता के लिए प्रयास- को छीन लिया है। उन्होंने अच्छे शिक्षकों, विद्वानों और शोधकर्ताओं को विदेशी धरती पर भेज दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालयों को धन से वंचित करके उनके हाथ-पैर बांध दिए हैं। विश्वविद्यालयों में हजारों पद रिक्त हैं। संसद में दिए गए एक उत्तर के अनुसार, 31 अक्तूबर, 2024 तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 शिक्षण पद खाली थे। मुझे डर है कि इस जटिल मुद्दे पर आगे का रास्ता वित्त मंत्रालय के दायरे से बहुत दूर है।

सुझावः सीईए इस मुद्दे को अपनी सूची से हटा दें।

अर्थव्यवस्था में औपचारिक तौर पर कैसे तेजी लाई जाए

मुख्य आर्थिक सलाहकार का 'अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण' से क्या तात्पर्य है? क्या वे चाहते हैं कि 'अनौपचारिक' अर्थव्यवस्था में की जाने वाली अधिक आर्थिक गतिविधियों (जैसे मध्यम वर्ग के घरों में अंशकालिक सहायिका सेवाएं) को औपचारिक बनाया जाए?

सुझाव : जब तक स्पष्टता न हो, मेरे पास कोई सुझाव नहीं है।

कृपया, इन सुझावों को स्वीकार करें या अस्वीकार; पर इन्हें अनदेखा न करें।

परिवारवाद की नींव

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

पिछले सप्ताह खूब चर्चा रही 'इमरजंसी' यानी आपातकाल की। जून 25 के दिन उस काले दौर के पचास साल बीत गए थे, तो चर्चा क्यों न हो। मैंने राजनेताओं, पत्रकारों, राजनीतिक पंडितों को सुना टीवी पर और कई लेख पढ़े अखबारों में, जिनमें इन ज्ञानियों ने गंभीर शब्दों में उन अठारह महीनों का जिक्र किया, जब इस देश में लोकतंत्र को ताक पर रखकर एक अति-लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने अपने आप को तानाशाह बनाकर हमारे सारे बुनियादी अधिकार छीन लिए थे। मेरे लिए वे काले दिन खास महत्त्व रखते हैं, इसलिए कि एक भारतीय अखबार में काम करने का मौका पहली बार मिला मुझे आपातकाल के घोषित होने से एक महीने पहले।

इन ज्ञानियों ने ध्यान दिलाया कि उन अठारह महीनों में तानाशाही इतनी थी कि दिल्ली में लोग दोस्तों, रिश्तदारों से भी राजनीति पर बात करने से डरते थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ पत्रकार एक शब्द नहीं लिख सकते थे। जब गरीब मर्दों को भेड़ों की तरह रात के अंधेरे में ट्रकों में भर कर ले जाया जाता था उनकी नसबंदी करने। न शिकायत कर सकते थे, न विरोध। यह सब बातें सच हैं, लेकिन जो भारतीय राजनीति को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था उन अठारह महीनों में, उसका जिक्र तक मैंने नहीं सुना। शायद इसलिए कि इस हमाम में अब हमारे सारे राजनीतिक दल नंगे हैं।

आपातकाल का सबसे बड़ा नुकसान, मेरी नजर में यह हुआ कि परिवारवाद की नींव रखी गई थी उसी दौर में। इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे, संजय गांधी को न सिर्फ अपना सबसे अहम सलाहकार बनाया था, बल्कि उसके हवाले देश की बागडोर दे डाली थी। संजय अपनी मां के बाद देश के सबसे बड़े राजनेता बन गए थे। मंत्रियों से लेकर भारत सरकार के सारे आला अधिकारी संजय के आदेश का पालन करते थे। जिन्होंने संजय का हुकुम मानने से इनकार किया, उनकी फौरन छुट्टी कर दी जाती थी। इंद्र कुमार गुजराल उन दिनों इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे और उनके सूचना प्रसारण मंत्री भी थे, लेकिन जब उन्होंने संजय का हुकुम मानने से इनकार किया तो उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया और उनकी जगह संजय ने बिठाया विद्याचरण शुक्ला को, जिन्होंने दिखाया हम पत्रकारों को कि प्रेस सेंसरशिप का उल्लंघन करने की कीमत क्या है।

संजय गांधी पहले व्यक्ति थे जो राजनीति में आए सिर्फ इसलिए कि उनकी मां प्रधानमंत्री थीं और उनके नाना देश के पहले प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा जा सकता है कि वे प्रधानमंत्री बनीं, सिर्फ इसलिए कि उनके पिता भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सच यह है कि इंदिरा गांधी को नेहरू ने अपने जीवन में अपना वारिस नहीं बनाया था। नेहरू के बाद दो प्रधानमंत्री और बने थे। तो इंदिरा गांधी काफी हद तक अपने बल पर राजनीति में सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंचीं थीं। संजय गांधी के साथ ऐसा नहीं था। जब उनकी मां ने देश और कांग्रेस पार्टी को उनके हवाले किया तो उनको न राजनीति में कोई अनुभव था और न शासन में।

> इस परंपरा का नुकसान भारतीय लोकतंत्र को यह हुआ है कि कई काबिल लोग, जिन्होंने समाजसेवा की है और जिनके लोकसभा में आने से देश को लाभ हो सकता है, उनको टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि युवराज साहब से अधिक काबिल लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है उन राजनीतिक दलों में जो किसी परिवार की निजी जायदाद बन कर रह गए हैं।

आपातकाल के बाद जब इंदिरा गांधी जनता पार्टी की गंभीर गलतियों और झगड़ों के कारण फिर से 1980 का चुनाव जीतीं, तब असल में संजय गांधी ने उनको उस बार चुनाव जिताने में सहायता की थी और सीटों के बंटवारे में भी उनका दखल था। इंदिरा गांधी की सफल राजनीतिक वापसी को देख कर देश के बाकी छुटभैया राजनेता भी अपने परिवार से वारिस चुनने लगे। नतीजा यह है कि आज एक भी राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के अलावा, जो एक परिवार की निजी संपत्ति न बन चुका हो। जो परिवार चलाते हैं इन दलों को, उनका कहना है कि उनके बेटे-बेटियां चुनाव लड़ कर आते हैं तो यह लोकतंत्र ही तो है।

यह बात बिल्कुल गलत है। अक्सर इन राजनीतिक राजकुमार और राजकुमारियों का लोकसभा में प्रवेश होता है ऐसे जनपदों से जो उनकी मां या पिता का गढ़ माने जाते हैं। राजीव गांधी को जब राजनीति में लाया गया, उनके भाई के हवाई दुर्घटना में देहांत के बाद, तो उन्हें रायबरेली से लड़ाया गया जो उनकी मां की पक्की सीट मानी जाती थी। वैसा ही होता है हर नए वारिस के साथ। उनको सौंपी जाती हैं अक्सर उनकी मां या उनके पिता की कोई पक्की सीट। इसलिए जीत कर तो आते हैं लोकसभा में, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी करके।

इस परंपरा का नुकसान भारतीय लोकतंत्र को यह हुआ है कि कई काबिल लोग, जिन्होंने समाज सेवा की है और जिनके लोकसभा में आने से देश को लाभ हो सकता है, उनको टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि युवराज साहब से काबिल लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है उन राजनीतिक दलों में, जो किसी परिवार की निजी जायदाद बन कर रह गए हैं। जब लोग राजनीति में आते हैं देश की नहीं, अपने परिवार की सेवा करने, तो राजनीति कारोबार बन जाता है, धन कमाने का सबसे आसान तरीका। ऐसा हुआ है अपने इस बेहाल देश में, इसलिए जब प्रधानमंत्री परिवारवाद को गलत बताते हैं, तो वे बिल्कुल ठीक कहते हैं। उनकी समस्या यह है कि उनके अपने दल में भी अब वारिसों की बहार आई हुई है तो जनता की सेवा करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं राजनीति में और अपने परिवार की सेवा करने वाले जरूरत से बहुत ज्यादा।

विकसित भारत का सपना हमको नरेंद्र मोदी दिखाते हैं जब भी किसी आम सभा को संबोधित करते हैं, लेकिन शायद भूल गए हैं प्रधानमंत्री कि विकसित देशों में परिवारवाद बहुत कम देखने को मिलता है। वही लोग ऊंचे ओहदों तक पहुंचते हैं, जिन्हें वास्तव में जनता की सेवा करने की इच्छा है। आपातकाल के बिना इंदिरा गांधी परिवारवाद की नींव नहीं रख सकतीं थीं।

भारत के यथार्थ की अभिव्यक्ति

संदर्भ

राकेश सिन्हा

संविधान की प्रस्तावना में बयालीसवें संशोधन द्वारा आरोपित 'धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी' शब्दों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा राजनीतिक बहस और पुनर्विचार के सुझाव ने सियासी भूचाल ला दिया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संघ और भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को ही बदलने का आरोप मढ़ दिया। राहुल गांधी ने तो संविधान को मनुस्मृति से विस्थापित करने की साजिश तक कह दिया। यह प्रक्रिया समकालीन राजनीति की प्रकृति और गुणात्मक गिरावट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। विमर्श विपक्ष को कांटे से भी अधिक कंटीला लगने लगा है। वे विमर्श मुक्त राजनीति के पक्षधर हो गए हैं।

जनतंत्र की आत्मा मतों की भयमुक्त और स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। यही समाज की चेतना को समृद्ध करती है। इसे रोकना नदी को तालाब बना देने जैसा है। आज वही हो रहा है। जिस संविधान की राजनीतिज्ञ दुहाई देते थकते नहीं हैं, उसे या तो पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ा है, तो उसके मर्म और संदेश को ग्रहण नहीं किया है।

संविधान सभा मत अभिव्यक्ति की एक प्रयोगशाला भी थी। इसे विमर्श का स्वर्णिम अध्याय भी कहा जा सकता है। न किसी पर कुछ थोपा गया, न ही रोका गया। अनचाही बातों को धैर्य से सुना गया। विमर्श के तीन आयाम होते हैं- तथ्य, तर्क और संयम। तीनों ही भरपूर थे। उदाहरण के लिए एचवी कामत ने संविधान में 'ईश्वर' शब्द जोड़ने का संशोधन रखा। उस पर शांतिपूर्ण बहस हुई और मतदान भी। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। बहस के लिए नीयत के साथ-साथ स्वध्याय, चिंतन और चेतना जरूरी होता है। इसकी गिरावट विमर्श की संस्कृति को समाप्त कर देती है।

दत्तात्रेय होसबाले ने जो कहा, उसका प्रतिबिंब संविधान सभा में विद्यमान है। केटी शाह संविधान सभा के मुखर सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द जोड़ने का संशोधन रखा था। वह खारिज हो गया। बाबा साहब आंबेडकर ने 'समाजवादी' शब्द की अप्रसांगिकता बताते हुए कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में समानता, शोषण मुक्त और श्रम को सम्मान देने वाले प्रावधानों की प्रचुरता है। उन्होंने कहा था, 'और कितना समाजवाद चाहिए?' समाजवाद एक विशिष्ट प्रकार की विचारधारा है। एक आर्थिक विचार से पीढ़ियों को बांधा नहीं जा सकता है। समय, संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक दर्शन का अन्वेषण होता है। भारतीय समाज समानता का पक्षधर है। इसलिए सामाजिक-आर्थिक न्यूनताओं के विरुद्ध व्यक्ति या संगठन को स्वाभाविक स्वीकृति मिलती रही है।

पंथनिरपेक्षता जीवंत पद्धति होती है। इसका अभिप्राय आध्यात्मिक विवेचना करने, अपनी इच्छा से तौर-तरीके को चुनने और ईश्वर से संबंध को फिर से परिभाषित करने का अधिकार होता है। इसीलिए विविधताएं डराती नहीं हैं। लड़ाई दो प्रवृतियों के बीच रहती है। एक प्रवृति है विविधता का हिस्सा बन कर चलना। दूसरी प्रवृत्ति है विविधता को किसी पुस्तक के संदेश या आध्यात्मिक गुरु के दर्शन के आधार पर एकरूपता में तब्दील कर देना। हिंदू जीवन पद्धति जितनी ही प्रवहमान और न्यूनताओं से मुक्त रहेगी, पंथनिरपेक्षता उतनी ही प्रबल और प्रभावी होगी। वेद और उपनिषद दोनों ही हमारी इस जीवन पद्धति को ठोस आधार प्रदान करते हैं। इसीलिए दोनों शब्दों 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवादी' का संविधान की प्रस्तावना में रहना उसे पश्चात्यवादी परिभाषा का दास बना देता है। ये शब्द मुखौटा से अधिक कुछ नहीं हैं। इन शब्दों को जोड़ने के पीछे की नीयत जनतंत्र पर लगे ग्रहण को ढकना था। इंदिरा गांधी की सरकार ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया। देश को अभिव्यक्ति शून्य बना दिया गया जिसे कवि भवानी प्रसाद मिश्र की ये पंक्तियां जीवंतता से प्रतिबंबित करती हैं: *'बहुत नहीं सिर्फ चार कौए थे काले,/ उन्होंने यह तय किया कि सारे उड़ने वाले/ उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खायें और गाएं/ वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं।'*

सत्ता का केंद्रीकरण चरम पर था। व्यक्ति पूजा उससे भी आगे थी। लोकतंत्र में शक्ति का पृथक्कीकरण उसका बहुमूल्य धरोहर था। इसे समाप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही 42वां संविधान संशोधन था। उस वक्त संसद के भाषणों में यही मुख्य धारा थी। इस संशोधन में न तो जनभागीदारी हुई और न ही लोक विमर्श हुआ। लोकसभा में मतदान के दौरान 346 इसके पक्ष में और दो मत जिनमें जीवी मावलंकर शामिल थे, विरोध में पड़े। आखिर वे विरोध की भूमिका में रह कर वाजपेयी, देसाई, फर्नांडीज की तरह सरकार का कोपभाजन क्यों नहीं बने। इसका उत्तर रूस के एक कम्युनिस्ट तानाशाह के शब्दों में मिलता है।

> दत्तात्रेय होसबाले ने जो कहा उसका प्रतिबिंब संविधान सभा में विद्यमान है। केटी शाह संविधान सभा के मुखर सदस्यों में एक थे। उन्होंने प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द जोड़ने का संशोधन रखा था। वह खारिज हो गया। बाबा साहब आंबेडकर ने 'समाजवादी' शब्द की अप्रसांगिकता बताते हुए कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समानता, शोषण मुक्त और श्रम को सम्मान देने वाले प्रावधानों की प्रचुरता है। उन्होंने पूछा 'और कितना समाजवाद चाहिए?'

चुनाव में उन्हें 99.6 फीसद वोट मिले। किसी ने पूछा, शेष वोट क्यों नहीं पड़े। उत्तर था 'आखिर जनतंत्र है।' वही जनतंत्र 1976 में लोकसभा में था।

'हम भारत के लोग' का तात्पर्य एक पीढ़ी नहीं, भविष्य की पीढ़ियां भी हैं। उनके सोचने, समझने और भारत को परिभाषित करने का अधिकार किसी कालखंड की पीढ़ी की सोच-समझ और परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है। यही भाव संविधान सभा में आंबेडकर ने एक नहीं अनेक बार व्यक्त किया था।

अमेरिका में राष्ट्रपति दो या दो से अधिक बाइबिल पर हाथ रख कर शपथ लेते हैं। ब्रिटेन के हाउस आफ लाड्र्स में चर्च आफ इंग्लैंड के 26 प्रतिनिधि मनोनीत होते हैं। यह 'पश्चात्य पंथनिरपेक्षता का प्रतिमान है। भारत इससे आगे है। सम्राट अशोक और चोल वंश राजा राजेंद्र जैसे शासकों ने धर्म और राजनीति के संबधों का जो प्रतिमान दिया, वह भारतीय पंथनिरपेक्षता का प्रतिमान है। दत्तात्रेय होसबाले ने इन्हीं के बीच संघर्ष को पुनर्जीवित किया है। आरोप- प्रत्यारोप, बदजुबानी और काल्पनिकता विमर्श नहीं होता है। इन दोनों शब्दों पर विमर्श संविधान की प्रस्तावना तक सीमित रहेगा। यह भारत के यथार्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकता है। विपक्ष इसे रोकना चाहता है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

आपातकाल बरक्स आपातकाल

बाखबर

सुधीश पचौरी

ट्रंप कहिनः मोदी आते क्या अमेरिका? आएंगे जाएंगे, खाना खाएंगे, बात करेंगे और क्या? मोदी कहिनः मुझे बुलावा आया है... महाप्रभु की धरती ने बुलाया है। अथ एक 'फील्ड मार्शल' उवाचः ट्रंप का बुलावा आया था। दोपहर के भोजन पर बुलाया था... हमने खाया खाना, हमारा पेट भर गया... ट्रंप ने युद्ध दिया रोक, उन्हें मिले 'नोबेल शांति शांति शांति'! फिर शुरू हुआ 'युद्ध राग...'। इजराइल कहे कि ईरान में हमने ये मारा, वो मारा... जवाब में ईरान कहे कि हमने भी इजराइल में ये मारा वो मारा...। फिर बोले ट्रंप कि असली तो हमारे 'बी 2' के पायलटों ने 'परमाणु' ठिकाने ध्वस्त किए। 'बी 2' के पायलटों को धन्यवाद। ईरान करे आत्मसमर्पण... न करेगा, तो होगा बवंडर... बंद करो 'गोलीबारी', करो 'युद्ध विराम'। फिर भी कोई न माना तो ट्रंप इतने नाराज कि मुखारविंद से निकल पड़ा एक 'सुभाषित'... फिर 'कतर ब्योंत' से बनाई गई 'युद्ध विराम' की खबर!

विशेषज्ञ बोले कि सबको सब पता रहा। सबको बता दिया गया था कि 'परमाणु ठिकानों' पर हमला होगा, इसलिए ईरान ने पहले ही साजो-सामान को अलग जगह पर भेज दिया था। ट्रंप कहिन कि सारे ठिकाने तबाह किए, तो ईरान कहे 'सब ठिकाने सुरक्षित..!' क्या सच, क्या झूठ, किसी को नहीं मालूम!

फिर एक दिन शुरू हुआ विपक्ष का 'वीडियो उपहास युद्ध'। पहले रोमन में 'नरेंदर सरेंडर' लिखा दिखा। पक्ष प्रवक्ता कहिन कि एक विपक्षी दल मोदी की सिर्फ खिल्ली उड़ाता है और हारता रहता है..! फिर एक दिन शुरू हुआ पुराना रोना कि चुनाव फिक्स... चुनाव फिक्स। पक्ष प्रवक्ता कहिनः ये जीतें तो चुनाव ठीक, नहीं तो गलत! गलत है तो अदालत जाइए। विपक्ष का जवाबः अदालत जाने से क्या होगा? कोई सुनता नहीं और आयोग भी सुनता नहीं..! एंकर बोलाः मीठी 'गप' और कड़वी 'थू'! ये कैसा तर्क? इसी बीच चैनल ने एक 'तुरंता आनलाइन' सर्वे करा डाला। उसने पूछा कि चुनाव आयोग पर मिथ्यारोप लगाने वालों को 'दंडित' किया जाना चाहिए, तो 75 फीसद ने कहाः हां 'दंडित' किया जाना चाहिए! चुनाव आयोग कहिनः पहले भी जवाब दिया है, आएं तो समझा देंगे।

> आपातकाल' के 'पचास वर्ष' हुए और सत्तादल ने मनाया 'संविधान हत्या दिवस'! विपक्ष कहिन कि वह 'घोषित आपातकाल' था, लेकिन आज 'अघोषित आपातकाल' है! फिर चैनलों पर देर तक होता रहा 'आपातकाल' बरक्स 'अघोषित आपातकाल'!

फिर, 'आपातकाल' के 'पचास वर्ष' हुए और सत्तादल ने मनाया 'संविधान हत्या दिवस'! विपक्ष कहिन कि वह 'घोषित आपातकाल' था, लेकिन आज 'अघोषित आपातकाल' है! फिर चैनलों पर देर तक होता रहा 'आपातकाल' बरक्स 'अघोषित आपातकाल'! एक कहे कि आपातकाल में जनतंत्र का गला घोंट दिया गया था। कुर्सी बचाने के लिए हजारों विपक्षी नेता जेलों में डाल दिए गए। उन पर अत्याचार किए गए। लेकिन सन 1975 के 'आपातकाल' के शिकार बने कुछ विपक्षी नेता ही कहते दिखे कि आज तो 'अघोषित आपातकाल' है! इतना ही नहीं, विपक्ष के एक नेता ने तो 'आपातकाल' का भी 'सौंदर्यीकरण' करते हुए कह दिया कि इतना भी बुरा नहीं था आपातकाल!

फिर एक शाम एक चैनल ने बिहार के चुनाव को एजंडे पर ला दिया। जब लोगों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे चहेता चेहरा कौन है तो 'रेंटिंग' ने आंकड़ों से बताया कि 40 फीसद से अधिक लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्रह फीसद से कुछ ही अधिक पसंद करते हैं... उनसे तो ज्यादा यानी 18 फीसद से कुछ ज्यादा तो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में चाहने वाले हैं।

फिर 'रेटिंग' ने सवाल किया कि राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्ट रहने वाले कितने फीसद हैं, तो आंकड़े बोले कि 34.4 फीसद बहुत संतुष्ट और 27 फीसद से अधिक 'कुछ संतुष्ट'। जब 'रेटिंग' ने पूछा कि नीतीश के काम से लोग कितने संतुष्ट हैं तो आंकड़े बोले कि 34.4 फीसद बहुत संतुष्ट और 25 फीसद से अधिक 'कुछ संतुष्ट'। रेटिंग विशेषज्ञ ने स्पष्ट किया कि चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे का महत्त्व होता है, लेकिन सिर्फ चेहरा ही काफी नहीं होता। चुनाव में सरकार के 'कामकाज' और 'प्रदर्शन' का भी महत्त्व होता है। जब नीतीश सरकार के कार्यकाल में 'आम जनता के रहन-सहन में सुधार' के बारे में पूछा गया तो आंकड़े बताने लगे कि 25 फीसद ने कहा कि बहुत हुआ और 40 फीसद ने कहा कि जैसा था वैसा ही रहा! तब जद(एकी) के प्रवक्ता कहिन कि बिहार में कोई सत्ता-विरोधी लहर नहीं है... नीतीश के नेतृत्व में ही राजग चुनाव लड़ेगा और जीतेगा!

सप्ताह की सबसे 'सकारात्मक' खबर आई अमेरिका से प्रक्षेपित किए जाते 'एक्सिम 4', अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल की, जिन्होंने इस यात्रा में शामिल होकर भारत का गौरव बढ़ाया।

और अंत में आई दो कथावाचकों की 'इटावा कथा', जिसने एक बार फिर 'जाति युद्ध' का खतरा पैदा कर दिया। फिर नेताओं का कूद पड़ना। एक ओर 'मनुवाद', 'ब्राह्मणवाद' की कुटाई, दूसरी ओर 'धर्मशास्त्र' में कथावाचन की व्यवस्थाएं!

चीन के किंगदाओ (चिंगदाओ) शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलन 25 और 26 जून को आयोजित किया गया। एससीओ सम्मेलन में चीनी नेतृत्व में तैयार संयुक्त वक्तव्य में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि एससीओ का संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका। लेकिन इस सबमें जहां आतंकवाद को लेकर चीन का दोगलापन व पाक प्रेम फिर से उजागर हुआ, वहीं भारत का कड़ा रुख सामने आया। भारत ने चीन व पाकिस्तान समेत एससीओ सदस्य देशों को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली की जीरो टॉलरेंस की नीति है और एससीओ अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हो सकता है। एससीओ की प्रस्तावना में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई की बात है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि वो रूस एससीओ के चीनी संयुक्त घोषणा पत्र में भारतीय हितों की अनदेखी पर चुप रहा, जिसने इस समूह में भारत को शामिल कराने के लिए वकालत की थी। अभी भारत व पाक के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान भी अमेरिका व रूस के आचरण भारत की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की विदेश नीति ठहर गई है? आजकल के ताजा अंक में पेश है एक विश्लेषण...

विदेश नीति में 'स्टैंड' लेने का वक्त

एससीओ सम्मेलन
प्रभात कुमार रॉय
विदेश मामलों के जानकार

भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा जब तैयार किए गए संयुक्त वक्तव्य दस्तावेज की बाकायदा समीक्षा की गई तो उसको स्पष्टतया प्रतीत हुआ कि यह अत्यंत पक्षपातपूर्ण और असंतुलित तौर से तैयार किया गया है। भारत के मुताबिक इस दस्तावेज में विगत 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में यात्रियों पर अंजाम दिए गए नृशंस आतंकवादी आक्रमण को पूरी तरह से नजरअंदाज करके उसे एकदम दरकिनार कर दिया गया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लीडर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तैयार किए गए संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप इस दफा एससीओ सम्मेलन कोई संयुक्त घोषणा पत्र (जॉइंट डिक्लेरेशन) भी जारी नहीं कर सका।

चीन के किंगदाओ (चिंगदाओ) नगर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का एक शिखर सम्मेलन 25 और 26 जून को आयोजित किया गया। एससीओ सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य तैयार किया गया। संयुक्त वक्तव्य का मकसद निरूपित किया गया कि एससीओ देशों में संयुक्त सुरक्षा प्रबंधन, परस्पर आर्थिक सहयोग और वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध एक संयुक्त और कारगर रणनीति का ऐलान करना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा जब तैयार किए गए संयुक्त वक्तव्य दस्तावेज की बाकायदा समीक्षा की गई तो उसको स्पष्टतया प्रतीत हुआ कि संयुक्त वक्तव्य दस्तावेज को अत्यंत पक्षपातपूर्ण और असंतुलित तौर से तैयार किया गया है। भारत के मुताबिक इस दस्तावेज में 11 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जफर एक्सप्रेस के अपहरण कांड की वारदात का एक आतंकवादी वारदात के तौर पर बाकायदा उल्लेख किया गया है, लेकिन विगत 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में यात्रियों पर अंजाम दिए गए नृशंस आतंकवादी आक्रमण को पूरी तरह से नजरअंदाज करके उसे एकदम दरकिनार कर दिया गया है।

संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर से इनकार

एससीओ सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लीडर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तैयार किए गए पक्षपातपूर्ण संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और वैश्विक आतंकवाद को किसी भी एक मुल्क के नजरिए से कदाचित देखा और परखा नहीं जा सकता। भारतीय रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर फरमाया कि आतंकवादी वारदातों को कदापि नहीं रोका जा सकता, जब तक कि सभी आतंकवादी वारदातों को निष्पक्षता के साथ देखा और समझा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत का स्पष्ट नजरिया है कि पक्षपातपूर्ण रवैये और संकीर्णतापूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण द्वारा वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध कामयाबी के साथ कोई भी सामूहिक संघर्ष कदापि अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसी कारण से भारत ने संयुक्त वक्तव्य दस्तावेज पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्री एससीओ सम्मेलन में जब तकरीर कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सम्मेलन में विद्यमान थे। अतः भारत द्वारा संयुक्त वक्तव्य पर दस्तखत नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप इस दफा एससीओ सम्मेलन कोई संयुक्त घोषणा पत्र (जॉइंट डिक्लेरेशन) भी जारी नहीं कर सका। क्योंकि एससीओ चार्टर के प्रावधान के तहत सभी सदस्य देशों की संपूर्ण सहमति से ही कोई संयुक्त वक्तव्य और संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि एससीओ की स्थापना सन् 1991 में सोवियत संघ के विघटन के तत्पश्चात 26 अप्रैल सन 1996 में चीन के शंघाई नगर में आयोजित एक सम्मेलन में की गई थी। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान द्वारा शिरकत की गई थी। शंघाई सम्मेलन में संयुक्त तौर पर इन देशों द्वारा परस्पर सरहदी विवादों को निपटाया गया था। प्रारंभ में इस एससीओ ग्रुप को शंघाई फाइव के नाम से स्थापित किया गया था। भारत, ईरान, पाकिस्तान सन् 2005 से निरंतर एससीओ सम्मेलनों में पर्यवेक्षक देशों के तौर पर शिरकत करते रहे।

रूस का भारत को एकतरफा समर्थन नहीं

2017 में भारत और पाकिस्तान को एससीओ का सदस्य बनाया गया। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 को निरस्त किया, रूस ने भारत का प्रबल समर्थन किया। सन् 2023 एससीओ में ईरान को सदस्य बनाया गया। वस्तुतः नीतिगत और कूटनीतिक तौर से एससीओ पर चीन और रूस का निर्णायक प्रभाव कायम रहा है। परम्परागत तौर से रूस सदैव भारत का प्रबल रणनीतिक और कूटनीति पक्षधर देश रहा। एससीओ में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से ही रूस की पहल पर भारत को एससीओ में शामिल किया गया था। दुर्भाग्य से पाकिस्तान द्वारा प्रेरित और प्रायोजित पहलगाम हत्याकांड के प्रतिशोध में भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर के दौर में रूस द्वारा भारत को एकतरफा समर्थन प्रदान नहीं किया गया। वरन रूस ने भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की। फरवरी 2022 से प्रारंभ हुए यूक्रेन-रूस युद्ध के दौर में भारत द्वारा रूस का एक तरफा समर्थन नहीं किया गया। रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए भारत ने मध्यस्थता का प्रस्ताव पेश किया। रूस द्वारा भी भारत को कूटनीतिक प्रत्युत्तर देते हुए भारत का समर्थन करने के स्थान पर भारत-पाक युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश कर दी। एससीओ सम्मेलन में वस्तुतः चीन द्वारा संयुक्त वक्तव्य का दस्तावेज तैयार किया गया और रूस और अन्य सहयोगियों की सहमति ली गई। अतः चीन की पहल पर तैयार किए गए दस्तावेज में भारत पर अंजाम दिए गए नृशंस आतंकवादी आक्रमण का तो कदाचित उल्लेख नहीं किया गया, किंतु बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस के अपहरण को आतंकवादी वारदात करार देकर, उसका बाकायदा उल्लेख किया गया। भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि रूस पहले की तरह अब भारत का प्रबल पक्षधर प्रतीत नहीं हो रहा है।

पाक को चीन और रूस का सहारा

ऐसा प्रतीत होता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौर में रूस किसी हद तक चीन के रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव में आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौर में चीन वस्तुतः भारत का धुर विरोधी और पाकिस्तान का प्रबल समर्थक बनकर उभरा है। तकरीबन साढ़े तीन वर्ष से रूस-यूक्रेन युद्ध निरंतर जारी है। चीन द्वारा रूस को आधुनिकतम सैन्य हथियारों की निरंतर आपूर्ति की जा रही है। विश्व पटल पर एकदम अलग-थलग पड़े हुए पाकिस्तान को रूस और चीन दोनों का सहारा मिल रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र करार दिए जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने पर उतारू हो गए हैं। यकीनन अघोषित तौर पर कोल्ड वार के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब विश्व दो परस्पर विरोधी सैन्य खेमों में विभाजित हो चुका है। गुट निरपेक्ष भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक परीक्षा का यह कठिन दौर है। विश्व पटल पर अत्यधिक संतुलनवादी विदेश नीति अपनाते हुए भारतीय कहीं अकेला तो नहीं पड़ रहा है? शिखर सम्मेलन में नौ सदस्य देशों ने शिरकत की। अफगानिस्तान और बेलारूस और मंगोलिया शिखर सम्मेलन में पर्यवेक्षक देश के तौर पर उपस्थित रहे। एससीओ सम्मेलन द्वारा वैश्विक आतंकवाद के ज्वलंत प्रश्न पर पाखंडपूर्ण और दोगली कार्य नीति और रणनीति अख्तियार करने के विरोध में भारत का समर्थन करने और साथ देने के लिए एक भी सदस्य मुल्क आगे नहीं आया। कैसी विचित्र विडंबना है कि पाकिस्तान सरीखा मुल्क जोकि दशकों से वैश्विक आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ बना रहा है, जिसकी सरजमीं पर जिहादी दहशतगर्दों के सरगना ओसामा बिन लादेन की परवरिश हुई और अलकायदा ने परवान चढ़कर सारी दुनिया में तबाही मचाई है। पहलगाम में नृशंस हत्याकांड अंजाम देने वाले रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा अपना गहरा ताल्लुक लश्कर तैयबा के साथ स्वीकारा है। लश्कर ए तैयबा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है और जिसको सदैव पाकिस्तान ने पाला पोसा और उसकी तरबीयत की गई है। अब वह पाकिस्तान एससीओ की नजर में आतंकवाद का शिकार एक मुल्क बन गया है। भारत जो कि अनेक दशक से जिहादी आतंकवाद के नृशंस निशाने पर बना रहा है, उस भारत के गहरे ज़ख्मों को जानने और समझने के लिए एससीओ के सदस्य देश तैयार नहीं हैं।

गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा चीन जाकर एससीओ सम्मेलन में शिरकत करने की एक उपलब्धि अवश्य हो गई है। इस अवसर पर भारत और चीन के मध्य कूटनीति की एक नई इबारत खुलती दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के मध्य हुई बैठक में सीमा विवाद का समाधान, शांति बहाली और भारत-चीन संबंधों को फिर से सामान्य करने को लेकर चार अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा के पुन प्रारंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई तो वहीं पाकिस्तान द्वारा समर्थित जिहादी आतंकवाद पर भारत ने चीन को दो-टूक पैगाम भी दे दिया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैद्धांतिक रणनीति करार दिया और यह वक्तव्य ऐसे वक्त में आया जबकि एससीओ द्वारा संयुक्त दस्तावेज में वैश्विक आतंकवाद से जुड़े गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। उल्लेखनीय है कि इन दिनों भारत और चीन की सरहद पर देपसांग और डेमचौक इलाकों में डिसएंगेजमेंट डील को आखिरी रूप प्रदान किया जा रहा है। चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात से पहले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी थी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत अपनी सरहद पर शांति और सुरक्षा स्थापित करना चाहता है किंतु अपने बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कदापि कोई समझौता नहीं करेगा। अब आगे देखना होगा कि विस्तारवादी फितरत का देश चीन चार पाइंट फार्मूले पर कितना अमल अंजाम देता है। वैश्विक पटल पर आज के बेहद मुश्किल दौर में भारत को अपनी विदेश नीति एवं कूटनीति पर क्या फिर से विचार नहीं करना चाहिए? वैश्विक सैन्य संघर्ष पर भारत की तटस्थ खामोशी भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए क्या घातक सिद्ध नहीं हो रही है? हमास बनाम इजरायल जंग में भारत का इजरायल के पक्ष में बयान आतंकवाद के खिलाफ भारतीय नीति का प्रतिफल था। गाजा पर हमास का शासन अवैध है, हमास एक आतंकी गुट है, इसलिए हमास के कृत्य का समर्थन संभव नहीं है। इसलिए जब भी संयुक्त राष्ट्र के पटल पर गाजा में युद्ध विराम करने के प्रस्ताव पेश किए गए, भारत ने मतदान का बॉयकॉट किया। अमेरिका की कयादत में नाटो सैन्य संगठन द्वारा वस्तुतः यूक्रेन को एक मोहरा बनाकर एक सैन्य युद्ध रूस पर थोप दिया गया। भारत द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध पर नाटो ताकत का विरोध ना करके केवल शांति का पैगाम और केवल फरमाया कि आज का दौर युद्ध का नहीं है वरन विकास का दौर है। परिणाम क्या रहा कि विश्व पटल पर सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस को भारत ने तकरीबन चीन के हाथों गंवा दिया है।

आतंकवाद पर चीन को भारत का सख्त संदेश

कूटनीति
अरविंद जयतिलक
वरिष्ठ स्तंभकार

संघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) सम्मेलन के जरिए भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जमकर हमला बोला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त बयान के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करके कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवाद के मसले पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने संयुक्त बयान के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मसौदा भारत की आतंकवाद-विरोधी नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण को कमजोर करता है। उन्होंने सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के जवाब में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आतंकवाद पर दोहरे मानदंड को खत्म करना बेहद जरूरी है और एससीओ जैसे मंच को ऐसी ताकतों की खुलेआम आलोचना करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि एससीओ के संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले को जगह नहीं दी गई जबकि इसी संयुक्त बयान में पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले को भरपूर तवज्जो दी मिली है।

चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत

मतलब साफ है कि यह कारस्तानी चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से हुआ है। ऐसे में अगर भारत ड्राफ्ट के मौजूदा स्वरुप पर ऐतराज जताता है तो यह उचित ही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मेजबान देश चीन और आतंकी देश पाकिस्तान दोनों को दो टूक सुना दिया कि जब तक संयुक्त बयान में आतंकवाद पर चिंता का जिक्र नहीं होगा, तब तक भारत को यह ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। गौर करें तो यह पहली बार नहीं है जब भारत ने एससीओ के मंच से आतंकवाद के मसले पर चीन-पाकिस्तान की कड़ी घेराबंदी की है। वर्ष 2024 में भी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ सम्मेलन में भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए मेजबान देश पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर तंज कसते हुए कहा था कि एक अच्छे पड़ोसी के धर्म निभाए जाने की कमी है तो खुद के भीतर झांकने की जरूरत है। तब विदेशमंत्री जयशंकर ने चीन की महत्वाकांक्षी 'वन बेल्ट वन रोड' पहल का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उसकी इजाजत के बिना किसी भी तरह का निर्माण उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है और चीन ऐसा ही कर रहा है।

आतंकवाद पर दोहरा आचरण

चीन को समझना होगा कि जब तक वह आतंकवादी देश पाकिस्तान को प्रश्रय देना बंद नहीं करेगा, तब तक वह आतंकवाद के मसले पर फजीहत झेलता रहेगा। रही बात एससीओ के भविष्य की तो यह काफी कुछ इस पर निर्भर रहेगा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय संप्रभुता के मसले पर

इस संगठन का रवैया क्या रहता है। वैसे हर बार की तरह इस बार भी सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई मसलों पर चर्चा हुई। लेकिन आतंकवाद पर जिम्मेदार देशों के दोहरे आचरण से उनका असली चेहरा सामने आ गया। इस सम्मेलन के जरिए भारत एक बार फिर जिम्मेदार वैश्विक भूमिका में दिखा जिसकी चतुर्दिक सराहना हो रही है। यह भारत के पक्ष में जाता है और यही कारण है कि उसकी भूमिका बढ़ रही है। अगर एससीओ की भूमिका सकारात्मक रहती है तो भारत की प्रभावी भूमिका से इस क्षेत्र में उभर रही आतंकी गतिविधियों, अंतरराष्ट्रीय खतरों, अवैध ड्रग कारोबार, जैसी चुनौतियों से निपटने और सदस्य देशों को गोलबंद करना आसान होगा। भारत की सदस्यता से पहले संगठन के सदस्य राष्ट्रों का कुल क्षेत्रफल 30 मिलियन 189 हजार वर्ग किमी और जनसंख्या तकरीबन 1.5 बिलियन था। अब भारत के जुड़ जाने से संगठन का क्षेत्रफल व जनसंख्या व्यापक हो गया है। आज की तारीख में यह संगठन विश्व की तकरीबन आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन बन चुका है। चूंकि इस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा यूरोपिय संघ, आसियान, कॉमनवेल्थ और इस्लामिक सहयोग संगठन से भी संबंध स्थापित किए हैं। इस नाते भारत की भूमिका और अधिक व्यापक हो जाती है। गौर करें तो अभी तक एससीओ पर चीन का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में संगठन में भारत की भूमिका और स्वीकार्यता दोनों बढ़ी है। इस कारण चीन के व्यापक प्रभाव में कमी और दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। संघाई सहयोग संगठन के इतिहास में जाएं तो अप्रैल, 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक-दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने को राजी हुए। तब इस संगठन को शंघाई फाइव कहा गया। जून 2001 में चीन, रूस और चार मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई संगठन सहयोग शुरू किया और धार्मिक चरमपंथ से निपटने के अलावा व्यापार व निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता किया। शंघाई फाइव के साथ उज्बेकिस्तान के आने के बाद इस समूह को शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। यह संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका कार्यालय बीजिंग में है और क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना ताशकंद में है। राज्य प्रमुखों की परिषद इस संगठन का सर्वोच्च निकाय है जिसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है। इसके अलावा शासन प्रमुखों की परिषद (एचजीसी) की वार्षिक बैठक होती है। शंघाई सहयोग संगठन में 2008 से डायलॉग पार्टनर यानी वार्ताकार सहयोग की व्यवस्था की गयी है। 2009 के शिखर सम्मेलन में सबसे पहले श्रीलंका और बेलारुस को डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया।

बेहतर संबंधों की प्रतिबद्धता

अफगानिस्तान, शंघाई सहयोग संगठन-अफगानिस्तान कांटेक्ट ग्रुप का हिस्सा है और इस ग्रुप की स्थापना 2005 में की गयी थी। इस संगठन की शिखर बैठकों में संयुक्त राष्ट्र, सीआईएस, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एवं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी सीएसटीओ के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। 2005 में कजाकिस्तान के आस्ताना में भारत के प्रतिनिधियों ने पहली बार शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लिया और सितंबर 2014 में एससीओ की सदस्यता के लिए आवेदन किया। भारत ने एससीओ की सदस्यता ग्रहण करने के बाद हर सम्मेलन में यूरेशियाई धरती के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहरायी। किंगदाओ सम्मेलन में भी भारत ने आतंकवाद पर सख्त संदेश देकर अपनी भावी-प्रभावी भूमिका स्पष्ट कर दी है।

चीनी कुटिलता का जवाब जरूरी था

एससीओ
विकेश कुमार बडोला
स्वतंत्र पत्रकार

शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में पारित संयुक्त वक्तव्य में आतंक संबंधी भारत की चिंताओं को स्थान न मिलने और पहलगाम आतंकी घटना का उल्लेख न होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किये। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के जो भी अंतिम एवं निर्णायक कार्यबिंदु निर्धारित किये गये थे, उनमें आतंक से पीड़ित भारत की व्यापक चिंताओं, वर्षों पुरानी समस्याओं और इस कारण शासन के सम्मुख उभरने वाली कठिनाइयों व चुनौतियों के बारे में कुछ भी वर्णित नहीं था।

स्वाभाविक था कि पहलगाम नरसंहार के ठीक दो माह बाद ही आयोजित इस सम्मेलन के अंतिम निष्कर्षजन्य प्रारूप में पहलगाम की घटना और इस आलोक में पाकिस्तानी आतंक को इंगित करने की दिशादृष्टि ही अदृश्य थी। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत ने किंचित उचित निर्णय लिया है जो एससीओ सम्मेलन की बैठक की निर्णायक नीतियों पर सहमति दर्शाने हेतु हस्ताक्षर नहीं किये। वास्तव में एससीओ का गठन 2001 में हुआ था। तब चीन की दक्षिण एशियाई और दक्षिणी यूरोपीय व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए चीन के नेतृत्व में ही संघाई सहयोग संगठन की नींव रखी गई थी। भारत और पाकिस्तान तो इस संगठन के साथ ठीक 16 वर्ष बाद 2017 में जुड़े थे और 2023 में ईरान ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की थी।

भारत की राह अभी सुगम नहीं

ऐसे में स्वाभाविक है कि आतंकवाद के संबंध में परस्पर संघर्षरत भारत व पाकिस्तान की हितों के अनुसार एससीओ की कार्यकारी नीतियां निर्धारित होने की राह अभी सुगम नहीं है। संगठन के साथ जुड़ने के वरिष्ठता क्रम में भारत व पाकिस्तान दोनों ही देश संगठन के शेष देशों से 16 वर्ष पीछे हैं। ऐसे में भारत के अनुरूप आतंकवाद संबंधी भारतीय चिंताओं को इस संस्था के सामूहिक नीतिगत उद्देश्यों में प्राथमिकता मिलना कठिन प्रतीत होता है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति सौभाग्य से अनुकूल है। एससीओ की स्थापना के 16 वर्ष तक जब भारत इसका सदस्य नहीं था, तब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में आतंकवाद इस संगठन की कार्यनीतियों, रणनीतियों और अन्य नीतियों के विषयों में सम्मिलित था ही नहीं। ऐसे में अब पहलगाम के आक्रोशजन्य वातावरण में एससीओ की, चीन के नेतृत्व में संचालित, चिर-परिचित व्यावसायिक नीतियों का अतिक्रमण कर आतंकवाद जैसा विषय प्राथमिकता के आधार पर भावी कार्यसूचियों में स्थान प्राप्त कर लेगा, ऐसा संभव तो नहीं लगता।

भारत को नहीं दी गई वरीयता

सम्मेलन में यह देखने को भी मिला है कि राजनाथ सिंह के आक्रोश व रुष्टता को चीन के नेतृत्व में किसी भी देश ने विशेष वरीयता नहीं दी और अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर सहमतिपूर्ण हस्ताक्षर न किए जाने के संबंध में कोई विशेष चिंता प्रकट नहीं की। उनके व्यवहार

से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें इससे कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि एससीओ की देर से सदस्यता प्राप्त करने वाला भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन तथा दक्षिणी यूरोप के प्रमुख देश रूस, इन दोनों के लिए शंघाई सहयोग संगठन में भारत की प्राथमिकताओं की उपेक्षा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना किंचित सुगम नहीं होगा।

चूंकि भारत ने आर्थिक आधार पर विश्व के चौथे सबसे बड़े देश होने का गौरव प्राप्त कर लिया है तथा रक्षा-सुरक्षा की दृष्टि से भी पहलगाम के प्रतिशोध में पाकिस्तान के विरुद्ध आरंभ किये ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने अपनी नवोन्नत युद्धक तकनीकों, प्रौद्योगिकियों, पराक्रम को भी विश्वस्तरीय होने के रूप में सिद्ध किया है, अतएव एससीओ के किसी भी देश के लिए भारत की प्राथमिकताओं की उपेक्षा कर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। एकल रूप में, चीन और पाकिस्तान को छोड़कर, एससीओ के शेष सदस्य देश भारत की आतंकवाद संबंधी चिंताओं और सामूहिक रूप में इसके उन्मूलन की प्राथमिकताओं पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहमति प्रदान करते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के उन्मूलन के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा युद्धक अभियान चलाकर पाकिस्तान के साथ अमेरिका और चीन की भी सामरिक हेकड़ी को लगाम लगाने में सफलता पाई है, तब एससीओ में चीन को अपनी पुरानी प्राथमिकताओं, हितों और रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही पाकिस्तान को छोड़कर एससीओ के शेष सदस्य देशों को भी संगठन की कार्यनीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों पर भारत की दिशादृष्टि के साथ सर्वथा एक नवदृष्टिकोण तैयार करना होगा, जिसके प्रभाव में भविष्य में एससीओ के सांगठनिक उद्देश्यों को भारत के मार्गदर्शन में एक उदार व समावेशी बोध के साथ प्राप्त किया जा सके। विश्व का कोई भी देश हो जब तक वह अन्य देश की किसी समस्या अथवा समस्याओं से स्वयं पीड़ित नहीं होता, तब तक वह पीड़ित देश की भांति समस्या के निदान हेतु विचारोत्तेजक व कार्यनीतिक दृष्टिबोध से संपन्न नहीं होता। आतंकवाद के संबंध में भारत ऐसा ही पीड़ित देश रहा है और एससीओ के शेष सदस्य देशों की चिंताएं कभी भी सामूहिक रूप में भारत के लिए समाधानमूलक नहीं बन सकी हैं।

शंघाई सहयोग संगठन संगठन का एक सदस्य देश पाकिस्तान, भारत के विरुद्ध आतंक का सिद्धदोषी प्रायोजक रहा है। इसी प्रकार दूसरा सदस्य देश ईरान भी मध्य पूर्व के क्षेत्र में अनेक आतंकी गुटों व समूहों को तैयार करवाकर क्षेत्रीय व राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कराने का दोषी रहा है। रूस और चीन जैसे सदस्य देशों ने पाकिस्तान और ईरान और इनके आतंकी समूहों को अस्त्र-शस्त्र बेचने की अपनी व्यापारिक नीति को हमेशा से संरक्षित किया है।

भारत का निर्णय स्वागत योग्य

भारत, जो एससीओ के सदस्य देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जिसने दक्षिण एशिया में पाकिस्तान द्वारा फैलाये गये आतंक में सर्वाधिक जनधन की हानि उठाई है। इसीलिए, यदि भारत एससीओ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है तो इसकी सामूहिक कार्ययोजनाओं में भारत की चिंताओं और आपत्तियों को वरीयता के क्रम में चिन्हित करते हुए उनके समयानुकूल समाधान की दिशा में सांगठनिक प्रयास होने अत्यंत आवश्यक हैं। इस हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आक्रोश, आपत्ति और संगठन के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह भारत की विदेश नीति के सशक्त व सुदृढ़ पक्ष का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस पर संकल्प के साथ डटे रहकर ही भारत अपने आर्थिक और सामरिक गौरव की रक्षा कर सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

सतत प्रयासों से हीटवेव से ग्रीनवेव की ओर बढ़ रहा है यूपी: मुख्यमंत्री

सीएम योगी ने जारी किया वृक्षारोपण महाभियान 2025 का लोगो - कहा, वन महोत्सव की अवधि में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को 'ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट' प्रदान किया जाए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में आगामी जुलाई माह में आयोजित होने जा रहे वन महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में तैयारियों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान को प्रदेशव्यापी जनांदोलन का रूप दिया जाए। वृक्षारोपण महाभियान-2025 का लोगो जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हम एक दिन में प्रदेश की कुल जनसंख्या से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 'एक पेड़ मां के नाम' थीम पर आधारित इस वृक्षारोपण महाअभियान में हमारा सामूहिक प्रयास प्रदेश को हीटवेव से ग्रीनवेव की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच प्रदेश में 204.92 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं और भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में ऐतिहासिक रूप से तीन लाख एकड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जो व्यापक जनसहभागिता से ही संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री ने इस वर्ष वन महोत्सव में एक अभिनव पहल की घोषणा करते हुए कहा कि वन महोत्सव की अवधि में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को 'ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट' प्रदान किया जाए, साथ ही शिशु के अभिभावकों को एक पौधा भी भेंट किया जाए। यह प्रयास पर्यावरणीय चेतना को व्यक्तिगत जीवन से जोड़ने का अभिनव प्रयोग होगा, जिसमें पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी उसी भावना से निभाई जाएगी जैसी किसी नवजात की। उन्होंने निर्देश दिया कि इस पहल को अभियान का भावनात्मक आधार बनाया जाए और इसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार वन महोत्सव में कुल 35 करोड़ पौधे रोपे जाने हैं, जो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी से भी अधिक होगी। उन्होंने इसे एक बड़ा पर्यावरणीय आयोजन बताते हुए कहा कि इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए और 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ' के संदेश को जन-जन तक पहुँचाया जाए। कार्ययोजना के संबंध में अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस बार वन विभाग द्वारा 12 करोड़ 60 लाख पौधे तथा अन्य विभागों द्वारा 22 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विभागवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जा चुका है और ग्रामीण व शहरी माइक्रोप्लान पर कार्य प्रगति पर है। समन्वय हेतु सभी विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। पौधों की आपूर्ति हेतु 1901 वन विभागीय पौधशालाओं, 146 उद्यान विभाग की पौधशालाओं, 55 रेशम विभाग की पौधशालाओं तथा 484 निजी पौधशालाओं में कुल 52 करोड़ 43 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की गई है, जिनमें औद्योगिक, इमारती, फलदार, चारा एवं शोभाकार जैसी विविध प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभागवार कार्ययोजना को अत्यंत गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत लाभान्वित सभी विद्यालयों में वृहद स्तर पर पौधरोपण कराया जाए। इसी प्रकार, सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सहजन सहित छायादार वृक्षों का रोपण आवश्यक रूप से किया जाए, ताकि इन संस्थानों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भविष्य में इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी औद्योगिक इकाइयों और परिसरों में सघन पौधरोपण कराया जाए, जिससे औद्योगिक वातावरण अधिक हरित और स्वस्थ बन सके। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निराश्रित गो-आश्रय स्थलों में नीम, पाकड़, पीपल जैसे वृक्षों का रोपण प्राथमिकता से किया जाए, जो गोवंश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष वन महोत्सव के अंतर्गत नदियों के पुनर्जीवन को भी केंद्र में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में किए गए संरक्षण प्रयासों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। इस बार वन महोत्सव के अंतर्गत नदियों के दोनों तटों पर वृक्षारोपण कराया जाए, जिससे जल गुणवत्ता और जैव विविधता दोनों को लाभ मिले। साथ ही आवश्यकतानुसार नदियों का चैनलाइजेशन भी किया जाए। उन्होंने कहा कि नदियों के कैचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी तालाबों के किनारों पर भी पौधरोपण सुनिश्चित हो और इन जल स्रोतों के संरक्षण व पुनर्जीवन का कार्य भी समानांतर रूप से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितना महत्वपूर्ण पौधारोपण है, उतनी ही गंभीरता से पौधों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक रोपे गए पौधे की जियो टैगिंग कराई जाए और उनकी फेंसिंग की समुचित व्यवस्था हो। जनता को पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाए, ताकि लगाए गए पौध वृक्ष बन सकें। उन्होंने इस अभियान को प्रदेश के हर व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी की सहभागिता से सफल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रपति की भव्य अगवानी करेगा गोरखपुर: सीएम

लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में शामिल होने आ रहीं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की भव्य अगवानी में कोई खामी न रहे, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे दिन भटहट के पिपरी स्थित आयुष विश्वविद्यालय का भ्रमण-निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने के बाद राष्ट्रपति सड़क मार्ग से गोरखनाथ मंदिर जाएंगी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर से आयुष विश्वविद्यालय तक राष्ट्रपति के रूट का भी जायजा लिया।

30 जून और एक जुलाई को राष्ट्रपति के दो दिवसीय दौरे के कार्यक्रमों को लेकर शुक्रवार दोपहर बाद से शनिवार पूर्वाह्न तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तैयारियों पर नजर बनाए रखी। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु 30 जून को एम्स गोरखपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होंगी। जबकि अगले दिन एक जुलाई को वह भटहट के पिपरी में बने राज्य के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण और सोनबरसा बालापार में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में अकादमिक भवन, ऑडिटोरियम, पंचकर्म केंद्र का लोकार्पण और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास करेंगी। आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने के बाद राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर जाएंगी। अब तक दिख रही तैयारियों के अनुसार गोरखपुर में राष्ट्रपति का सभी कार्यक्रम स्थलों पर सड़क मार्ग से जाएंगी। शुक्रवार को आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से गोरखनाथ मंदिर से आयुष विश्वविद्यालय तक की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रपति के रूट का निरीक्षण-परीक्षण करना था। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर से नकहा ओवरब्रिज, स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा, करीमनगर चौराहा, झुंगिया मोड़, मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए आयुष विश्वविद्यालय आए। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बार फिर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। आयुष विश्वविद्यालय में निरीक्षण के दौरान कुलपति, कई जनप्रतिनिधि, प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह आयुष विश्वविद्यालय जाने से पूर्व गोरखनाथ मंदिर के सभाकक्ष में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग पूरी जिम्मेदारी से राष्ट्रपति के कार्यक्रम को यादगार बनाने में जुट जाएं। बैठक में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्रीराम चौहान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, निवर्तमान अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

तीन नए कानूनों के तहत चिन्हित 457 मामलों में अपराधियों को दिलाई गई सजा

चार को मृत्युदंड, 425 को 20 वर्ष से कम कारावास और 19 अपराधियों को मिली 20 वर्ष से अधिक का करावास

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कनविक्शन के जरिये पिछले एक साल में 97 हजार से अधिक अपराधियों को सजा दिलायी जबकि पिछले करीब एक साल में तीन नये आपराधिक कानूनों के तहत चिन्हित कुल 457 मामलों में त्वरित सुनवाई के बाद दोषियों को सजा दिलाई गई है। इसकी हाल ही में बनारस में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफी सराहना की। अभियोजन एडीजी दीपेश जुनेजा ने बताया कि सीएम योगी के नेतृत्व में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत तीन नए आपराधिक कानूनों का सफल और प्रभावी अनुपालन प्रदेश को न केवल अपराधमुक्त बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल भी प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ नेतृत्व में चल रही यह पहल उत्तर प्रदेश को 'सुरक्षित और सशक्त राज्य' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि पिछले करीब एक साल में तीन नये आपराधिक कानूनों के तहत अब तक 457 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें 4 अपराधियों को मृत्युदंड (फांसी की सजा), 10 अपराधियों को आजीवन कारावास, 425 अपराधियों को 20 वर्ष से कम कारावास की सजा और 19 अपराधियों को 20 वर्ष से अधिक कारावास की सजा दिलायी गयी है। इन मामलों में अदालतों में अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मजबूत और तथ्यात्मक तर्क रखे। इसमें विशेष रूप से बीएनएसएस के प्रावधानों का सही उपयोग कर न्याय प्रक्रिया को सशक्त और तेज़ बनाया गया। इसके अलावा योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि गवाहों की सुरक्षा, साक्ष्य संग्रहण और अदालतों में समय पर उपस्थिति की सभी आवश्यकताएं पूरी हों। एडीजी ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 जुलाई 2024 से पूरे प्रदेश के 25,000 वादों की सुनवाई में प्रभावी डिजिटल दस्तावेज और गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिससे पुलिस और सरकारी गवाहों को बार-बार अदालत आने की आवश्यकता कम हुई और योगी सरकार को लगभग 25 करोड़ रुपये की बचत हुई। उन्होंने बताया कि बदांयू के बिल्सी थाने में दर्ज केस (394/2024) में आरोपी जाने आलम को बीएनएस की धाराओं में मृत्युदंड और 2 लाख 30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित कराया गया है। इसी तरह हाथरस के कोतवाली थाने में केस (26/2025) में आरोपी विकास और लालू पाल को मृत्युदंड के साथ 80 हजार रुपये का अर्थदंड दिलाया गया है। इसके अलावा कानपुर देहात के भीमगंज थाने में दर्ज केस (224/2024) में आरोपी दीपू को बीएनएस की धाराओं के तहत मृत्युदंड और 10 लाख रुपये के आर्थिक दंड से दंडित कराया गया है।

सपा मुखिया को ज्ञापन देकर पुश्तैनी जमीन को अधिग्रहण से बचाने का अनुरोध

लखनऊ (पीएनएस) समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन देकर तहसील मुगलसराय चंदौली के ग्राम ताहिरपुर मिल्कीपुर के निवासियों ने बंदरगाह के नाम पर गांवों की पुश्तैनी जमीन को अधिग्रहण से मुक्त रखने हेतु मार्मिक अनुरोध किया है। चंदौली के शिक्षक गांधीवादी लेखक विद्याधर ने बताया कि बंदरगाह एवं फ्रंट विलेज जैसी औद्योगिक परियोजना हेतु अधिग्रहण के नाम पर ताहिरपुर, मिल्कीपुर, रसूलागंज और छोटा मिर्जापुर की गरीब जनता को उजाड़ने की साजिशें हो रही है।

ज्ञापन पर ईशान मिल्की, नफीस अहमद, विनय मौर्य, वीरेन्द्र कुमार साहनी, आस मोहम्मद, अखिलेश सिंह, चंद्र प्रकाश मौर्य तथा अरविन्द कुमार साहनी के भी हस्ताक्षर है। उन्होंने श्री अखिलेश यादव से भेंटकर अपनी पीड़ा बताई।

ज्ञापन के अनुसार इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत आबादी माझी समाज की है जो पीढ़ियों से संगम के किनारे मछली पकड़ने, नांव चलाकर आजीविका कमाते हैं। विगत 20 मई को चंदौली जनपद के मुगलसराय उपजिलाधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के तीन बुलडोजर तथा भारी पुलिस फोर्स लेकर गांव पहुंचे जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बताया गया कि चंदौली के सांसद वीरेन्द्र सिंह, समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव, चंदौली जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव तथा प्रवक्ता मनोज काका ने भी जबरन अधिग्रहण का विरोध किया है। स्थानीय लोग आशंका और भय में जी रहे हैं। शिक्षक विद्याधर का कहना है कि वे अहिंसक प्रतिरोध करेंगे, मारेंगे नहीं पर मानेंगे भी नहीं। विद्याधर ने अपनी लिखी दो पुस्तकें अखिलेश यादव को भेंट की।

जरूरतमंदों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने नन्ही बिटिया के इलाज में मदद और आवास की व्यवस्था करने की गुहार के साथ बिटिया को गोद में लेकर बैठी महिला को भरोसा दिया कि बच्ची का अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी। महिला और उसके परिवार के लिए आवास की भी व्यवस्था कराई जाएगी। इसे लेकर सीएम योगी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं।

शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। ध्यान से बात सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना से मकान दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय संबल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। लोगों से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोद में बीमार बच्ची को लेकर कुर्सी पर बैठी महिला की समस्या सुन मुख्यमंत्री अत्यंत भावुक हो गए। महिला बच्ची के इलाज और आवास की समस्या लेकर आई थी। सीएम योगी ने उसे आश्वस्त किया कि दोनों समस्याओं इलाज और आवास की व्यवस्था, का समाधान सरकार कराएगी। इस दौरान वह मां की गोद में बैठी बच्ची को खूब दुलारते भी रहे। जनता दर्शन में कुछ अन्य लोग भी इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब दुलारा और आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट दिया।

कौशांबी में हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कौशांबी में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।उन्होंने दिवंगत के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस आपदा से घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रमुख बौद्ध तीर्थ व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा श्रावस्ती: जयवीर सिंह

लखनऊ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि श्रावस्ती जनपद स्थित महामंगोल बौद्ध विहार परिसर में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा अब रात में भी रोशनी में नजर आएगी। इस ऐतिहासिक स्थल पर फसाड लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत प्रतिमा और परिसर की भव्यता रात के समय और बढ़ जाएगी, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। पर्यटन विभाग का उद्देश्य है कि प्रदेश स्थित बौद्ध स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाया जाए, ताकि देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्राप्त हो सके। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि श्रावस्ती राज्य का प्राचीन शहर है। सनातन के साथ बौद्ध व जैन धर्म की जड़ें भी यहां से जुड़ी हैं। ऐसे में यह क्षेत्र पर्यटन व धार्मिक यात्रा के लिए आगंतुकों को रास आता है। देश ही नहीं दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी हर साल यहां भ्रमण के लिए आते हैं। पर्यटक सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण से आगंतुकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।झील, नदी, पहाड़ व जंगल से घिरा श्रावस्ती जिला अध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रमुख कर्मस्थलियों में से एक है, जहां उन्होंने जीवन के सबसे अधिक वर्षावास व्यतीत किए। दुनियाभर से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। अब फसाड लाइटिंग के जरिए इस स्थल की भव्यता को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस पूरे परिसर में रोशनी की ऐसी व्यवस्था की जाएगी, कि वह 360 डिग्री से देखने पर समान रूप से भव्य नजर आएगा। विशेष त्योहारों और अवसरों पर थीम आध्धारित बहु-स्तरीय प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में श्रवस्ती में कुल 1,27,222 पर्यटक आए थे। इनमें 1,20,540 घरेलू पर्यटक जबकि 6,682 विदेशी आगंतुक थे। विभाग को उम्मीद है कि उनके प्रयासों का सकारात्मक प्रतिफल सामने आएगा। श्रावस्ती आने वाले जेतवन महाविहार, अंगुलिमाल गुफा, आनंद बोधि वृक्ष सहित महात्मा बुद्ध से जुड़े अन्य स्थलों की सैर करते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सरकार श्रावस्ती को एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग का सतत प्रयास है कि श्रावस्ती की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को वैश्विक पहचान दिलाई जाए। इस दिशा में फसाड लाइटिंग की समुचित व्यवस्था की जा रही है, जिससे न केवल श्रद्धालु बल्कि आम पर्यटक भी आकर्षित होंगे। फसाड लाइटिंग की समुचित व्यवस्था न केवल श्रद्धालुओं बल्कि आम पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। यह पहल पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को को भी नई गत्ति देने का कार्य करेगी।

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे सामाजिक चेतना के केंद्र

लखनऊ।प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा को एक नई दिशा देने की पहल करते हुए प्रदेश के पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम देश के महान महापुरुषों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के नाम पर रखे हैं। यह निर्णय केवल एक औपचारिक नामकरण नहीं, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक उद्देश्य से प्रेरित बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग शिक्षा को सिर्फ तकनीकी दक्षता तक सीमित न रखते हुए छात्रों को सामाजिक चेतना, न्याय, समरसता और प्रेरणा से भी जोड़ना है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति के बाद अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने इस पहल को 'नई पीढ़ी को मूल्यों से जोड़ने वाली ऐतिहासिक पहल' बताते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को तकनीकी विशेषज्ञता के साथ सामाजिक नेतृत्व की भी प्रेरणा मिलेगी।

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रतापगढ़ का नाम अब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रतापगढ़, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मीरजापुर का नाम अब सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मीरजापुर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का नाम भारत रत्न सरदार बल्लभभाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का नाम अब मां पाटेश्वरी देवी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनपुरी का नाम बदलकर लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनपुरी कर दिया गया है।प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नामकरण केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इन नामों से छात्रों को प्रेरणा प्राप्त होगी और वे इन महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतार सकेंगे। इन नामों से कॉलेजों की पहचान न केवल तकनीकी शिक्षा से जुड़ी रहेगी, बल्कि छात्रों में सामाजिक चेतना, आत्मबल और राष्ट्र निर्माण की भावना भी विकसित होगी। आने वाले समय में ये संस्थान उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी विशेषज्ञता के साथ सामाजिक नेतृत्व के लिए भी तैयार करेंगे।

भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में चल रहा जमीनों का गोरखधंधा: अखिलेश

लखनऊ (पीएनएस)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में जमीनों का गोरखधंध चल रहा है। जहां भी जमीन दिख जाती है भाजपा उसे हड़पने और कब्जा करने के लिए सक्रिय हो जाती है। भाजपा सरकार में गोरखपुर में विरासत गलियारा के नाम पर व्यापारियों के मकान और दुकान ढहा कर जमीन लूटी जा रही है। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। गोरखपुर में व्यापारियो की समस्याओं की सुनने और उनकी आवाज उठाने गये नेता विरोधी दल विधानसभा माता प्रसाद पाण्डेय और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव को भाजपा के विधायक, कार्यकर्ताओं ने रोका, उन पर हमला किया। रोकने के लिए रास्ते में बुलडोजर लगा दिया। भाजपा सरकार लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को रोका जाना उन पर हमला होना निन्दनीय है। यह सब कभी हिटलर के जमाने में होता था। भाजपा सरकार में बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में दोनों नेता विरोधी दल के साथ हुई घटना की जितनी निंदा की जाय कम है। इस घटना में नेता विरोधी दल गोरखपुर के अधिकारियों जिलाधिकारी और एसएसपी के खिलाफ लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे और दोनों सदनों में नोटिस देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर में सत्ता के संरक्षण में जमीनों का गोरखधंधा चल रहा है। अगर गोरखपुर के लोगों ने मुंह खोल दिया, राज बता दिया तो वहां विरासत की जगह वहां हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। यादव ने कहा कि सरकार गोरखपुर में व्यापारियों की जमीनों का बाजार मूल्य दें। गोरखपुर में विरासत गलियारा में जमीन, मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए। वहां मार्केट रेट बहुत ज्यादा है। शासन-प्रशासन पुलिस को आगे कर व्यापारियों और जो लोग रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति करा रहे हैं। मुआवजा ज्यादा न देना पड़े इसके लिए सरकार डर दिखाकर, सहमति कराने के लिए दबाव बना रही है। यादव ने कहा कि जब अपनी जमीन का मामला था तब अधिकतम संभव मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने के नाम पर वाहवाही लूटी गयी। सच्चाई यह है कि कारीडोर के नाम पर भाजपाई लूटतंत्र सक्रिय है जो तरह-तरह के बहाने करके लोगों की जमीन औने-पौने दाम पर खरीद लेते हैं और बाद में ऊंचे दाम पर बेंच देते हैं। स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है। यही वजह है कि भाजपा अयोध्या और प्रयागराज में हारी है। वाराणसी में हारते-हारते बची है। अगला नम्बर गोरखपुर और मथुरा का है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में जमीनों का गोरखधंधा गोरखपुर, के अलावा अयोध्या, लखनऊ समेत प्रदेश के हर जिले में चल रहा है। भाजपा सरकार विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सिर्फ योजनाएं बनाकर अपने लोगों को ठेका दे रही है और किसानों, व्यापारियों की जमीनों की लूट कर रही है। जब किसानों, व्यापारियों की जमीनें खरीदना होता हो तो यह सरकार, सस्ती कीमत पर जबरन छीन लेती है। जब जमीने भाजपा नेताओं के हाथ में आ जाती है तो सर्किल रेट बढ़ा देती है। अयोध्या में यही काम हुआ और अन्य जिलों में भी ऐसा ही हो रहा है। इस सरकार में जमीनों का गोरखधंधा लखनऊ में बैठकर खूब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के अपने सलाहकार को जमीनों के गोरखधंधा के कारण इस्तीफा देना पड़ा। पीछे-पीछे न जाने किससे-किससे हाथ मिलाए थे। जिनसे हाथ मिलाये थे वे देश छोड़कर जा चुके है। केवल वही नहीं सरकार में और भी छिपे लोग है जो आपने गांव के आस पास की जमीनों को हड़प रहे हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

दैनिक जागरण

लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान है

बेकार की बहस

इसमें हर्ज नहीं कि संविधान पर फिर बहस चल निकली, लेकिन यह ठीक नहीं कि आपातकाल के समय जब लगभग पूरा विपक्ष जेल में था, तब संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने पर घिसी-पिटी बहस ही हो रही है। यह बहस इसलिए हो रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी की ओर से 1975 में आपातकाल थोपे जाने और लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दमनचक्र चलाए जाने के घोर अलोकतांत्रिक फैसले के 50 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर जो कुछ कहा और लिखा गया, वह कांग्रेस को रास नहीं आया। उसने खुले-छिपे शब्दों में यह जताने में संकोच नहीं किया कि उसे इंदिरा गांधी के लोकतंत्र को कलंकित करने वाले फैसले की निंदा-आलोचना पसंद नहीं। देश जानना चाहेगा कि क्यों नहीं पसंद? देश यह भी जानना चाहेगा कि क्या जब संविधान में पंथनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे, तब भारत पंथनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों का वाहक नहीं था। भारत तो यूरोप में सेक्युलर शब्द के प्रचलन में आने के सदियों पहले सर्वपंथ समभाव अर्थात पंथनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का हामी था।

यह विचित्र है कि जिसकी जरूरत संविधान निर्माताओं और यहां तक कि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नहीं समझी, उसकी इंदिरा गांधी ने क्यों समझी? क्या यह सत्य नहीं कि अपने निर्वाचन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रतिकूल फैसले के चलते प्रधानमंत्री पद का त्याग करने से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपकर संविधान की प्रस्तावना बदली? यह कहना बौद्धिक बेईमानी है कि संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट लिखे जाने से भारत पंथनिरपेक्ष और समाजवादी हो गया। सेक्युलरिज्म का सही पर्यायवाची पंथनिरपेक्षता है, लेकिन प्रचलन में धर्मनिरपेक्षता है। आखिर कोई देश और कम से कम भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्म का अर्थ है व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का कर्तव्य। क्या भारत को इससे निरपेक्ष हो जाना चाहिए? क्या यह किसी और विशेष रूप से कांग्रेस से यह छिपा है कि समाजवाद ने देश का कैसा बेड़ा गर्क किया है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आज के अनेक कथित समाजवादी नेता कितने पाखंडी और परिवारवादी हैं। आज तो समाजवाद घनघोर जातिवाद का भी पर्याय बन गया है। अच्छा हो कि देश बेकार की और समय जाया करने वाली बहस से बचे और ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श हो, जिससे देश की जनता को कोई दिशा मिले और उसका भला हो। कांग्रेस को यह भी याद रहे तो अच्छा कि वह जिन भीमराव आंबेडकर की हितैषी बन गई है, वे संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। वे तो विभाजनकारी और कश्मीर में अलगाव पैदा करने वाले अनुच्छेद 370 के भी विरोधी थे।

अन्य जिले भी आएं आगे

केंद्र सरकार और नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा में झारखंड के चतरा जिले को अग्रणी स्थान दिया है। 112 आकांक्षी जिलों की सूची में चतरा ने प्रथम स्थान लाकर न सिर्फ राज्य, बल्कि देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कभी इसकी पहचान थी। आज इस जिले में प्रशासन, स्थानीय निकाय, जन प्रतिनिधि और एजेंसियों ने मिलकर विकास की नई कहानी लिखी है। यहां फ्लैगशिप योजनाओं के साथ-साथ नवाचार को मिलाकर सतत विकास का प्रयोग का रंग लाया है। राज्य के लगभग सभी जिलों की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कुछ जिलों को खनन और उद्योगों से रोजगार के अवसर मिलते हैं। चतरा इन दोनों का समन्वय है। यहां कोल खनन परियोजनाएं भी हैं और नदियों से सिंचित कृषि भूमि भी। ऐसे में राज्य के दूसरे जिले भी चतरा माडल को अपना कर विकास की नई कहानी रच सकते हैं। नीति आयोग ने इसी तरह गढ़वा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। गढ़वा जैसे सुदूर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार ने ड्रापआउट जैसी समस्या पर नियंत्रण पाया है। यह कुशल प्रबंधन और मजबूत नेतृत्व के साथ सामाजिक सरोकार का बेहतरीन उदाहरण है। चतरा और गढ़वा की उपलब्धि पूरे राज्य के लिए मानक है। अन्य जिसे भी पहल कर इसमें आगे बढ़ें ताकि पिछड़े प्रांतों की सूची से झारखंड बाहर आए।

> आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में चतरा के अव्वल आने से झारखंड में विकास का नया माडल आया सामने

जस्टिस यशवंत वर्मा हाजिर हों!

अरविंद जैन

कूड़े को कालीन तले छिपा कर, न्यायिक संस्थाओं की छवि को कब तक विश्वसनीय रखा जा सकता है?

अवधेश राजपूत

वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग (1788-1795) की बहस में सांसद और वकील एडमंड बर्क ने कहा था- सत्य, न्याय और इंसाफ के लिए कानून के मार्ग पर जो राष्ट्र चलता है, वही महान है। बेहद गंभीर आरोपों और पर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद ब्रिटिश संसद ने हेस्टिंग्स को बेकसूर माना और कंपनी ने उन्हें 4,000 पौंड सालाना पेंशन भी दी। शायद सत्ता अपने लाडले सपूतों के बचाव में ऐसे ही न्याय के नाटक-नौटंकी करती रही है। 14 मार्च, 2025 को दिल्ली के एक बंगले के स्टोर रूम में आधी रात आग लगने से धुंआ उठने लगा। आग में जलते नोटों के ताप से कांच की बोतलें टूटने और शराब बहने से आग और भड़क उठी। आग में शराब ने घी से भी अधिक खतरनाक काम किया। बंगला दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को आवंटित था। दमकल, पुलिस आई, आग बुझाई, वीडियो बनाई और जले-अधजले या बचे करोड़ों रुपये और शराब की बोतलों को यूं का यूं छोड़ चली गई। कोई पंचनामा (एफआइआर) या बरामदगी नहीं की गई। घटना के समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी भोपाल में थे। अगले दिन आए तो घटनास्थल पर शेष-अशेष कुछ न था। विश्वासपात्र सचिव और अन्य सेवकों ने सब साफ-सफाई कर दी। मीडिया में हफ्ते भर तक कोई खबर नहीं। कैश कांड की जानकारी गोपनीयता और संवेदनशीलता के घूंघट में उच्चाधिकारियों, न्यायाधीशों के बीच घूमती रही। अदालत के गलियारों में धुंआ, धूल और धुंध...खामोशी का षड्यंत्र गहराता रहा, अटकलों का बाजार गर्माता गया। कुछ पत्रकारों ने पर्दा हटाना शुरू किया तो पहले जज साहब को न्यायिक कार्य न करने के निर्देश और फिर इलाहाबाद वापस जाने के आदेश जारी हुए। कैश कांड की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाने की सिफारिश करके गेंद संसद के पाले में लुढ़का दी और खुद सेवानिवृत्त हो गए। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अधिकांश दस्तावेज (जांच रिपोर्ट के अलावा) सार्वजनिक करने पड़े। न जाने कैसे जांच रिपोर्ट बाद में लीक हो गई। जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनु शिवरमन शामिल थे।

फिलहाल महाभियोग की पेचीदा प्रक्रिया चलाने या न चलाने के मुद्दे पर वाद-विवाद, सहमति-असहमति की राजनीति के इर्द-गिर्द ही वरिष्ठ वकीलों द्वारा सार्वजनिक रूप से कानूनी तर्क-वितर्क रचे जा रहे हैं। कानून मंत्री सभी दलों के बीच आम सहमति बनाने में प्रयासरत हैं। एक ओर न्यायपालिका में आमजन की आस्था बचाए रखने के लिए और संसद को इस मामले पर बहस करने, वोट देने और अभियोग सिद्ध करने की दुःसाध्य जटिलता से बचाने के लिए यह सलाह दी जा रही कि जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे दें, ताकि न्यायपालिका और संसद का धर्मसंकट से बचाव हो सके। दूसरी ओर उपलब्ध तथ्यों पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सांसदों में वकील और वकीलों में सांसद के रूप में जाने-पहचाने चेहरे रोज नया रास्ता तलाश-तराश रहे हैं।

कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं, पर यथार्थ यह भी है कि न्याय मंदिरों के विशाल प्रांगण में भी भ्रष्टाचार के विष-वृक्ष अप्रत्याशित रूप से फलते-फूलते रहे हैं। यौन शोषण से लेकर आर्थिक धांधली तक के आरोपों में अकसर लीपापोती होती रही और अधिक हुआ तो न्यायाधीशों से इस्तीफा लेकर बाइज्जत मुक्त कर दिया गया। विचारणीय है कि कूड़े को कालीन तले छिपा कर न्यायिक संस्थाओं की छवि को कब तक विश्वसनीय रखा जा सकता है? इस्तीफा के बारे में सोचते ही न्यायाधीश शामित मुखर्जी सामने आ खड़े होते हैं, जिन पर आपराधिक मामला अभी तक लंबित है। इससे इन्कार नहीं कि शायद कोई न कोई दल जस्टिस वर्मा को भी वैसे ही बचा ले, जैसे कांग्रेस ने वाकआउट करके जस्टिस रामास्वामी को बचाया था। कांग्रेस जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग कर रही है। राजनीति के अपराधीकरण के मौजूदा दौर में अनुमान लगाना मुश्किल है कि अंतिम क्षणों में क्या फैसला लिया या नहीं लिया जाएगा।

संदेह और सवालों का घेरा बढ़ रहा है। यदि कथित करोड़ों रुपये वर्मा जी के नहीं थे तो किसके थे? अगर यह उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र है तो ऐसा कौन है, जो रकम और शराब स्टोर रूम में प्लांट कर-करा सकता है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? खुद न्यायाधीश महोदय ने कोई उचित कार्यवाही या शिकायत क्यों नहीं की? आज तक अग्निकांड में जला-अधजला एक भी नोट बरामद नहीं हुआ। कानून और न्याय व्यवस्था में आस्था बचाए रखने के लिए जांच तो करनी-करानी ही पड़ती है। इसे 'सत्यमेव जयते' कहो या 'यतो धर्मा स्ततो जय'!

जस्टिस वर्मा के विरुद्ध संसद के जुलाई सत्र में महाभियोग आ सकता है, पर इसमें अनेक 'किंतु-परंतु' हैं। महाभियोग के लिए राज्यसभा के 50 या लोकसभा के सौ सांसदों का हस्ताक्षरित प्रस्ताव अनिवार्य है। जजे'ज इंक्वायरी एक्ट, 1968 की धारा-3 के अनुसार संसदीय समिति को स्वतंत्र जांच करनी होगी, तीन न्यायाधीशों की जांच रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में मौजूद सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए। रामास्वामी के महाभियोग के समय उनका बचाव नेता एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (प्रधान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने किया था। न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच वर्चस्व के शीतयुद्ध में विवेकहीन बिखराव घटता-बढ़ता रहता है। देखना है लोकतंत्र के प्रहरी राष्ट्रहित में क्या निर्णय लेते हैं। 'रिमोट कंट्रोल' से संचालित आवारा पूंजी के अभेद्य चक्रव्यूह में अनेक यशवंतों की भूमिका रहती है। यदि वक्त रहते न्याय एवं कानून व्यवस्था की देखभाल नहीं की गई तो स्थितियां बेकाबू और भयावह हो सकती हैं।

(लेखक सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं)

response@jagran.com

सिद्धांत वही जो दूसरों के काम आएं

हास्य-व्यंग्य

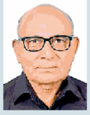

सूर्यकुमार पांडेय

आदमी जीवन में तमाम सिद्धांत बनाता है, लेकिन उन पर तभी तक चल पाता है, जब तक मामला गैरों से जुड़ा हो

उस रोज मंत्री जी के बंगले पर जाना पड़ा। मेरे सगे भाई की नौकरी का प्रसंग था। वह बोला, 'भाई साहब, आप कह देंगे, तो हो सकता है, काम बन जाए!' मैं ठहरा आदर्शवादी। मुझे जीवन भर सोर्स-सिफारिश जैसी चीजों से परहेज रहा। मगर सगे भाई का काम था इसलिए ना करते नहीं बना। मैंने भी सोचा, जिंदगी में कई काम ऐसे भी करने पड़ते हैं, जिनके लिए आत्मा गवारा नहीं करता। आदमी तमाम सिद्धांत बनाता है, उन पर चलने की कोशिशें भी करता है, पर यह तभी तक संभव हो पाता है, जब गैरों का मामला हो। अपने लिए सिद्धांतों से विचलन का चलन पाया जाता है।

मेरे एक मित्र थे। निहायत ईमानदार। सरकारी नौकरी में थे, तब भी ईमानदार बने रहे। उलटे जिसका काम करते, उसी को चाय पिलाते। उन्होंने नौकरी में ऊपर का एक पैसा नहीं लिया। जो कमाया, वेतन से कमाया। तब एक वक्त ऐसा भी आया, जब अपने लड़के की नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत देने में उन्होंने एक मिनट की देरी नहीं की। ईमानदारी की सारी कमाई घूस में परिवर्तित हो गई। सगे खून के आगे सिद्धांतों का खून करने में उन्हें कतई कष्ट का अनुभव नहीं हुआ था। मैंने पूछा, तो बोले, 'यार, क्या करता? बेटे की नौकरी का सवाल था। बड़ी मुश्किलों से जुगाड़ लगा था।' जब ऐसी ही परिस्थिति मेरे सामने आई तो मैंने अपने उस मित्र का पुण्य-स्मरण किया। बड़ा बल मिला। जब मेरा वह मित्र अपने लड़के की नौकरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की ईमानदारी की कमाई को तिलांजलि दे सकता है, तो क्या मैं अपने सगे भाई के लिए मंत्री जी के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता था? मैंने स्वयं को समझायाः रे मनमूरख, ये सिद्धांत-विद्धांत दूसरों के लिए हुआ करते हैं।

अगर कोई अपने काम के लिए आपके पास आए और आप नहीं करना चाहते हैं, तो उससे कहिए-'भाई, अपना तो उसूल है, जो भी करेंगे, नियमानुसार करेंगे। माफ कीजिएगा, हम दुनिया त्याग सकते हैं, पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकते।' फिर वह भी ऊपर से आपको परम आदर्शवादी और भीतर से महा कमीना समझता हुआ कहेगा- 'छोड़िए भी। आपका सिद्धांत आड़े आता है, तो कोई बात नहीं। काम तो किसी और तरीके से भी कराया जा सकता है, लेकिन आप जैसा सिद्धांतवादी आज के जमाने में चिराग लेकर ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेगा।' वह आपके पैर छुएगा और भीतर-ही-भीतर दोबारा आपके दरवाजे का रुख न करने की कसम खाता हुआ विदा लेगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा, जब आपका कोई काम उससे पड़ेगा। आप उससे मिलेंगे तो वह मुस्कुराएगा। आप कहेंगे-'यार, नियम से तो नहीं हो सकता, पर कैसे भी कर-करा दो। करीब के रिश्तेदार का केस न होता तो मैं कहने ही न आता। अपना सिद्धांत जो ठहरा, पर क्या करूं? इतना दबाव है कि दुनियादारी में आना ही पड़ा।' तब वह दुनियादार आदमी आपका काम सबसे पहले करेगा और कहेगा, 'भाई साहब, देखिए, दुनिया ऐसे ही चलती है।'

तो मैंने भी अपने दिल को मजबूत किया और मंत्री जी के बंगले पर पहुंच गया। मंत्री जी ने मुझे पहचान लिया, पर जब मैंने आने का प्रयोजन बताया तो गंभीर हो गए। बोले, 'मैं जानता हूं, आप सिद्धांतवादी हैं। कभी किसी की सिफारिश लेकर नहीं आए। आज एक काम लेकर आए हैं, तो करना भी चाहता हूं। मगर अपना भी एक सिद्धांत है। मैं अपने सगे-संबंधियों के अलावा किसी का काम नहीं करता।' मुझे तत्काल बुरा लगा, लेकिन बाद में यह सोचकर अच्छा भी लगा कि वस्तुतः इस दुनिया में सबको अपने-अपने सिद्धांतों पर अटल रहना चाहिए।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य जीडीपी के अनुपात में रक्षा खर्च

(आंकड़े 2023 के)

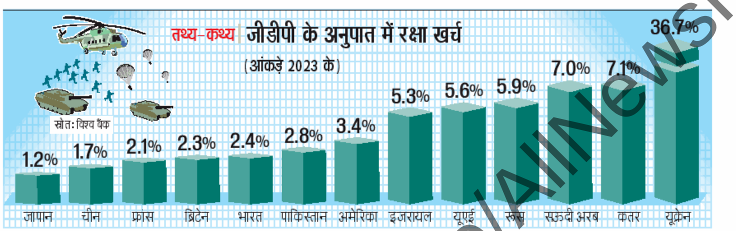

ऊर्जा

अपराध बोध

अपराध बोध एक संवेदनात्मक मनोभाव है, जो अपराधी के मन में ग्लानि रूप में उत्पन्न होकर अपराध को रोकने का काम करता है। इसीलिए अपराध के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। अपराध बोध का उत्कृष्टतम रूप वह है, जो अपराध से पहले ही मन में उत्पन्न होकर अपराध भाव को समाप्त कर देता है। संवेदना से भी इसका गहरा संबंध है। संवेदनशील व्यक्तियों में अपराध बोध की मात्रा अधिक होती है। अतः उनमें अपराध की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। अपराध की सर्वाधिक प्रवृत्ति संवेदनशून्य लोगों में होती है, क्योंकि उन्हें अपराध की पीड़ा का अहसास ही नहीं होता। आज अपराधों में हो रही बढ़ोतरी संवेदनहीनता और अपराध बोध में कमी का परिणाम है, जो गहरी चिंता का विषय है।

अपराध बोध एक स्वस्थ मानवीय गुण है, जो आत्म सुधार की प्रक्रिया को बढ़ाकर आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाता है। अतः सभी में इसका होना आवश्यक है। किंतु यही सामान्य से अधिक होने पर विकार भी बन जाता है। फिर अवसाद को जन्म देकर आत्महत्या जैसे घृणित अपराध का कारण बनता है। क्रोध अपराध बोध में बड़ा बाधक है, जो कई बार संवेदनशील व्यक्ति से भी न चाहते हुए अपराध करा देता है। क्रोध शांत होने पर बढ़े हुए अपराध बोध से वही व्यक्ति स्वयं का अनिष्ट कर लेता है। यह अपराध बोध का घृणित रूप है, जो नहीं होना चाहिए। अतः क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है।

अपराध बोध वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है, जो मानव को महान बनाती है। इससे समाज को अपराध मुक्त किया जा सकता है। धर्म में निष्ठा एवं अधर्म का भय अपराध बोध जागृत करने में सहायक हैं। बुद्ध, महावीर, गांधी आदि महापुरुषों ने सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, ममता आदि जिन मानवता के पोषक तत्वों की धर्म के रूप में प्रतिष्ठापना की है, उनके आने से अपराध बोध स्वयं ही जागृत होता है।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

खतरे में दुनिया के ग्लेशियर

मुकुल व्यास

> ग्लेशियर के पीछे हटने से न केवल समुद्र के स्तर पर असर पड़ता है, बल्कि ताजे पानी की उपलब्धता पर भी प्रभाव पड़ता है

ग्लेशियर हमारी बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति करने वाले ये जल स्रोत इस समय भारी दबाव में हैं। यदि वैश्विक तापमान अपने वर्तमान पथ पर जारी रहता है, तो दुनिया के 75 प्रतिशत ग्लेशियर गायब हो सकते हैं। ग्लेशियरों के लुप्त होने का सिलसिला जारी रहेगा, भले ही आगे गर्मी और न बढ़े। एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि आज के स्तर पर तापमान को स्थिर करने से भी ग्लेशियरों को बहुत नुकसान होगा। अध्ययन का निष्कर्ष है कि यदि दुनिया का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, जो वर्तमान जलवायु नीतियों के अनुरूप है, तो भी दुनिया के ग्लेशियरों की बर्फ का केवल एक-चौथाई हिस्सा ही बचेगा, लेकिन इस अध्ययन में एक आशा की एक किरण भी दिखाई देती है। यदि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है, जो पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य है, तो तमाम ग्लेशियरों की बर्फ का लगभग आधा हिस्सा अब भी बचाया जा सकता है।

दस देशों के 21 विज्ञानियों ने दुनिया के दो लाख से अधिक ग्लेशियरों के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए आठ स्वतंत्र ग्लेशियर माडलों का उपयोग किया। इस अध्ययन में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर शामिल नहीं किए गए। जर्मनी के ब्रेमेन विश्वविद्यालय के विज्ञानी बेन मार्जियन ने कहा है कि अध्ययन के परिणाम इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि वर्तमान जलवायु नीतियां भविष्य में ग्लेशियरों के आकार में निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। विज्ञानियों ने हर अतिरिक्त 0.1 डिग्री गर्मी पर वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान में दो प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है। अध्ययन में शामिल एक अन्य विज्ञानी डा. हैरी जेकोलारी कहते हैं कि डिग्री का हर अंश मायने रखता है। आज हम जो विकल्प चुनते हैं, वे सदियों तक प्रतिध्वनित होंगे। अध्ययन से जुड़ी विज्ञानी डा. लिलियन शूस्टर का कहना है कि ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के अच्छे संकेतक हैं। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ग्लेशियरों के पीछे हटने से जलवायु कैसे बदल रही है।

ग्लेशियरों की स्थिति वास्तव में आज पहाड़ों में दिखाई देने वाली स्थिति से कहीं ज्यादा खराब है। ग्लेशियर के पीछे हटने से न केवल समुद्र के स्तर पर असर पड़ता है, बल्कि ताजे पानी की उपलब्धता पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ग्लेशियर से संबंधित खतरों का जोखिम बढ़ता है और ग्लेशियर आधारित पर्यटन प्रभावित होता है। ये परिवर्तन जो पहले से ही कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं, वैश्विक जलवायु नीति के महत्व को रेखांकित करते हैं। यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष (2025) में एक महत्वपूर्ण योगदान है और दुनिया के ग्लेशियरों को बचाने के लिए वैश्विक जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

एक संकेत यह भी

कुछ राज्यों में भाजपा ने संगठन चुनाव की फिर से शुरुआत की है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो गई है कि शायद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत दूर नहीं है। हालांकि कुछ बड़े राज्यों में इस संबंध में घोषणा नहीं होने से उनमें थोड़ा असमंजस भी था, लेकिन इसी बीच फिर से उनका उत्साह बढ़ा है। और इसका कारण यह है कि हाल में भाजपा में लगातार सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने वाले जेपी नड्डा ने मुख्यालय के कुछ कर्मचारियों से मुलाकात की। इसे परिवर्तन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी के अध्यक्ष के कार्यालय को सुचारु रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों का आभार जताया। वैसे पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कब होगा? यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। चर्चा है कि भाजपा संसद के मानसून सत्र शुरू के पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर सकती है।

शाह की प्रशंसा से बढ़ी रेटिंग

कर्नाटक के दावनगिरी से कांग्रेस की सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन की रेटिंग आजकल प्रदेश के किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसके कारण हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बताया जाता है कि हाल ही में अपने कर्नाटक दौरे के वक्त जहां उन्होंने पार्टी नेताओं में एकता की कमी पर नाराजगी जताई, वहीं प्रभा मल्लिकार्जुन की प्रशंसा कर दी। यह खबर तेजी से फैली और कई स्थानीय अखबारों में प्रसारित हो गई। अमित शाह की प्रशंसा से जहां खुद प्रभा मल्लिकार्जुन गदगद नजर आ रही हैं और अमित शाह को धन्यवाद बोलते हुए यह सफाई दे रही हैं कि वह कांग्रेस में ही रहने वाली हैं, वहीं कांग्रेस के अंदर नेताओं में यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रभा मल्लिकार्जुन की प्रगति को रोकना अब संभव नहीं होगा। हालांकि उनके पति पहले से ही सिद्दरमैया की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन महिला चेहरे के रूप में प्रभा मल्लिकार्जुन की दमक बढ़ने वाली है।

आयोग का दांव

एक कहावत है कि सौ सुनार की, एक लुहार की। चुनाव आयोग पर इन दिनों यह पूरी तरह फिट बैठ रही है। खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को घेरने के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए थे, उससे निपटने के लिए आयोग ने भी फैसला लिया है कि वह मतदाता सूची में एक भी गड़बड़ी को नहीं छोड़ेगा। इसके लिए वह मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन कराएगा। चुनाव आयोग ने बिहार से इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है। साथ ही संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, वहां भी मतदाता सूची का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस जैसे दल दोहरे ईपिक एवं मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग को सड़क से संसद तक घेरने में जुटे थे, उनकी आयोग के इस फैसले के बाद नींद उड़ी हुई है। वे आयोग के इस फैसले का विरोध करते दिख रहे हैं।

बंगाल का असमंजस

पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं ने तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ गिरा दिया है, लेकिन इसका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा इसे लेकर विश्लेषकों में भी असमंजस है और वहां के मुख्य विपक्षी दल भाजपा में भी। दरअसल देश में अब यह अकेला राज्य है, जहां चुनाव में हिंसा होती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर ही निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, लेकिन नेताओं का मानना है कि राष्ट्रपति शासन का उल्टा असर भी हो सकता है। लोगों में जिस ममता सरकार के खिलाफ अभी गुस्सा है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद वह कहीं सहानुभूति में न बदल जाए।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****